

9 दिल्‍ली, **5 फरवरी, 2026 गुरुवार**
ईशा‍वारचमिंदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।



मणिपुर में फिर भाजपा सरकार

लगभग एक वर्ष के राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर में पूर्व मंत्री युमनाम खेमचंद सिंह के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार का गठन हो गया है। उन्होंने बुधवार शाम को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ दो उपमुख्यमंत्री कुकी समुदाय से नेमचा किपगेन और नागा समुदाय से लोथी दिखो ने भी शपथ ली। पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के कट्टर आलोचक खेमचंद सिंह को भाजपा नेतृत्व में स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। लम्बे समय से जातीय हिंसा और राजनीतिक अनिश्चितता झेल रहे राज्य में नई सरकार का गठन कर भाजपा ने स्थिति को संतुलित करने के लिए बड़ा दांव खेला है। भाजपा ने मैतेई और कुकी समुदाय के नेताओं को सत्ता में साथ लाने की रणनीति पर काम किया। इसके पीछे सामाजिक संतुलन और शांति बहाली के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा ने कुकी समुदाय से आने वाली महिला नेता नेमचा किपजेन को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया। दोनों समुदायों को सत्ता में प्रतिनि ष्ठ देकर बीजेपी राजनीतिक और सामाजिक तनाव कम करके राज्य में स्थिर सरकार देना चाहती है। मणिपुर में नई सरकार का गठन संवैधानिक जरूरत और राजनीतिक अनिवार्यता दोनों ही थी क्योंकि राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि फरवरी में खत्म हो रही है। ऐसे में समय पर सरकार का गठन जरूरी था। नई सरकार बनने से प्रशासनिक फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे और शांति की बहाली की प्रक्रिया मजबूत होगी।

60 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के पास 37 विधायक हैं और उसके पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त आंकड़े हैं लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैतेई-कुकी संघर्ष को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए भाजपा क्या संतुलन कायम करती है जिससे शांति बहाली हो सके। मैतेई समुदाय से ताल्लुक रखने वाले युमनाम खेमचंद सिंह की पहचान ऐसे नेता की है जिन्हें हर समुदाय का समर्थन हासिल है। वे हर किसी समूह के साथ जाकर काम कर सकते हैं। उनकी छवि एक सुलझे हुए राजनेता की है जो संगठन और सरकार दोनों का अनुभव रखते हैं। वे 2017 से 2022 तक मणिपुर विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कई विधायी निर्णय लिए और सदन को सुचारू रूप से चलाने का अनुभव प्राप्त किया। 2022 में पुन: बीजेपी सरकार बनने पर उन्हें एन. बीरेन सिंह की कैबिनेट में शामिल किया गया था और उनके पास नगर प्रशासन और आवास विकास, ग्रामीण विकास और पंचायत राज जैसे भारी-भरकम मंत्रालय थे। खेमचंद सिंह को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन हासिल है और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ भी उनके अच्छे संबंध हैं। मणिपुर में 3 मई 2023 को जातीय हिंसा शुरू हुई थी जिसमें 300 से अधिक लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हुए। हिंसा की शुरुआत तब हुई जब मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने की सिफारिश भेजने को कहा। इस फैसले से पहाड़ी इलाकों में रहने वाली कुकी जनजातियों में असुरक्षा बढ़ी। उनका मानना ​​था कि मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा मिलने पर आरक्षण में उनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी। साथ ही घाटी का प्रभाव बढ़कर पहाड़ी इलाकों के प्रभावों को कम करेगा। कुकी लोगों को डर था कि अगर मैतेई लोगों की जनजातीय दर्जा मिल जाता है तो वे और भी ज्यादा हाशिये पर चले जाएंगे। बहुसंख्यक मैतेई मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में बसे हुए हैं जबकि कुकी लोगों को बसावट पहाड़ी इलाकों में है।

मणिपुर में भूमि अधिकार, जंगलों का नियंत्रण, सीमा निर्धारण और पुनर्वसन जैसे मुद्दे कई वर्षों से विवाद का केंद्र रहे हैं। कुकी समुदाय का आरोप था कि मैतेई समुदाय उनके अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहा है। मैतेई समुदाय मुख्‍यतः हिन्‍दू हैं जबकि कुकी अधिकतर ईसाई हैं। यह पहचान राजनीति में बदल कर संघर्ष को और गहरा कर गई। हिंसा फैली तो घर जले। मंदिरों और चर्चों पर हमले हुए। हजारों लोग विस्थापित हुए। कई जिलों में महीनों तक कर्फ्यू लगा रहा। इंटरनेट बंद रहा। सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। तत्कालीन एन. बीरेन सरकार हिंसा को रोकने में पूरी तरह विफल रही। इस हिंसा ने मणिपुर के समाज को पूरी तरह से बांट दिया। कुकी और मैतेई समुदाय अपनी-अपनी सुरक्षा में लग गए। हालांता ऐसे बने कि दोनों समुदायों ने एक-दूसरे के इलाकों में जाना ही बंद कर दिया। कुकी समूहों ने एन. बीरेन पर मैतेई लोगों का पक्ष लेने का आरोप भी लगाया। अंततः केन्द्र सरकार ने एन. बीरेन पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया लेकिन विधानसभा निलम्बित रखी गई। केन्द्र सरकार ने दोनों समुदायों में दूरियां पाटने के लिए बातचीत का सिलसिला शुरू किया। कुकी समुदाय का कहना है कि समस्या का हल सिर्फ शांति प्रक्रिया के दौरान ईमानदारी और गैर पक्षपाती रवैया अपना कर ही हो सकता है। जब तक संसंधनों का समान बंटवारा या केन्द्रीय व्यवस्था नहीं स्थापित होती, समस्या खत्म नहीं होगी और समाधान की प्रक्रिया जटिल बनी रहेगी।

इस समस्या से निपटने का टिकाऊ तरीका यही है कि जातीय तनाव की जड़ के जो मुद्दे हैं उन्हें हल किया जाए और ऐसा समाधान किया जाए जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। कुकी में नंगा समुदाय भी शामिल है। कुकी और मैतेई समुदायों में तनाव तो अंग्रेजों के शासन से ही चल रहा है। अब जबकि राज्य में फिर से सरकार बन गई है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि युमनाम सरकार राज्य में शांति बहाल के प्रयास करेगी और दोनों समुदायों के बीच गहरी हो चुकी अविश्वास की खाई को पाटने के लिए बातचीत की प्रक्रिया शुरू करेगी। हाल ही में युमनाम खेमचंद सिंह ने कुकी बहुल इलाकों का दौरा कर शांति और बातचीत की वकालत की थी।

मैतेई समुदाय से होने के बावजूद दूसरे समुदायों तक उनकी पहुँच उन्हें मौजूदा संकट में एक स्वीकार्य चेहरा बना सकती है। विवादों से दूर रहने वाले नेता के तौर पर उनकी पहचान बड़ी भूमिका निभा सकती है। जरूरत इस बात की है कि दोनों समुदायों के बीच संवाद कायम हो। जमीन और आरक्षण पर स्पष्ट नीति तैयार की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर से तनाव पैदा हो सकता है। कुकी समुदाय को भी कुकीलैंड या जूमलैंड नाम से अलग प्रशासनिक स्वायत्तता की मांग छोड़नी होगी। क्योंकि मैतेई समुदाय इस मांग को राज्य की अखंडता के लिए खतरा मानता है। पड़ोसी देश से होने वाली अवैध घुसपैठ को भी नियंत्रित किए जाने की जरूरत है। राज्य में निष्पक्ष सरकार का होना बहुत जरूरी है। ताकि लोगों को भरोसा हो कि सरकार उनके हक के लिए काम कर रही है।

प्रतिभा को पहचान मिले...

“विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बिल 2026 सामाजिक समानता की ओर कदम बढ़ाने को तैयार है, अनुसूचित जाति और जनजाति एक बेहतर भविष्य की हकदार है, शिक्षा के द्वार खुले हों, यह प्रत्येक वर्ग का अधिकार है, प्रतिभा को पहचान मिले, न हो कोई भेदभाव का प्रहार है, नीति में समावेश हो, यही तो सच्चा सुधार है, ज्ञान के इस महायज्ञ से सशक्त होगा भारत के विकास का आधार है...।”



निर्मला जो ने एक और बजट पेश कर दिया। यह उनका लगातार 9वां बजट था। उनसे अधिक केवल मोरारजी देसाई ने 10 बजट पेश किए थे, पर वह लगातार नहीं थे। मैं अर्थ शास्त्री नहीं हूँ इसलिए बजट के गुण- दोष पर टिप्पणी नहीं कर रहा। यह नोट किया गया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था 7.4% को अच्छी दर से तरक्की करेगी। हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और कुछ सालों में जर्मनी को पछाड़ कर हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। यह उस देश के लिए मामूली उपलब्धि नहीं है जो कभी अपने लोगों का पेट भरने के लिए अमेरिका से PL-480 कार्यक्रम के अधीन अनाज के लिए निर्भर था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ़ ने कहा है कि दूसरे देशों से ‘भीख मांगते’ उनका त्सर झुक जाता है और उन्हें शर्म आती है। भारत की वह हालत नहीं बनी। यह आजादी से लेकर अब तक हमारे नेतृत्व की सही सोच का परिणाम है।

वर्तमान मोदी सरकार ने लगभग 12 सालों में देश को स्थिरता दी है जिस कारण भी देश तरक्की कर रहा है। हाल ही में हम ई-यू से बड़ी डील कर हटे हैं और डोनाल्ड ट्रम्प ने भी डील की घोषणा की है, पर इसका ब्यौरा अभी स्पष्ट नहीं। देश मजबूती से 2047 में ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की तरफ़ चल रहा है,ऐसा हमें बताया गया है। यह सब तो ठीक है, संतोषजनक है, पर ज़मीनी हकीकत तो यह है, सड़कें टूटी हुई हैं,कूड़े-कचरे के ढेर हैं, पर कोई परवाह करने वाला नहीं क्योंकि चुनाव रोज़मर्रा के मसलों पर नहीं, भावनात्मक मुद्दों पर लड़े जाते हैं। धर्म पर बांटने के बाद जाति पर बांटने का भी प्रयास होता रहता है। दुख की बात है कि यूजीसी जैसी उच्च संस्था जिसकी जिम्मेवारी बच्चों का भविष्य संभालने की है, ने ही ऐसे नियम बना दिए जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ‘विभाजनकारी’ और ‘खतरनाक’ करार दिया। नियम ऐसे थे कि कैम्पस के अंदर जातिगत बंटवारा हो सके था। कूड़े अदालत ने रोक तो लगा दी, पर सवाल तो उठता है कि प्रयास ही क्यों किया गया?

यह लेख मैं दिल्ली में लिख रहा हूँ। चार दिन पहले मैं जालंधर से यहां सड़क के रास्ते आया था। विभाजन से पहले इसे कभी सड़क-ए-आज़म कहा जाता था। अंग्रेजों ने इसे जटी रोड का नाम दिया और आज़ाद भारत में यह शेरशाह सूरी मार्ग बन गया। आजकल यह NH-1 कहा जाता है। इसका आकार बढ़ चुका है। दोनों तरफ़ तीन-तीन लेन हैं। नितिन गडकरी को ऐसे हाईवे बनाने



तारीख 1 फरवरी 2026। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण जब संसद में बजट का पिटारा खोल रही थीं तो पूरी दुनिया की नज़रें टीवी स्क्रीन पर चिपकी थीं लेकिन यह बजट सिर्फ आमदनी और खर्च का हिसाब-किताब नहीं था। यह भारत का एक ऐसा ‘लॉर डिक्लेरेशन’ था जिसकी गुंज बीसिंग से लेकर बार्शिंगटन तक सुनाई दी है। इसे सिर्फ एक आर्थिक दस्तावेज समझना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। इसे भारत की जियोपॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक कहना ज्यादा मुश्किल होगा।

आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, वहां तेल अब पुरानी खबर हो चुका है। “डेटा नया तेल है”, यह भी अब घिसा-पिटा डायलॉग हो गया है। असली खेल अब क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और सेमीकंडक्टर का है। जिसे हम और आप मामूली पत्थर या रेत समझते हैं, असल में वही 21वीं सदी का सोना है और 2026 के इस बजट में मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत अब इस सोने का खरीदार नहीं, बल्कि सौदागर बनेगा।

मामला बड़ा पेचीदा है। इसे समझने के लिए थोड़ा स्लैशबैक में चलते हैं। आज हमारे हाथ में मौजूद स्मार्टफोन हो, सड़क पर दौड़ती इलेक्ट्रिक कार हो, सीमा पर तैनात हमारी मिसाइलें हों, फ़ाइट्र जेट का ग्राइंड्स सिस्टम हो, या फिर विंड टरबाइन के मैग्नेट-इन सबमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स लगते हैं। और कड़वा सच यह है कि पिछले तीन दशकों से चीन ने इस मार्केट को अपनी जागीर बना रखा था लेकिन 1 फरवरी 2026 को भारत ने कहा दिया है, “बस, अब और नहीं!” बजट में जो सबसे बड़ी बात सामने आई, वह है डोडिकेटेड रेयर अर्थ कारिडोर और सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। यह कोई हवा-हवाई बात नहीं है। सरकार ने अपनी



पंजाब की राजनीति में डेरों का प्रभाव कोई नई बात नहीं है, यह सालों से चलता आ रहा है। असल में डेरों की शुरुआत अंग्रेजों के समय से हुई जब उन्होंने सिखों की ताकत को कम करने के लिए, उन्हें गुरु ग्रन्थ साहिब से तोड़कर डेरों की ओर अप्रसर किया। देखते ही देखते सिख समुदाय के ज्यादातर लोगों का रुख डेरों की ओर बढ़ने लगा क्योंकि जितने भी डेरे खोले गए हैं उनमें से ज्यादातर पंथ (धैणी साहिब), डेरा बाबा मुराद शाह (नकोदर), डेरा बाबा बालक नाथ, डेरा बल्लन रविदासिया डेरा हैं जिनके हजारों लाखों अनुयाई हैं और उन्हें डेरों से जो भी आदेश मिलता है वह उसी पर चलते हुए वोट करते हैं और उन्हें देखते हुए ज्यादातर आम वोटर की राय भी बदल जाती है जिससे यह तय माना जाता है कि डेरा प्रमुख की दिव्य दृष्टि सिख पाटी या नेता पर पड़ गई उसके समर्थन में वोटों की बारिश होना तय है।

प्रधानमंत्री मोदी का पंजाब दौरा

देश के उपभामंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब दौरा और वह भी संत रविदास की जयंती वाले दिन उनके डेरे में जाना पंजाब की राजनीति में होने वाले बदलाव की ओर इशारा करता दिख रहा है। नरेंद्र मोदी शायद पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने रविदास भाईचारे के डेरे में जमकर ना सिर्फ हाजरी भरी, बल्कि उन्हें पूर्ण सम्मान भी दिया और आदमपुर हवाई अड्डे का

हमारी ज़िन्दगी कब सुधरेगी?

का जायज श्रेय दिया जाता है। देशभर में हाईवे और सुपर हाईवे का जाल बिछ गया है लेकिन यह नहीं देखा जाता कि मेटैरियल कैसा लगता है, या हाईवे की मेन्टेनेंस कैसी है? जालन्धर से दिल्ली तक अब इस हाईवे पर झटके मिलते हैं। लालू प्रसाद यादव ने एक बार कहा था कि सड़कें एक प्रसिद्ध अभिनेत्री (नाम नहीं लूंगा, क्योंकि वह सही नहीं है) के गाल जैसे मुलायम होंगी। पर अब तो गाल में गड्डे पड़ गए हैं! असली समस्या है कि देश में बर्क कलचर में सुधार नहीं हुआ। जिनका काम देखना है, वह जिम्मेवारी

“ टिकाऊ सड़कों से किसी की जेब नहीं भरती इसलिए खुदाई होती रहती है, टेंडर होते रहते हैं, सड़कें फिर बनाई जाती हैं। पहली बरसात में गड्डे पड़ जाते हैं। जनवरी की धुंध में ग्रेटर नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार पानी से भरे निर्माणधीन गड्डे में गिर गई। सावधान करने के लिए न कोई बोर्ड था, न कोई बाड़ या चारदीवारी इसलिए वह सीधा पानी में चले गए और डूब गए। पिता को अंतिम फ़ोन में उसने कहा, “मैं मरना नहीं चाहता’। नोएडा तो ‘स्मार्ट सिटी” घोषित है। पर किसी अफ़सर ने नहीं देखा कि खुला असुरक्षित गड्ढा है और हादसा हो सकता है?

सही नहीं निभा रहे। बाबुओं की मानसिकता नहीं बदली। बाक़ी तबाही भ्रष्टाचार ने पूरी कर दी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैकसिमम गवर्नंस’। अर्थात सरकार बढ़िया शासन देगी। पर आज भी काम करने की संस्कृति वही है जिसका दुष्परिणाम आम आदमी भुगत रहा है। मैं पिछले महीने मलेशिया की राजधानी कौलालम्पुर में था। सड़कें सचमुच उस अभिनेत्री की गाल की तरह मुलायम थीं। कहीं कोई हार्न नहीं बजाता, कहीं पुलिस वाला नजर नहीं आता। वातावरण भी साफ़-सुथरा था जबकि दिल्ली में आते ही प्रदूषण आपको पकड़ लेता है। गला खराब हो गया, नाक बहने लगी। देश की राजधानी, दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। बीमारी का घर है। बाहर से लोग आने से घबराते है। कोई इलाज भी नहीं। यह कैसी गवर्नंस है कि राजधानी में ही लोगों को बीमार होने और कईयों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है क्योंकि प्रदूषण को कम करना सरकारी प्राथमिकता में नहीं है? जिस संसद ने 150 साल पुराने वंदे मातरम् पर एक दिन बहस में लगाया, उसके पास प्रदूषण पर बहस के लिए कोई समय नहीं था जबकि हर सर्दियों में बड़ी संख्या में नागरिक मरीज बन रहे हैं।

इसका अगर आप बीमार हो गए तो किधर जाओगे? सरकारी अस्पतालों की जो शोचनीय

हालत है वह सबके सामने है। ठिठुरती सर्दी में देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स के बाहर खुले में मरीजों के सम्बन्धी सोने के लिए मजबूर हैं। ऐसे चित्र प्रकाशित हो चुके हैं, पर शासन को परवाह नहीं है। सरकार इलाज के बहुत से खर्चें कम कर रही है, पर क्योंकि सरकारी अस्पतालों की हालत नहीं सुधरती इसलिए, नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 60% लोग प्राइवेट अस्पतालों में महंगा इलाज करवाने के लिए मजबूर हैं। बात वहीं आती है कि बर्क कलचर कब संवेदनशील, कार्य कुशल और भ्रष्टाचार

“ टिकाऊ सड़कों से किसी की जेब नहीं भरती इसलिए खुदाई होती रहती है, टेंडर होते रहते हैं, सड़कें फिर बनाई जाती हैं। पहली बरसात में गड्डे पड़ जाते हैं। जनवरी की धुंध में ग्रेटर नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार पानी से भरे निर्माणधीन गड्डे में गिर गई। सावधान करने के लिए न कोई बोर्ड था, न कोई बाड़ या चारदीवारी इसलिए वह सीधा पानी में चले गए और डूब गए। पिता को अंतिम फ़ोन में उसने कहा, “मैं मरना नहीं चाहता’। नोएडा तो ‘स्मार्ट सिटी” घोषित है। पर किसी अफ़सर ने नहीं देखा कि खुला असुरक्षित गड्ढा है और हादसा हो सकता है?

मुक्त बनेगा? दिल्ली में राजपथ को ‘कर्त्तव्य पथ’ का नाम दे दिया गया है, पर कर्त्तव्य के प्रति भावना कब पैदा होगी? बार-बार निर्बनर्मित पुल यहां क्यों गिरते हैं? बिहार में तो बरसात में एक दर्जन पुल बह गए, पर जनता ने उसी अक्षम सरकार को भारी बहुमत से निर्वाचित कर दिया। इंदौर को कई वर्षों से सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया जा रहा है, पर वहां ही लगभग दो दर्जन लोग पानी पीने से मारे गए क्योंकि पानी और सीवरेज मिल गए थे। सरकारी स्कूलों की हालत साफ़ जानने हैं। केवल दिखावा होता है, पर बेहतर करने का कोई ठोस प्रयास नहीं किया जाता। शायद इसलिए क्योंकि जिन की जिम्मेवारी इन्हें ठीक करना है उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते। कुछ वर्ष पहले मुम्बई के राण इलाक़े में रहने वाले अभिनेता रितिक रोशन ने प्रेस में शिकायत की कि उनके नल में भूरे रंग का पानी आ रहा है। वहां भी पानी में सीवरेज मिल गया था। हर बरसात मेंहमारे बड़े शहर, दिल्ली, मुम्बई, बेंगलोर, पानी में डूब जाते हैं। इसे प्रदूषण की तरह सामान्य समझा जाता है इसलिए स्थाई समाधान ढूँढने की कोशिश नहीं की जाती। बेंगलोर को कभी गार्डन सिटी कहा जाता था, पर अब वह खचाखच भरे ट्रैफ़िक और चरमरा रहे इंफ़्रास्ट्रक्चर का शहर बन चुका है।सुध लेने वाला कोई नहीं क्योंकि सीएम और डिप्टी सीएम कुर्सी

भविष्य की करेसी पर भारत का होगा कंट्रोल

तिजोरी का मुंह खोल दिया है, ताकि हम चीन की गुलामी से आजाद हो सकें। सरकार ने कस्टम ड्यूटी में भारी कटौती की है अब जरा इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी की बात करते हैं जो अब तक पदों के पीछे था, वह है हमारा राजस्थान। वीरों की भूमि राजस्थान! अब तक हम राजस्थान को सिर्फ पर्यटन, किले और रेगिस्तान के लिए जानते आए हैं लेकिन बजट 2026 ने राजस्थान की तकदीर का पन्ना पलट दिया है। यहां की चट्टानों में ऐसे रेयर अर्थ छिपे हैं जो दुनिया में बहुत कम जगहों पर मिलते हैं। तटीय इलाकों में जो रेयर अर्थ मिलता है, वो रेत में होता है लेकिन राजस्थान में यह ठोस चट्टानों में है। बजट में इसी एडवांस टेक्नोलॉजी और एक्सप्लोरेशन के लिए भारी-भरकम वूट दी गई है। इसका मतलब है कि नागौर और आस-पास के क्षेत्रों में अब बड़ी-बड़ी रिफ़ाइनरीज खड़ी होंगी। नागौर के डेगाना क्षेत्र में तो पहले ही लिथियम चुके हैं। लिथियम मिनरल्स के संकेत मिल चुके हैं। चूँकि राजस्थान पहले से ही सोलर एनर्जी का किंग है, अब वहां बैटरी बनाने की फैक्ट्रियां भी लंगेंगी। यानी बिजली भी वहीं बनेगी और उसे स्टोर करने वाली बैटरी भी। सोचिए, अब राजस्थान में किस कदर नौकरियों को बाढ़ आने वाली है।

अब नजर घुमाते हैं देश के बाकी हिस्सों पर, क्योंकि यह लड़ाई अकेले राजस्थान नहीं लड़ सकती। यह टीम इंडिया का गेम है। बजट ने दक्षिण और पूर्वी भारत के राज्यों - केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा को एक रणनीतिक कवच में बदल दिया है। सरकार ने इन चार राज्यों में डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। यह कोई सड़क वाला कॉरिडोर नहीं है, यह एक पूरा इंडस्ट्रियल क्लस्टर है। केरल और तमिलनाडु के पास समुद्र तट पर मोनाजाइट रेत का खजाना है। बजट में 7,280

करोड़ रुपये की रेयर अर्थ परमानेंट मैनेट स्कीम (REPM) को हेरी झंडी दिखाई गई है। इसका मुकदम कच्ची मिट्टी नहीं, बल्कि फिनिरड प्रोडक्ट बेचना है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को तो सरकार ने ईवी और मैग्नेट हब बनाने की ठान ली है। रेयर अर्थ से जो परमानेंट मैनेट बनेते हैं, वो इलेक्ट्रिक मोटर का दिल होते हैं। अब तक हम ये चुंबक चीन से मंगाते थे। बजट का प्लान यह है कि तमिलनाडु की फैक्ट्रियों में ये चुंबक बनें और वहां बगल में बन रही इलेक्ट्रिक कारों में फिट हो जाएं।

सप्लाई चेन का ऐसा इंटिग्रेशन चीन की नींद उड़ाने के लिए काफी है और गुजरात तो सेमीकंडक्टर का हब बनने जा रहा है। बजट में वित्त मंत्री ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 (ISM 2.0) का ऐलान किया है। पहले मिशन में हमने दुनिया को दिखाया कि हम फैब लगा सकते हैं, अब मिशन 2.0 में हम दिखाएंगे कि हम टेक्नोलॉजी ईजाद भी कर सकते हैं। ISM 2.0 के लिए शुरुआती 1,000 करोड़ रुपये अलग से रख दिए गए हैं। सानंद में माइक्रोन का प्लांट परफरमी 2026 के अंत तक पूरी तरह उत्पादन शुरू करने जा रहा है। यह भारत का पहला बड़ा कमर्शियल चिप पैकेजिंग प्लांट है। धोलेर में टाटा को जो प्लांट आ रहा है, वो तो गेम चेंजर है ही। बजट 2026 ने इस आग में घी डालने का काम किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैयूफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) का बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब है कि मोबाइल और लैपटॉप का हर छोटा-बड़ा पुर्जा अब मेड इन इंडिया होगा।

अब असली बात पर आते हैं कि आखिर मोदी सरकार इतना आक्रामक क्यों हो रही है? तो मोदी सरकार के लिये यह विशुद्ध रूप से देश की सुरक्षा का मामला है। सरकार की सोच एकदम साफ

की खींचातानी में लगे हुए हैं। हमारे शहर गारबेज, गड्ढों और ट्रैफ़िक के दु:स्वप्न हैं। टिकाऊ सड़कों से किसी की जेब नहीं भरती इसलिए खुदाई होती रहती है, टेंडर होते रहते हैं, सड़कें फिर बनाई जाती हैं। पहली बरसात में गड्डे पड़ जाते हैं।

जनवरी की धुंध में ग्रेटर नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार पानी से भरे निर्माणधीन गड्डे में गिर गई। सावधान करने के लिए न कोई बोर्ड था, न कोई बाड़ या चारदीवारी इसलिए वह सीधा पानी में चले गए और डूब गए। पिता को अंतिम फ़ोन में उसने कहा, “मैं मरना नहीं चाहता”। नोएडा तो ‘स्मार्ट सिटी’ घोषित है। पर किसी अफ़सर ने नहीं देखा कि खुला असुरक्षित गड्ढा है और हादसा हो सकता है? बिल्डर भी समझते हैं कि रिश्तत से उनका काम चल जाएगा, इसलिए नियमों का पालन नहीं करते। हर प्रदेश में अवैध खनन हो रहा है। सब कुछ ड्रोन से नज़र आ सकता है, पर रकता क्यों नहीं? अरावली के जंगलों को बचाने के लिए सुप्रीम को दखल क्यों देनी पड़ी? सरकार ने तो नियम बदल दिए थे जिनका सहारा लेकर कटान चलता रहता और दिल्ली का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता।

नई समस्या बढ़ता क्राइम है। हर शहर में गैंग बन गए हैं जो लुटपाट करते हैं। मुम्बई में फिक्स निमांता रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हो कर हटी है।पंजाब में यह सामान्य बन चुका है।विदेश में बैठे या जेल में बंद गैंगस्टर फ़रौती की मांग करते हैं और न मिलने पर हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। कई परिवार तो इनके आतंक के कारण देश छोड़ने पर मजबूर हैं। इसके बारे कोई राष्ट्रीय नीति बनाने की जरूरत है।आशा है गृहमंत्री अमित शाह इस तरफ़ ध्यान देंगे। सरकार ने दिल्ली जिम्मेदारी नागरिक को सुर्खा देना है। हमारे शहर असुरक्षित बनते जा रहे हैं।

हम जो टेक्स देते हैं, उन्हें सरकार की तरफ़ से क्या मिलता है? हवा साफ़ नहीं, पानी साफ़ नहीं, रिश्तत अभी भी चलती है, शहर गंदे हैं। क्राइम और ड्रास बढ़ते जा रहे हैं। सुरक्षा नहीं है। निर्मला जी का कहना है कि सरकारी खर्चा बढ़ाने के लिए वह टैक्स का जाल और बढ़ाएंगी, पर क्या इससे हमारी जिन्दगी में सुधार आएगा? जो भारतीय विदेश चला जाता है वह लौटना नहीं चाहता क्योंकि बाहर “क्वालिटी ऑफ लाइफ़” बेहतर बताई जाती है। हमारी तो राजधानी रहने योग्य नहीं रही। सरकार ने स्मार्ट सिटिज बनाई हैं, पर क्या एक भी शहर उस मायने में स्मार्ट है? हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ कम इम्बूव करेगी? क्या समय नहीं आ गया कि इस तरफ़ ध्यान दिया जाए ताकि टेक्स देने वाला नागरिक महसूस कर सके कि उसे भी बदले में कुछ मिलता है। या ऐसा ही होता रहेगा? बजट आगे, बजट जाओगे, पर हमारी जिंदगी ऐसे ही चलती जाएगी?

पंजाब की राजनीति में डेरों का असर

संभव नहीं है जिसके चलते वह डेरों में हाजरियां भरते हैं। कौटिल्य, भाजपा, आम से लेकर स्वयं को पंथक कहलाने वाली पार्टी शिरोमणि अकाली दल के ज्यादातर नेतागण भी लम्बे समय से ऐसा ही करते आ रहे हैं। असल में डेरों के द्वारा समाजिक सेवाएं कर राजनीतिक पहचान बनाई जाती है जैसे शिक्षा, नशा-मुक्ति, लंगर और स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं। इससे लोगों में भरोसा बनता है और वही भरोसा चुनाव के समय राजनीतिक फैसले में बदल जाता है। आज पंजाब में वैसे तो सैकड़ों डेरे चल रहे हैं मगर उनमें से कुछ प्रमुख हैं जिनमें डेरा सच्चा सौदा,

नाम भी संत रविदास के नाम पर रखा गया। देखा जाए तो इस क्षेत्र में 32 प्रतिशत दलित समुदाय के वोट हैं और इस सम्मान के बाद निश्चित तौर पर



उनकी सोच भाजपा के प्रति बदलने वाली है। आम तौर पर देखा जाता है कि यह वोट किसी एक पार्टी का या जाकर इसका बंटवारा होता आया है, पर अब माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के इस कदम के बाद यह एकतरफा भाजपा के समर्थन में भुगत सकता है जिसके चलते अन्य सभी पार्टियों की चिन्ता बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। आज तक पंजाब में भाजपा अकाली दल की बैसाखी बनकर सरकार बनाती आई है मगर अब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने दम पर सरकार बनाने का ख़ाब संजोए हुए है और वह तभी पूरा हो

सकता है जब शहरों के साथ साथ गांव देहात का वोट भी भाजपा के हक में भुगतने जो कि शुरू से ही एकतरफा शिरोमणि अकाली दल और पिछले चुनाव

में आप को मिला। इसी के चलते शायद भाजपा ने अब डेरों का रुख किया और हाल ही में डेरा बल्लन में प्रधानमंत्री ने हाजरी भरी। इससे आए डेरा व्यास में भी प्रधानमंत्री मोदी होकर आए। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन सीमित था लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने कुछ बढ़ोतरी दर्ज की। भाजपा की नजर अब दोआबा क्षेत्र की उन विधायनसभा सीटों पर है जहां दलित और रविदासिया मतदाता निर्णायक भूमिका निभते हैं। भाजपा की रणनीति यही संकेत देती है कि पार्टी पंजाब में केवल पारंपरिक शहरी या सीमित वर्गीय राजनीति से बाहर निकलकर व्यापक सामाजिक संतुलन बनाते की कोशिश कर रही है। इसी प्रकार पंजाब के बड़े सियासी चेहरों को भी पार्टी में शामिल किया जा रहा है।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83

पंजाब केसरी

दिल्ली अवसाल :

फोन आधिकारिक :011-30712200,45212200,

प्रसार विभाग : 011-30712224

रिज्ञापन विभाग : 011-30712229

समादकीय विभाग : 011-30712292-93

मैगजीन विभाग : 011-30712330

फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84

Email : Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-ब्रिटिंग प्रेस कॉम्पलेक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए इन्द्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शर्मा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रेस, 2-ब्रिटिंग प्रेस कॉम्पलेक्स, वजीरपुर, दिल्ली से उद्भित तथा 2, ब्रिटिंग प्रेस कॉम्पलेक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

नतीजे अलग चाहिए, तो तरीका भी अलग अपनाना होगा। पुराने और सुरक्षित रास्तों पर चलकर बेहतर परिणाम नहीं मिलते। चाहे निवेश हो या जीवन, सोच में बदलाव, नई रणनीति और जोखिम लेने की हिम्मत ही सफल बनाती है।

मैलोडी डॉबसन, सीईओ, एरियल इन्व्हेस्टमेंट्स



पत्रिका फाइनेंस

@बिजनेस & वेल्थ

असर

अप्रैल से भारत-अमरीका ट्रेड डील का बड़ा लाभ मिलने लगेगा, 2.60 अरब डॉलर का एशियाई देशों का निर्यात खतरे में

देश से कपड़ा-फुटवियर-ज्वैलरी निर्यात 20% बढ़ने की उम्मीद

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली. अमरीका के साथ व्यापार समझौते पर अमल के बाद टैरिफ घटकर 18% पर आने के बाद टेक्सटाइल, लेदर और जेम्स-ज्वेलरी जैसे रोजगारपरक उत्पादों के निर्यात में 20% का इजाफा हो सकता है। निर्यातकों का कहना है कि अप्रैल से उन्हें इस समझौते का बड़ा लाभ मिलने लगेगा, क्योंकि नई दर पर आर्डर मिलने में थोड़ा समय लगेगा। अमरीकी में निर्यात बढ़ने की संभावना को देखते हुए कंपनियां भारत में निर्माण कराने के लिए निवेश भी करेंगी। अमरीकी कंपनियां जिन देशों में श्रम लागत कम होती है, वहां मैनुफैक्चरिंग करना सस्ता करते हैं।

बैंकों की गुहार

लोन तेज, जमा सुस्त लिक्विडिटी नियमों में ढील देने की मांग

मुंबई@ पत्रिका. बैंकों ने लोन के लिए ज्यादा फंड उपलब्ध कराने के मकसद से रिजर्व बैंक से लिक्विडिटी नियमों में ढील देने का अनुरोध किया है। सूत्रों ने बताया कि बैंकों में जमा की तुलना में कर्ज की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिससे फंडिंग पर दबाव बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, बैंकों ने आरबीआइ से उस नकदी का कुछ हिस्सा उपयोग करने की अनुमति मांगी है, जिसे उन्हें अल्पकालिक वित्तीय दबाव को स्थिति के लिए केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है। इस मामले पर पिछले दो हफ्तों के दौरान आरबीआइ और कई बैंकों के बीच बैठक हुई है।

ईसीएमएस

इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में ₹11,150 करोड़ निवेश की संभावना

नई दिल्ली@ पत्रिका. आइटी मंत्रालय जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैनुफैक्चरिंग स्क्रीम (ईसीएमएस) के तहत 5 से 7 नए आवेदनों को मंजूरी दे सकता है। इन परियोजनाओं में 11,150 करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना है। इन इकाइयों से लगभग 29,000 करोड़ रुपए का उत्पादन हो सकता है। साथ ही, इससे करीब 19,000 लोगों को सीधे रोजगार मिलने की उम्मीद है। एक अधिकारी ने बताया कि ये सभी परियोजनाएं 2026 में शुरू हो सकती हैं। नई इकाइयां प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, लिथियम-आयन सेल, ऑप्टिकल ट्रांसीमिटर, एनोड मटेरियल व कॉपर-क्लेड लेमिनेट के साथ एल्यूमिनियम एक्स्ट्रूजन जैसे क्षेत्रों में स्थापित की जा सकती हैं।

पीएम आवास योजना 2.0 29 लाख से ज्यादा परिवारों को लाभ

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2026-27 में बनेंगे 5 लाख मकान

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने शहरी गरीबों को पक्का मकान देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत लाभार्थी-नेतृत्व वाले निर्माण (बीएलसी) घटक में मकानों के निर्माण का वार्षिक लक्ष्य 2026-27 के लिए 350% बढ़ाकर 5 लाख मकान कर दिया है। बजट दस्तावेजों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में 1.10 लाख घर बनाने का लक्ष्य था। सरकार का मानना है कि इस फैसले से करीब 29.3 लाख परिवारजनों को सम्मानजनक आवास मिलेगा, जिसमें पानी, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाएं शामिल होंगी। इसके लिए बजट आवंटन 18,625 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

राहत

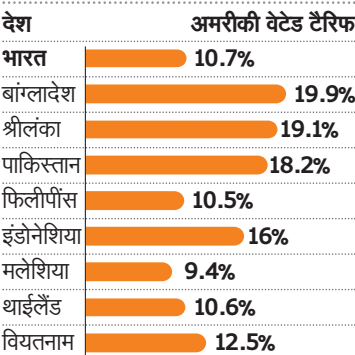
वैल्यू कैप समाप्त, जानिए कितना सोना-चांदी बिना कोई शुल्क दिए विदेश से भारत ला सकेंगे

विदेश से ड्यूटी-फ्री सामान लाने की लिमिट बढ़कर ₹75,000

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने भारत आने वाले यात्रियों के लिए बैगेज नियमों में बड़ी राहत दी है। सरकार ने बैगेज रूल में बदलाव कर यूआई सहित विदेश से सोने के गहनों समेत कई सामानों पर ड्यूटी-फ्री छूट बढ़ा दी है। अब विदेश से यात्री 75,000 रुपए तक का सामान ड्यूटी-फ्री ला सकेंगे, यानी कोई शुल्क नहीं देना होगा। पहले लिमिट 50,000 रुपए थी। नया नियम 2 फरवरी से लागू है। नियम भारतीय नागरिकों, विदेशी पर्यटकों के लिए अलग-अलग लिमिट के साथ लागू किया गया है।

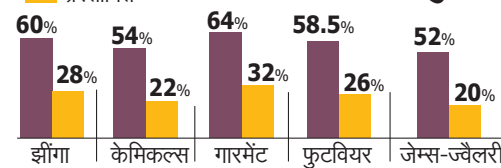
भारत अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर स्थिति में



(ट्रेड डील होने से पहले भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ के कारण अमरीका में प्रभावी औसत वेटेड टैरिफ 29.7% था, जो ट्रेड डील के बाद 10.7% रह जाएगा)

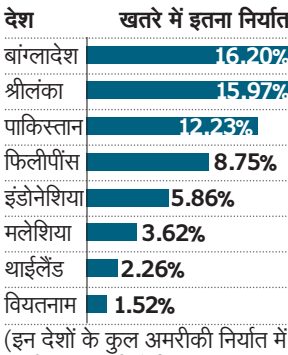


इतना कम हो जाएगा भारतीय उत्पादों पर शुल्क



डीमा केमिकल्स गारमेंट फुटवियर जेम्स-ज्वेलरी

इंडिया यूएस ट्रेड डील से किसे कितना नुकसान



(इन देशों के कुल अमरीकी निर्यात में इतनी आ सकती है गिरावट भारत-अमरीका ट्रेड डील के कारण)

10% बढ़ेगा रत्न-आभूषण निर्यात

50% शुल्क लगने के बाद खिलौना, फुटवियर जैसे सेक्टर में निवेश की इच्छुक अमरीकी कंपनियों ने हाथ खींचे थे। उद्योग संगठन सीआईटीई ने कहा, अब अमरीका को टेक्सटाइल निर्यात एक-दो साल में दोगुना हो सकता है। अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चैयरमैन ए शक्तिवेल ने कहा, अप्रैल से निर्यात में 20% की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं जेम्स एंड ज्वेलरी के निर्यात में 10% से ज्यादा बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जो 50% टैरिफ के कारण 45% गई थी। सी-फूड, प्रोसेस्ड फूड और कृषि निर्यात भी 10-15% बढ़ने की उम्मीद है।

राहत फैक्ट्रियों में बढ़ेगा रोजगार

टेक्सटाइल हब में नई भर्तियों की शुरू हो सकती है लहर

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली. प्रमुख टेक्सटाइल हब तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी के साथ राजस्थान में आने वाले माह में बड़े पैमाने पर भर्तियां होने की उम्मीद है। अमरीका के साथ हुए व्यापार समझौते के बाद निर्यात ऑर्डर धीरे-धीरे बढ़ने लगे हैं, जिससे उद्योग में हायरिंग की गतिविधियां तेज हो रही हैं। विशेषज्ञों ने कहा, भारत में करीब 7-10 करोड़ लोग इस सेक्टर में काम करते हैं। 50% टैरिफ से तिरुपुर, सूरत जैसे मैनुफैक्चरिंग हब में उत्पादन घटाना पड़ा। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार घटा था।

इतनी बढ़ेंगी नौकरियां

इंडियन टेक्सटाइल फेडरेशन के मुताबिक, नए समझौते से हर अतिरिक्त एक अरब डॉलर के निर्यात से करीब 1.50 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा हो सकती हैं। अर्थशास्त्री मिताली निकोर ने कहा, वैश्विक खरीदार लॉट रहे हैं, ऑर्डर वॉल्यूम में तेजी की संभावना है। तिरुपुर अमरीका को टेक्सटाइल निर्यात करने वाला भारत का सबसे बड़ा केंद्र है, यहां 8 लाख लोग काम करते हैं। निर्यात बढ़ने से अधिक श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी। इससे प्रमुख क्लस्टरों में भर्ती तेज होगी।

WEALTH नेक्स्टजेन बिजनेस CREATION

बिजनेस जर्नी नौकरी छोड़ शुरू करना चाहते हैं बिजनेस...

स्टार्टअप की नींव रखने से पहले मजबूत करें अपने फाइनेंस की जमीन

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली. नौकरी छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू करने का फैसला जितना रोमांचक लगता है, वास्तव में उससे कहीं अधिक जोखिम भरा भी होता है। नियमित वेतन की सुरक्षा से बाहर निकल व्यक्ति सीधे अनिश्चित आय, बढ़ते खर्च और मानसिक दबाव की दुनिया में कदम रखता है। कई बार बेहतरीन बिजनेस आईडिया भी केवल इसलिए दम तोड़ देते हैं क्योंकि आर्थिक तैयारी पूरी नहीं होती है। इसलिए स्टार्टअप की शुरूआत से पहले अपने पर्सनल फाइनेंस को संतुलित करना बहुत जरूरी है। स्टार्टअप की दुनिया में पहले कुछ साल बेहद चुनौतीपूर्ण होते हैं। इस दौरान नियमित आय का अभाव, अत्यावृष्टित खर्च और बाजार की अनिश्चितताएं किसी भी उद्यमी को परेशान कर सकती हैं। ऐसे में यदि व्यक्ति वित्तीय रूप से व्यवस्थित न हो तो स्थिति और भी जटिल हो जाती है।

अपने पर्सनल फाइनेंस को कैसे संभालें?



1 सेफ्टी कॉपर्स: घर के मासिक खर्चों को पूरा करने के लिए फंड बनाएं जो कम से कम पहले 6 महीने से 1 साल तक चल सके। जब तक स्टार्टअप से कमाई शुरू न हो जाए, यह फंड सहारा बनेगा।
2 मानसिक तैयारी: जितना खर्च आप सोच रहे हैं, असल में उससे ज्यादा खर्च आ सकता है। इसलिए मानसिक रूप से खर्च को वोगुना मानकर तैयारी करें।
3 हेल्थ इश्योरेंस: खुद और परिवार के लिए हेल्थ इश्योरेंस लें, क्योंकि नौकरी छोड़ते ही कंपनी का मेडिकल कवर खत्म हो जाता है। ऐसे में मेडिकल

इमरजेंसी पूरी वचत खत्म कर सकती है।
4 फिजूलखर्ची: शुरूआती वर्षों में फिजूलखर्ची से बचना बेहद जरूरी होता है। हर खर्च का स्पष्ट उद्देश्य हो और यह देखें कि खर्च सीधे बिजनेस की जरूरत से जुड़ा है या नहीं।
5 शुरूआती कर्ज: स्टार्टअप शुरू करते समय पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड से बचें। कर्ज मानसिक दबाव और जोखिम बढ़ाता है।
6 साइड इनकम: किसी संबोधित काम करके साइड काम से अतिरिक्त आय कमाई ला सकते हैं। इससे कैश फ्लो बना रहता है और स्टार्टअप पर दबाव कम होगा।
7 प्लान-बी: अगर बिजनेस नहीं चला तो अगला कदम क्या होगा? कर्ज चुकाने की क्षमता पहले से जांचें इससे घर, परिवार और भविष्य जोखिम में नहीं रहेगा।

पेज एक का शेष

वाट्सएप कमीशन...

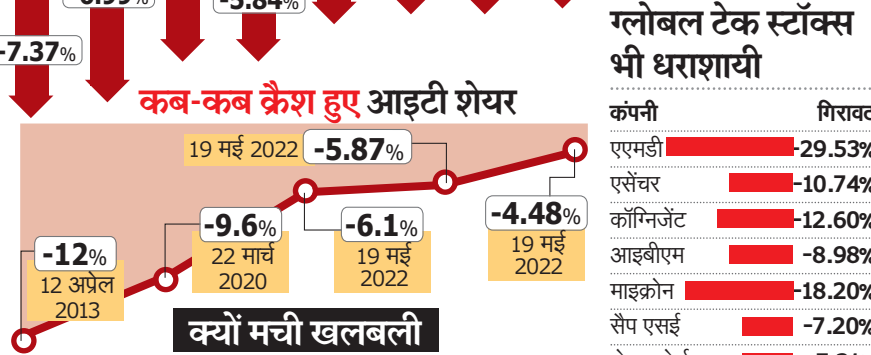
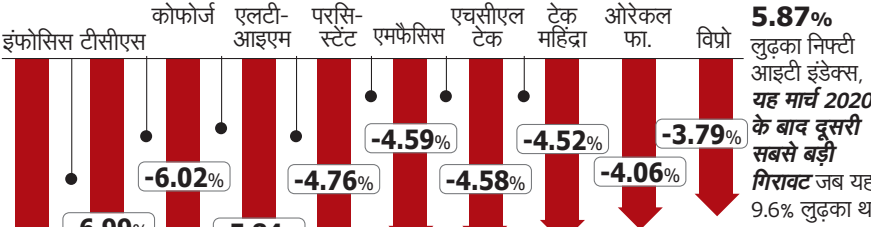
राज्य में अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग तरीके से नामों का उच्चारण किया जाता है। महिलाओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। यह रवैया पूरी तरह महिला विरोधी है। इस दौरान सीआईआइ सूर्यकांत ने कहा कि असली लोगों को मतवाला सूची में बने रहने चाहिए। इसके बाद सीआईआइ ने कहा, सभी नोटिफ वापस लाने अव्यावहारिक है। लेकिन नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ी होने पर चुनाव आयोग नोटिस जारी न करे। आयोग अपने अधिकारियों को भी निर्देश दे कि वे सेवेदनशील रहें। राज्य सरकार ऐसे लोगों की टीका देती है, जो बांग्ला और स्थानीय बोलियां जानते हों, और वे जांच करके चुनाव आयोग को बताएं कि स्थानीय बोली के कारण गलती है, तो इससे मदद मिलेगी।

खेल खत्म...

मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि स्थानीय निवासी चेतन कुमार की तीन लड़कियां निशिका (16), प्राची (14) और पाखी (12) नीचे जमीन पर गिरी थीं और बुरी तरह से घायल थीं। उन्होंने पाखी को उठाकर अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। 80 मिनट के बाद ही लड़कियों ने करीब 8-10 फीट ऊंचाई से छेलांग लगाई थी। पुलिस के अनुसार, तीनों बहनें 3 साल से रेगुलर स्कूल भी नहीं जा रही थीं। बताया जाता है कि उनके पिता ने उन्हें अत्यधिक गेमिंग के कारण फटकार लगाई थी और हाल ही में उन्हें ऐंग का उपयोग करने से रोक दिया था। घटना के समय क्रिशोरियों के माता-पिता ने दूसरे कमरे में सो रहे थे।

प्राची थी बॉस: तीनों बहनें पिछले 3 साल से ऑनलाइन गेम खेल रही थीं। ये टास्क वेस्ट गेम था। इस गेम में बीच वाली बहन प्राची बॉस थी, जो अपनी दोनों बहनों को भी टास्क देती थी। दोनों बहनें उसकी हर बात मानती थीं। हालत यह थी तीनों बहन हर काम साथ करती थीं, यहां तक कि खाना, सोना और घर को छोटे-मोटे काम भी साथ करती थीं।

पिता की हुई थी वो शादियां: इन क्रिशोरियों के पिता चेतन ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करते हैं। उन्होंने दो शादी की है। दोनों पत्नियां सगी बहनें हैं। पहली पत्नी से कोई बच्चा नहीं हो रहा था तो चेतन ने पत्नी की ही छोटी बहन यानी साली के साथ दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी से उसके तीन बच्चे हुए। इसी दौरान पहली पत्नी से भी दो बच्चे हो गए। जिन तीन बहनों ने खुदकुशी की है उनमें दो बहनें दूसरी पत्नी की जबकि एक पहली की बेटी हैं। सभी लोग साथ रहते थे।



नए एआई टूल आने से कानूनी रिसर्च प्लेटफॉर्म, डेटा विश्लेषण सेवाएं और पेशेवर सॉफ्टवेयर देने वाली कंपनियों को सीधी चुनौती मिल सकती है। इसी वजह से यह उर बढ़ गया है कि एआई के कारण लंबे समय तक चलने वाले और ज्यादा मुनाफा देने वाले स्क्वायरिफन कारोबार पर असर पड़ सकता है।

कर्मचारियों की संख्या पर टिके डिजिटल सर्विस मॉडल अब गंभीर दबाव में हैं। इसकी वजह यह है कि एजेंटिक एआई अब बड़े पैमाने पर होने वाले काम खूद करने लगा है। पहले माना जाता था कि एआई सॉफ्टवेयर कंपनियों की मदद करेगा। अब लग रहा है एआई खुद सॉफ्टवेयर की जगह ले सकता है।

कमोडिटीज गहनों पर नहीं मिलेगी छूट

सोना-चांदी आयात करना होगा सस्ता, बेस इंपोर्ट ड्यूटी घटी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली. सोने और चांदी के आयात पर सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने इन कीमती धातुओं के आयात पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी की गणना के लिए इस्तेमाल होने वाले बेस इंपोर्ट प्राइस (आधार आयात मूल्य) को कम कर दिया है। सीबीआईसी ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि सोने के बेस इंपोर्ट प्राइस को 49 डॉलर प्रति 10 ग्राम घटाकर 1,518 डॉलर कर दिया गया है। वहीं, चांदी के बेस इंपोर्ट प्राइस में 870 डॉलर प्रति किलोग्राम की कटौती की गई है, जिससे यह 2,675 डॉलर प्रति किलोग्राम हो गया है। यह नई दरें उन सोने और चांदी पर लागू होंगी जिनका आयात तय टैरिफ हैडिंस के तहत किसी भी रूप में किया जाएगा। इससे आयातकों को कम शुल्क देना होगा।



कैसे मिलेगा फायदा

इस ड्यूटी कटौती का फायदा हार्ड-प्योरिटी गोल्ड बार और कॉइन, साथ ही सिल्वर बुलियन और मेडेलियन पर भी मिलेगा। हालांकि, गहनों, कीमती धातुओं से बनी अन्य वस्तुओं और पोस्ट, कूरियर या बैगेज के जरिए होने वाले आयात पर यह छूट लागू नहीं होगी। भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक है। देश में सोने की लगभग सभी मांग आयात से पूरी करनी होती है। वहीं, चांदी की 80% से अधिक जरूरतें भी विदेशी आपूर्ति पर निर्भर करती हैं। ऐसे में बेस इंपोर्ट प्राइस घटाने से सोना और चांदी के आयातकों पर पड़ने वाला बोझ हल्का होगा।

सोने के गहनों के नियम सरल किए

अब सोने के गहनों पर ड्यूटी-फ्री सीमा से मूल्य आधारित कैप हटा दी गई है, अब केवल वजन आधारित सीमा ही लागू होगी। महिला यात्रियों के लिए 40 ग्राम तक गहने ड्यूटी-फ्री लाने की इजाजत है। वहीं पुरुष और अन्य के लिए 20 ग्राम तक गहने आयात शुल्क से मुक्त रहेंगे। नियम सोने के बाजार मूल्य की परवाह किए बिना लागू होगा। पहले वजन व मूल्य दोनों का सामना करना पड़ता था। महिलाओं के लिए ₹1,00,000 तो पुरुषों के लिए ₹50,000 लिमिट थी।

ये सुविधाएं भी दी

■ लैपटॉप छूट: 18 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक यात्री को एक लैपटॉप पर कोई शुल्क नहीं देना होगा, जो 75,000 रुपए की सीमा से अलग होगा। इससे व्यापारिक और तकनीकी यात्रियों को सुविधा मिलेगी।
■ पालतू जानवर: पालतू जानवरों के साथ यात्रा करने वालों के लिए स्पष्ट ड्यूटी-फ्री प्रावधान किए गए हैं (पशु आयात नियमों के अधीन)।
■ अग्रिम बैगेज डिक्लैरेशन: यात्रियों को ऐप या ई-सेवाओं के माध्यम से लैंडिंग से पहले डिजिटल घोषणा करने की अनुमति है, इससे कस्टम्स क्लियरेंस तेज होगा।

ये बदलाव किए



दुबई भारत

2 यह बड़ी हुई सीमा भारतीय निवासियों, एनआरआई, भारतीय मूल के लोगों और वैध वीजा रखने वाले विदेशी नागरिकों पर लागू होगी।
3 विदेशी पर्यटकों के लिए 75,000 के अलावा अलग से 25,000 रुपए की छूट दी गई है। शर्त यह है कि ये सामान अपने बैगेज में लाए गए हों, निजी इस्तेमाल के हों।

1 हवाई या समुद्री मार्ग से आने वाले यात्रियों के लिए सीमा 75,000 कर दी गई है। सड़क मार्ग से सामान लाने पर ये नियम लागू नहीं होंगे। एयरलाइन कू सदस्यों के लिए सीमा 2,500 रुपए तय की गई है।

पुनरीक्षण की परतें

निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उठ रहे सवालों का सिलसिला थम नहीं रहा है। बिहार से शुरू हुआ विवाद उत्तर प्रदेश से होकर अब पश्चिम बंगाल में केंद्रित हो गया है। पुनरीक्षण प्रक्रिया का मकसद मतदाता सूची से अपात्र लोगों को बाहर करना है, जिनमें स्थान बदलने वाले नागरिक या जिनकी मौत हो चुकी है या फिर गलत तरीके से नाम दर्ज कराने वाले लोग शामिल हो सकते हैं। चुनाव में शुचिता सुनिश्चित करने के लिए इस कवायद को जरूरी माना गया है और इस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी, मगर इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू है पारदर्शिता और निष्पक्षता का। विभिन्न राज्यों में इस प्रक्रिया के तहत मसविदा मतदाता सूची से जितनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम बाहर होने के दावे किए जा रहे हैं, उससे आम नागरिकों के मन में कई तरह की आशंकाएं पैदा हो गई हैं। इससे संबंधित मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए आरोप लगाया कि राज्य के लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि हर समस्या का समाधान होता है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी पात्र व्यक्ति माताधिकार से वंचित न रहे।

गौरतलब है कि पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें सामने आई हैं कि नागरिकों के नाम मनमाने तरीके से मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए और उन्हें इस संबंध में कारणों की जानकारी भी नहीं दी गई। ऐसे में निर्वाचन आयोग की इस प्रक्रिया में मतदाता सूची से बाहर होने वाले लोगों को समय पर सूचित करने और उन्हें अपनी पात्रता साबित करने के पर्याप्त अवसर देने को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। जाहिर है, अगर पुनरीक्षण को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने को प्राथमिकता दी जाती, तो संभवतः अनावश्यक विवाद खड़े नहीं होते। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के संदर्भ में स्पष्ट निर्देश दिया था कि इस पूरी प्रक्रिया में तार्किक विसंगतियों की श्रेणी में रखे गए मतदाताओं का सत्यापन पारदर्शी ढंग से होना चाहिए, ताकि इससे नागरिकों को किसी भी तरह की असुविधा या तनाव न हो।

पश्चिम बंगाल सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में दलील दी कि निर्वाचन आयोग को तार्किक विसंगति सूची में नामों का उल्लेख करने के कारणों को तत्काल सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि संबंधित व्यक्ति यह जान सके कि गड़बड़ कहाँ हुआ है और उसमें अपेक्षित सुधार किया जा सके। दावा किया जा रहा है कि राज्य में नाम, उपनाम या आयु में गड़बड़ी को लेकर अब तक 1.36 करोड़ लोगों को तार्किक विसंगतियों के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इस पर शीर्ष अदालत ने बांग्ला भाषा में बोलचाल का जिन्न करते हुए कहा कि कभी-कभी इसकी वजह से भी नामों की वर्तनी गलत हो जाती है, लेकिन पात्र व्यक्तियों का मतदाता सूची में बने रहना जरूरी है। सवाल है कि विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का जो काम निर्वाचन आयोग को खुद अपने स्तर पर शामिल करना चाहिए था, उस संबंध में न्यायालय को निर्देश देने की जरूरत क्यों पड़ रही है। ऐसे में यह सुनिश्चित करने की नितांत आवश्यकता है कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची से बाहर न हो, ताकि निर्वाचन आयोग पर आम लोगों का भरोसा पूरी तरह कायम रहे।

आभासी खतरे

आनलाइन खेल मनोरंजन का साधन हो सकता है, लेकिन इसके लिए सीमित समय तय करना और आत्मनियंत्रण बेहद जरूरी है। अगर किसी बच्चे या किशोर को इसकी लत लग जाए, तो इसके परिणाम भयावह हो सकते हैं। आज की आभासी दुनिया में ऐसे खेल भी आ गए हैं, जिनमें उपयोगकर्ताओं को जोखिम भरे कार्य दिए जाते हैं। बच्चे इन खेलों की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं, जिससे वे न केवल शारीरिक एवं मानसिक विसंगतियों का शिकार हो जाते हैं, बल्कि कई बार आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ऐसी ही एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहां तीन नाबालिग बहनें मंगलवार देर रात इमारत की नीवीं मंजिल से कूद गईं, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस को प्रारंभिक जांच-पड़ताल में पता चला कि ये तीनों बहनें एक ऐसे आनलाइन खेल की आदी थीं, जिसमें खेल के दौरान कुछ इस तरह के कार्य दिए जाते हैं, जो खतरे से खाली नहीं होते।

इसमें दोराय नहीं कि इंटरनेट और स्मार्ट फोन ने हमारे जीवन को सुविधाजनक बना दिया है, लेकिन तकनीक के इस साधन में कई तरह के खतरे भी छिपे हुए हैं। मोबाइल फोन के अत्यधिक इस्तेमाल से न केवल बच्चों और किशोरों की पढ़ाई प्रभावित होती है, बल्कि उनके व्यवहार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गाजियाबाद में इमारत से कूदकर जान देने वाली लड़कियों के परिवारवाले भी इस बात से चिंतित थे और उनके आनलाइन गेम खेलने पर आपत्ति जताते थे। कहा जा रहा है कि परिवार वालों ने इन तीनों बहनों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी, जिससे वे बेहद निराश थीं। सवाल है कि ऐसे आनलाइन खेलों की अनुमति कैसे दे दी जाती है, जो किसी बच्चे के जीवन को खतरे में डाल दे या फिर उसकी मौत का कारण बन जाए? जाहिर है, इसके पीछे कानून में स्पष्ट दिशा-निर्देशों का अभाव हो सकता है। मगर अभिभावकों की भी यह जिम्मेदारी है कि वे इस तरह के जोखिम को हल्के में न लें और बच्चों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल के दौरान उन पर नियमित नजर रखें।

तकनीक से संचालित ज्ञान के जोखिम

आज के तकनीकी दौर में मशीनी तंत्र हमारी पसंद, जिज्ञासा और यहां तक कि हमारे ज्ञान को भी आकार देने लगा है। बच्चों और युवाओं को लगता है कि वे स्वतंत्र रूप से ज्ञान एवं सूचना खोज रहे हैं, जबकि वास्तविकता इससे कहीं अलग होती है।

मनीष जैसल

आज का समय तकनीक का है और इसका मौन एवं सबसे प्रभावशाली चेहरा है ‘एल्गोरिदम’। यह मशीनी तंत्र हमारी पसंद, जिज्ञासा और यहां तक कि हमारे ‘ज्ञान’ को भी आकार देने लगा है। इंटरनेट की दुनिया में हम जो कुछ देखते हैं, पढ़ते हैं और साझा करते हैं, वह बहुत हद तक उन्हीं गणनात्मक सूत्रों से छनकर आता है, जिन्हें हम न तो देखते हैं, न ही समझ पाते हैं। बीते कुछ वर्षों में स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट के रूप में लोगों के हाथ में एक अभूतपूर्व शक्ति के साथ अदृश्य खतरा भी आया है, जिसने हमारे ज्ञान की धारा को ही बदलना शुरू कर दिया है। युवा और बच्चे आज सूचना के महासागर में डूबे हैं, लेकिन समस्या यह है कि वे अपने हिस्से की जानकारी उसी छोटे-सी जगह में पाते हैं, जिसे तकनीक उनके लिए चुन लेती है। उन्हें लगता है कि वे स्वतंत्र रूप से ज्ञान एवं सूचना खोज रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि वे एक ऐसे डिजिटल गलियारें में चल रहे होते हैं, जिसमें रास्ता किसी और ने तय किया होता है।

सबसे बड़ी चिंता यह है कि नई पीढ़ी इंटरनेट पर दिखाई देने वाली जानकारी को सत्य या वस्तुनिष्ठ मानने लगी है। पहले का समय ऐसा था, जब किसी बात को सही साबित करने के लिए पुस्तकें खंगालनी पड़ती थीं, विशेषज्ञों से संवाद करना पड़ता था या शोधपत्र ढूँढने पड़ते थे। अब गूगल सर्च, यू-ट्यूब वीडियो या रील किसी भी ‘तथ्य’ की खोज के कारगर विकल्प माने जाने लगे हैं। बच्चे यह मानकर चलते हैं कि जो स्क्रीन पर दिख रहा है, वही अंतिम सच है। जबकि स्क्रीन किसी विशेष झुकाव या विपणन के उद्देश्य से वही चीजें दिखा रही होती है, जो उन्हें दिखानी हैं। ईरान में एक ऐसी ही घटना खासी चर्चा में रही है। वहां महामारी के शुरुआती चरण में यह अफवाह फैली थी कि शराब का सेवन शरीर में संबंधित विषाणु को मार देगा। मीडिया रपटों के अनुसार, इस अफवाह की वजह से कई लोगों की विषाक्त मिथाइल-अल्कोहल पीने से मौत हो गई और कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। यह घटना दर्शाती है कि जब गलत जानकारी या सुझाव समाज में व्यापक स्तर पर फैलता है, तो उसका मानव जीवन पर कितना गहरा असर हो सकता है।

दरअसल, सोशल मीडिया के ‘एल्गोरिदम’ इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि वे हमें वही दिखाएं, जो हम पहले से पसंद करते हैं या जिसके समर्थन में हमने पहले कोई संकेत दिया है। यह प्रक्रिया इतनी बार और इतनी सहजता से होती है कि फर्क धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी मुद्दे पर पहली बार कुछ एकतरफा सामग्री देखता है, तो वह मंच भविष्य में उसे उसी तरह की और अधिक सामग्री दिखाने लगता है। देखने वाले को यह भ्रम होने लगता है कि ज्यादातर लोग उसी तरह सोचते होंगे, जैसे उसके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखता है। बच्चों में यह समस्या और गहरी है, क्योंकि उनकी दुनिया नई, संवेदनशील और आसानी से प्रभावित होने वाली होती है। वे तथ्य और राय के फर्क को समझना अभी सीख ही रहे होते हैं। यह समय उनके लिए तर्क, विवेक और विश्लेषण की क्षमता विकसित करने का होता है। मगर वास्तविकता यह है कि आज के डिजिटल मंच बच्चों को विश्लेषण नहीं, बस उपभोग सिखाते हैं। वे

चेतना की पाठशाला

रामानुज पाठक

शिक्षा शब्दों का संचय नहीं, बल्कि चेतना का संस्कार है। जो पढ़ा जाए और जीवन में न उतरे, वह ज्ञान नहीं, केवल सूचना बनकर रह जाता है। मनुष्य का विकास पुस्तकों से कम और अनुभवों से अधिक होता है। इसी गहरे सत्य की अभिव्यक्ति है- ‘पहले अपनाओ, बाद में पढ़ाओ।’ यह कोई भावनात्मक नारा नहीं, बल्कि सीखने की स्वाभाविक, वैज्ञानिक और दार्शनिक प्रक्रिया का संक्षिप्त सूत्र है। जब शिक्षा इस सूत्र से जुड़ती है, तब वह परीक्षा-केंद्रित व्यवस्था से निकलकर जीवन-केंद्रित दृष्टि बन जाती है। मानव मस्तिष्क जन्म से ही सीखने के लिए तत्पर रहता है। वह पहले देखता है, छूता है, सुनता है, गिरता है, संभलता है और फिर शब्दों को अर्थ देता है। शिक्षा पुस्तक पढ़कर चलना नहीं सीखता, बल्कि बार-बार गिरकर सीखता है। आधुनिक तंत्रिका-विज्ञान भी यही सिद्ध करता है कि जब सीखना प्रत्यक्ष अनुभव से जुड़ा होता है, तब मस्तिष्क में बनने वाले तंत्रिका-संबंध अधिक गहरे और स्थायी होते हैं। केवल सुनी या रटी गई जानकारी स्मृति में अल्कालिक होती है, जबकि किया गया कार्य चेतना में स्थायी छाप छोड़ता है।

गहरी दृष्टि से शिक्षा आत्मबोध की प्रक्रिया है। ज्ञान का उद्देश्य केवल बाहरी संसार को समझना नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानना भी है। जो शिक्षा मनुष्य को प्रश्न पूछने की क्षमता नहीं देती, वह उसे उतरों का बोझ ही सौंपती है। जब विद्यार्थी किसी समस्या से स्वयं जुड़ाता है, किसी प्रयोग में असफल होता है और पुनः प्रयास करता है, तब वह केवल विषय नहीं सीखता, बल्कि धैर्य, विवेक और आत्मसंयम भी अर्जित करता है। यही शिक्षा का वास्तविक प्रयोजन है- मनुष्य को भीतर से परिपक्व बनाना।

अध्ययन अनुभव के बाद आता है, ताकि वह जीवन से जुड़ सके। जब विद्यार्थी किसी घटना, प्रयोग या परिस्थिति से होकर गुजर चुका होता है, तब पुस्तक का एक-एक वाक्य अर्थवान हो उठता है। शब्द तब अनुभव की व्याख्या बन जाते हैं। यही कारण है कि पहले अपनाया गया ज्ञान बाद में पढ़े गए सिद्धांतों को गहराई देता है। समकालीन शिक्षा-दृष्टि इस तथ्य को स्वीकार करती है कि प्रत्येक विद्यार्थी समान नहीं होता। किसी की रुचि विज्ञान में होती है, किसी की कला में, किसी की प्रकृति में, तो किसी की समाज में। जब शिक्षा इन भिन्नताओं को नकारती है, तब वह व्यक्ति को भी नकार देती है। अनुभव-प्रधान शिक्षा, शिक्षा को एक सांचे में ढालने के बजाय, मनुष्य के भीतर छिपी संभावनाओं को उद्घाटित करती है। भावनात्मक स्तर पर वह दृष्टि शिक्षा को भय से मुक्त करती है। जब सीखना केवल अंक और परीक्षा का साधन बन जाता है, तब वह तनाव और हीनता को जन्म देता है। इसके विपरीत जब सीखना खोज, प्रयोग और संवाद की प्रक्रिया बनता है, तब आत्मविश्वास स्वतः

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com



लंबे लेख पढ़ने की बजाय रोल्स और छोटे वीडियो पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। उनकी धैर्यशीलता कम होती जाती है और वे ‘तेज जवाब’ तथा ‘तुरंत ज्ञान’ के आदी हो जाते हैं। यह ज्ञान अर्जित करना नहीं, बल्कि सूचना की लत है और दोनों में फर्क को समझना बेहद जरूरी है।

सोशल मीडिया अब वैचारिक मंच नहीं, बल्कि हमारी सोच, पसंद और राय को आकार देने वाली शक्ति बन चुका है। सूचना के इस प्रवाह में खब और भ्रम तथा तथ्य और अफवाह के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। यह परिदृश्य हमें केवल आंकड़ों से नहीं, बल्कि इस चेतावनी से भी अवगत कराता है कि मीडिया साक्षरता, आलोचनात्मक विवेक और तथ्य-जांच के बिना यह डिजिटल शक्ति समाज को सशक्त करने के बजाय दिशाहीन भी कर सकती है। ऐसे दौर में आवश्यक है कि हम ‘डिजिटल साक्षरता’ को सिर्फ कंप्यूटर चलाने की क्षमता न मानें, बल्कि इसे तथ्य की सत्यता को परखने की क्षमता से जोड़ें। स्कूलों में बच्चों को यह सिखाया जाना चाहिए कि इंटरनेट पर दिखने वाला हर वीडियो ज्ञान नहीं होता और हर खोज का नतीजा सही नहीं होता। उन्हें यह भी समझना होगा कि किसी विषय पर अलग-अलग दृष्टिकोण रखना क्यों जरूरी है।

युवा पीढ़ी में भी यह जागरूकता पैदा करने की जरूरत है कि उनकी सूचना का रास्ता उनके हाथ में नहीं होता, बल्कि किसी मशीन द्वारा नियंत्रित होता है। यह स्वीकार करना ही पहला कदम है। दूसरा कदम है उस नियंत्रण से बाहर निकलने की कोशिश करना। इसका अर्थ यह है कि हम विविध स्रोतों को पढ़ें, अलग-अलग विचार सुनें, किताबों और पत्रिकाओं की ओर लौटें, विशेषज्ञों से संवाद करें और सबसे बढ़कर यह समझें कि ‘ज्ञान’ और ‘सूचना’ दो अलग-अलग चीजें हैं। स्क्रीन के उस पार मौजूद दुनिया जितनी आकर्षक है, उतनी ही भ्रामक भी है। ज्ञान की खोज एक यात्रा है, जो धीमी, गहरी और निरंतर चलती है। यदि हमने यह संतुलन नहीं सीखा, तो तकनीक हमारे लिए एक साधन नहीं, बल्कि हमारी सोच को नियंत्रित करने वाली ताकत बनकर रह जाएगी।

संतुलन की दिशा

उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों पर रोक लगाया केवल एक कानूनी हस्तक्षेप नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन और शैक्षणिक वातावरण की रक्षा की दिशा में एक अहम कदम है। न्यायालय ने प्रथमदृष्टया यह माना कि नियमों की भाषा अस्पष्ट है और उनकी व्याख्या अलग-अलग ढंग से की जा सकती है, जिससे न केवल उनका दुरुपयोग संभव है, बल्कि शिक्षा संस्थानों में अविश्वस, भय और टकराव का माहौल भी बन सकता है। उच्च शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान, शोध, नवाचार और समान अवसर उपलब्ध कराना है, लेकिन नियम ऐसे हों जो असहमति या प्रशासनिक निर्णय को सीधे जातीय भेदभाव के दायरे में ले आएँ, तो इससे शिक्षकों और छात्रों के बीच संवाद के बजाय संदेह की दीवार खड़ी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भेदभाव को केवल जाति के चश्मे से देखना समस्या के समाधान के बजाय उसे और जटिल बना सकता है, क्योंकि शिक्षा संस्थानों में भेदभाव के कई रूप हो सकते हैं।

- *विभूति बुपव्या, दिल्ली*

समावेशी बजट

वर्तमान समय में पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची हुई है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने के लिए समावेशी बजट पेश किया है। यह वित्तीय विश्वसनीयता बनाए रखने और सुधारों की रफ्तार को जारी रखने की कोशिश है। इस बार बजट में न तो कोई चौंकाने वाले एलान थे, न आयकर दरों में कोई छूट। सरकार ने रोजगार का सृजन करने तथा उत्पादकता और विकास की गति तेज करने की दिशा में कई आर्थिक सुधार किए हैं। इस बजट के जरिए कैसर जैसी गंभीर बीमारियों से जुड़ा रोग-मरीजों और उनके परिवारों पर इलाज के खर्च के बोझ को कुछ कम करने की कोशिश की गई है। कैसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 जीवनरक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा प्रत्येक जिले में लड़कियों के लिए छात्रावास के निर्माण की घोषणा भी महत्वपूर्ण है।

- *गुलग किशोर राही, छपरा*

स्वास्थ्य की गरिमा

सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्कूलों में छात्राओं को निशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने और मासिक धर्म स्वच्छता को अनिवार्य करने संबंधी निर्देश छात्राओं के लिए एक नई सुबह की तरह है। यह दुखद ही है कि आज भी मासिक धर्म को संकोच, चुप्पी और उपेक्षा के साथ देखा जाता है। अब अदालत ने साफ कह दिया है कि मासिक धर्म कोई बोझ नहीं, बल्कि स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार है। यह भी कहा है कि

सेहत और सतर्कता

विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रपट के अनुसार, देश में कैसर के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ समय पहले भारत में कैसर के ग्यारह लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए। यह स्थिति चिंताजनक है। अगर इसको लेकर जल्द गंभीरता नहीं दिखाई गई, तो यह देश के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। यह ऐसी बीमारी है, जिसके बारे में कई बार लोगों को तब पता चलता है, जब यह व्यक्ति की मौत के करीब ले आती है। जो लोग समय-समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच कराते रहते हैं, उन्हें शुरुआती दौर में कैसर के संबंध में जानकारी मिल जाती है और वे समय पर इलाज शुरू करा देते हैं। वैसे तो कैसर की चपेट में आने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हम अपना खानपान और जीवनशैली सुधार लें, तो जोखिम को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है।

- *राजेश कुमार चौहान, जलंधर*

प्रेरणा

हमेशा खुश रहना ही सौंदर्य बढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। - चार्ल्स डिकेंस

संपादकीय

कानून ऐसे हों, जो धरातल पर अमल में लाए जा सकें

शिक्षा और खाद्य सुरक्षा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अलग-अलग समय और रातों से मौलिक अधिकार तो बने लेकिन क्या इनका वास्तविक लाभ आम नागरिकों को मिला? शिक्षा महंगी और निजी हाथों में जाती रही जबकि खाद्य सुरक्षा कुछ किलो मुक्त अनाज तक सीमित हो गई। वर्तमान सरकार मनरेगा के बाद इन दोनों कानूनों में बदलाव लाकर इन्हें समयबद्ध तरीके से अमल में लाना चाहती है। हल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सामनात स्कूलों से शुरू होती है। कोर्ट के एक फैसले के बाद ही 2002 में संविधान संशोधन करके शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए अनुच्छेद 21(अ) जोड़ा गया और 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून आया। खाद्य सुरक्षा को भी कोर्ट ने जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग माना और यूएफए सरकार ने 2013 में इसे कानूनी जामा पहनाया। लेकिन क्या वास्तव में एक गरीब का बच्चा आज वही शिक्षा पा रहा है, जो किसी उच्च वर्ग के बच्चे को मिल रही है? क्या यह सच नहीं कि आज भी कुपोषण देश के लिए बड़ी समस्या है और केवल मुक्त अनाज इसका हल नहीं है? सरकार का मानना है कि इन कानूनों में बदलाव करके इन्हें सबके लिए सुलभ करने का समयबद्ध खाका होना चाहिए। दूसरा, क्रियान्वयन की रियल टाइम मॉनिटरिंग डिजिटल प्रक्रिया से हो। और तीसरा, योजना भूले सबके लिए हो लेकिन उससे लाभान्वित होने वाले लोगों को प्राथमिकता से चिह्नित किया जाए। कानून ऐसे होने चाहिए, जिन्हें अमल में लाना राज्यसत्ता के लिए बाध्यकारी हो।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता

humarehnanuman@gmail.com



साथ भोजन करने से शांति व प्रेम का माहौल बनता है

जीवन में अशांति आने के अनेक रास्ते हैं, पर शांति के मार्ग सीमित हैं। उनमें से एक है- भोजन। अन्न भी हमें बहुत शांति पहुंचा सकता है। भोजन का संबंध तीन बातों से है- बनाना, परोसना, खाना। और यदि ये ठीक हों तो पचाना आसान है। अन्न की ये तीनों प्रक्रियाएं मनुष्य को शांत कर सकती हैं। अब तो मनोवैज्ञानिकों ने भी मान लिया है कि साथ बैठकर जो लोग भोजन करते हैं, उनके परिवारों में शांति और प्रेम का वातावरण बनता ही है। नए प्रयोग इस बात के हो रहे हैं- जिसको केल बीहंग शू कुर्किए कहते हैं- कि यदि कोई एक-दो सदस्य भोजन बना रहे हों तो दो-चार को और उसमें जुट जाना चाहिए। बनते हुए भोजन को जितने स्थानों का साथ मिलेगा, भोजन में उतना ही आनंद आएगा। आज एकल खाने की वृत्ति बढ़ गई है। लेकिन सिंगल डाय्नर्स आगे जाकर अपने को अशांत पाएंगे। हमारे यहां सभी धार्मिक अनुष्ठानों में इसीलिए अन्न का बड़ा महत्व बताया है। वैसे आजकल अनुष्ठानों की बनावट बढ़ी जटिल है और आयोजनों की सजकट कुटिल है। ऐसे में कम से कम घर में तो अन्न देवता का मान करें।

•Facebook:Pt. Vijayashankar Mehta

पाठकों के पत्र

दीर्घकालिक सुधारों पर जोर

बजट में विकास, कल्याण और वित्तीय अनुशासन को महत्व दिया गया है। आखर स्तैब में बदलाव नहीं होने से धारणा बनी है कि वेतनभोगियों को राहत नहीं दी गई। किसानों को भी एमएसपी और प्रत्यक्ष आय सहायता में बढ़ोतरी की उम्मीद थी। लेकिन बजट में तात्कालिक राहत के बजाय संरचनात्मक सुधारों पर जोर रहा है। आलोचकों के अनुसार बजट दीर्घकालिक विकास की दिशा में है, लेकिन अल्पकालिक आकांक्षाओं को संबोधित नहीं कर पाया। -समीक्षा मिश्रा, जम्मू

बच्चों में बढ़ रही हिंसक प्रवृत्ति

इंटरनेट का बढ़ता उपयोग आज बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति और असामाजिकता को बढ़ावा दे रहा है। किशोर गंभीर अपराधों में लिप्त पाए जा रहे हैं। संयुक्त परिवारों का अभाव और अकेलापन भी इस समस्या का प्रमुख कारण है। अमेरिका में अभिभावकों को लेकर किए गए एक अध्ययन में 77 फीसदी पैरेंट्स ने कहा कि स्कूलों में शैक्षणिक कौशल के साथ ही बच्चों को चरित्र निर्माण की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। -साजिद अली, इंदौर, मध्य प्रदेश

नौकरी न मिलने से निराश हो रहे अभ्यर्थी

कई स्टूडेंट्स सालों से कॉम्पीटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, लेकिन नौकरी न मिलने से निराश हैं। महानगरों में ये विद्यार्थी होस्टल या कमरों में रहते हैं। गांव के इलाकों के पैरेंट्स हर महीने इन्हें पैसे भेजते हैं, लेकिन अगर कई सालों तक परिश्रम देते के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती तो वे क्या करें? कई अभ्यर्थी तो अपने सपने छोड़कर निजी कंपनियों में काम करने लगे हैं। -प्र.मु.काळे, नासिक, महाराष्ट्र

परिवारवाद पर दोहरा मानदंड क्यों?

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की विमान हदसे में मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना तो ठीक है। लेकिन क्या यह परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देता? प्रधानमंत्री अक्सर कांग्रेस पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं। मुख्य विपक्षी दल को खूब कोसा भी जाता है। लेकिन यही काम उनकी सरकार का सहयोगी दल करता है तो सब ठीक है। ऐसा दोहरा मानदंड क्यों? -अनिल तलवाड़, लुधियाना, पंजाब

आप अपने पत्र editpage@dbcorp.in पर भेज सकते हैं

क्या आप जानते हैं

जापान के शिनजुकु स्टेशन से रोजाना गुजरते हैं 38 लाख यात्री

जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित शिनजुकु रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन से होकर रोजाना औसतन 35 से 38 लाख लोगों का आवागमन होता है। यह मेट्रो, शहरी रेल और उपनगरीय रेल सेवा का हब है। जमीन के ऊपर और नीचे 5 से 8 तलों में स्टेशन संबंधी कार्यालय, प्लेटफॉर्म, मॉल और भूमिगत पैदल मार्ग बने हुए हैं, जिससे यह स्टेशन एक पूरे शहर जैसा प्रतीत होता है। 2022 में इसे विश्व के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया।

200 दरवाजे यात्रियों के आने-जाने के लिए बने हैं
शिनजुकु स्टेशन पर। यहां **36 प्लेटफॉर्मों** से ट्रेनें संचालित होती हैं।

विश्लेषण • अप्रैल-मई में तमिलनाडु में होने जा रहे चुनाव राष्ट्रीय राजनीति के लिए मायने रखते हैं

दक्षिण की राजनीति पर भी नजर बनाए रखें



सियासत

शीला भट्ट

वरिष्ठ पत्रकार

sheelabhattach@gmail.com

तमिलनाडु में क्षेत्रीय राजनीति का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, जो राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करेगा। जानकारों का मानना है कि दशकों बाद तमिलनाडु में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। उससे भी बड़ा अचम्भा ये है कि वहां इस बार त्रिशंकु विधानसभा की संभावनाएं भी बन रही हैं। दक्षिण भारत के इस महत्वपूर्ण राज्य में राजनीति के मूलभूत आयाम बदल रहे हैं। इस बार के चुनाव सिर्फ हिंदी बनाम तमिल और उत्तर विरुद्ध दक्षिण के ही नहीं हैं। ये चुनाव सिर्फ तमिल संस्कृति की रक्षा वाले भी नहीं होंगे। ये तमिलनाडु के मिजाज को बदलने वाले होंगे। अभी इस बाजी में पूरे पते खुले नहीं हैं। लेकिन मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है।

विधानसभा की 234 सीटों में सत्तारूढ़ द्रमुक के पास 133 सीटें हैं। द्रमुक मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के खिलाफ अन्य सभी दल कुछ न कुछ ऐसा मोर्चा बांध रहे हैं कि इस बार का चुनाव उन सभी के लिए संपूर्णतः द्रमुक को हराने का चुनाव बन गया है। वैसे तो तमिलनाडु में कई साल से द्रमुक के सामने अन्नाद्रमुक मैदान में होती है। मुकाबला इन दो द्रविड़-पार्टियों में ही होता रहा है। पर्सनैलिटी-कण्ट आधारित राजनीति तमिलनाडु की पहचान रही है। अन्नादुरै, एमजी रामचंद्रन, करुणानिधि और जयललिता जैसे महारथियों को तमिल जनता ने अवर्णनीय श्रद्धा से अपना बनाया था।

लेकिन आज तमिलनाडु में उनके बराबर का कोई स्थापित नेता नहीं है। ऐसा नेता जो अपने पक्ष से भी बड़ा हो और तमिल संस्कृति का रूआबदार संरक्षक भी हो। खासकर जयललिता के बाद अन्नाद्रमुक के पास उनके कद का कोई दिग्गज नेता नहीं रह गया है और पार्टी के सीनियर नेताओं में मतभेद बहुत बढ़ गया है।

नजरिया • मुद्दा हवा, पानी, भोजन, दवा का

विकसित भारत के केंद्र में

इकोनॉमी तो है, पर इंसान?



देश-समाज

मुकेश माथुर

दैनिक भास्कर

X @mukesh1275

शून्य से शिखर तक पहुंचने वाला एक व्यक्ति अपना 'विकास' कैसे मनेगा? पैसे, पद, प्रतिष्ठा को या अच्छी गुणवत्ता वाले जीवन-स्तर, बौद्धिक विकास, मन की शांति और खुशी को? इससे भी आगे, अपने दायरे में आने वाले लोगों की जिंदगियां बेहतर करने को? शायद इस सभी को, लेकिन सिर्फ बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी विकास नहीं हो सकता।

2047 में विकसित देश बनने से हमारे देश को कोई नहीं रोक सकता। ट्रम्प का टैरिफ की नहीं। अब हमारे पास 'मां' भी है। मदर ऑफ ऑल डीलस। सवाल इतना-सा है कि विकसित होते देश की हवा ज़हरीली, पानी मृत्यु देने वाला, भोजन कैन्सर कोशिकाएं बनाने वाला और दमश्चिां मीत के और करीब ले जाने वाली (नकली) कैसे हो सकती हैं? क्या हमारे विकास मॉडल के केंद्र में इकोनॉमी तो होगी मगर इंसान न होगा? विकसित बन किसके लिए रहे हैं? दुनिया को दिखाने के लिए या अपनी को आगे ले जाने के लिए?

दुनिया को तो बुलंदी से बढ़ता भारत दिख ही रहा है। लेकिन दुनिया को यह भी दिख रहा है कि भारत में निवेश करने जाएंगे तो दिल्ली में लैंड करते ही फेफड़े लड़खड़ाने लगेंगे, सांस उखड़ने लगेंगी। विश्व बैंक की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर साल 17 लाख लोगों की मौत प्रदूषण से होती है।

क्या सरकार ने तय किया है कि हम किस तरह के विकसित देश बनना चाहते हैं? अमेरिका जैसे, जो इंसान छोड़ इकोनॉमी को केंद्र में मान चुका है? सुनते तो है कि अमेरिका में एक भी असामान्य मौत हो जाए तो वह जमीन-आसमान एक कर देता है। लेकिन मिनिशोपैरिस में एक व्यक्ति को फेडरल एजेंटों ने दूध गोली मार दी, महिला को गाड़ी में शूट कर दिया। ट्रम्प सुरक्षा बल के पक्ष में ही खड़े हो गए जबकि पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। दुनिया पर मममानी करते आए इस देश में 2021 के बाद से आम आदमी का जीवन-स्तर और क्रय-शक्ति गिरते चले गए। एक

उसके कारण द्रमुक के खिलाफ बन रहे माहौल का वो सही लाभ उठा नहीं पा रही है।

भाजपा- जो द्रविड़ भूमि में अपनी जड़ें डालने की कोशिश कर रही है- के पास भी न करिश्माई नेता हैं, न द्रविड़ रणनीति समझने वाले तमिलभाषी महारथी हैं। शायद उनको ऐसा व्यक्तित्व चाहिए भी नहीं, जिसका कद पार्टी और उसकी विचारधारा से बड़ा हो। भाजपा इस चुनाव में सिर्फ एक ही मकसद से लड़ रही है- कुछ भी हो जाए द्रमुक को हराना है। तमिलनाडु में कांग्रेस पूरी तरह से द्रमुक की छाया में ही पनपती रही है। वो लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु से नौ सीटें जीत पाई थी। अगर द्रमुक तमिलनाडु में हारती है तो केंद्र में कांग्रेस की आज जो स्थिति है, वह उससे भी ज्यादा निर्बल हो जाएगी। द्रमुक के पास लोकसभा में 22 सांसद हैं। मोदी सरकार का वो हर मुद्दे पर पुरजोर विरोध करते हैं। आज देश में भाजपा विरोधी दो मजबूत गढ़ हैं- एक ममता बनर्जी का बंगाल में और एक स्टालिन का तमिलनाडु में।

तमिलनाडु में भाजपा का संगठन ऐसा नहीं है, जो द्रमुक की बराबरी कर सके। ये भी सही है कि 2026 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव भाजपा के नेतृत्व में लड़ा जाने वाला चुनाव भी नहीं है। इस चुनाव में अभित शाह प्रमुख रणनीतिकार हैं, जो द्रमुक के सामने एक प्रभावशाली गठजोड़ खड़ा करने में कुछ सफल हुए हैं। अप्रैल 2025 में भाजपा और अन्नाद्रमुक ने तमिलनाडु चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन बनाया था। पिछले तीन महीनों में अभित शाह और प्रभारी पीयूष गोयल ने गौडर से लेकर वाणीथार जाति को समझा-बुझाकर एनडीए के साथ जोड़ा है। इधर पिछले दो सालों से द्रमुक का प्रचार भी प्रमुख रूप से भाजपा की विचारधारा के खिलाफ का रहा है। स्टालिन ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने बेटे उदयनिधि को आगे किया है। आज द्रमुक की भाजपा विरोधी राजनीति के मुख्य प्रचारक उदयनिधि ही हैं।

स्टालिन कई मुसीबत से घिरे हुए हैं। गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप, बेटे उदयनिधि को अपना वारिस बनाने का संकल्प और राज्य में बिगड़ती हुई कानून-व्यवस्था



द्रविड़ राजनीति में उभर रहा है एक नया त्रिकोणीय संघर्ष

वैसे तो तमिलनाडु में कई साल से द्रमुक के सामने अन्नाद्रमुक मैदान में होती है। मुकाबला इन दो द्रविड़-पार्टियों में ही होता है। लेकिन आज इनके पास लोकप्रिय नेता नहीं हैं। विजय से उन्हें कड़ी चुनौती मिल रही है। भाजपा-कांग्रेस की नजरें इन समीकरणों पर हैं।

द्रमुक के खिलाफ एक माहौल पैदा कर रही है। बदलती जमीनी हकूकत के कारण इस बार द्रमुक की साथी रही कांग्रेस भी हिम्मत दिखाकर द्रमुक से अलग चुनाव लड़ने का सोच रही है। पर ऐसा होने की संभावना काफी कम है।

लेकिन तमिलनाडु का चुनाव अगर अभूतपूर्व बनने जा रहा है तो उसका कारण न तो स्टालिन है, ना ही विपक्ष के नेता पलानीस्वामी (ईपीएस)। वास्तव में तमिल सुपरस्टार विजय ने सबको हिलाकर रख दिया है। कई सर्वे आ गए हैं, जिनमें विजय को लगभग 25% लोग पसंद कर रहे हैं। अगर ये लोग विजय की टीवीके- तमिलमा वेन्री कषगाम- पार्टी को वोट भी दे देंगे तो चुनाव नतीजों का कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगा सकता है।

कांग्रेस में तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो सोच रहे हैं

दूरदृष्टि • एआई हमसे श्रम की अस्मिता छीन रहा

काम करने का प्रश्न मनुष्य के अस्तित्व की गरिमा से जुड़ा है



एआई

पीटर कर्षलेगर

प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में

ल्यूसेर्न और डायरेक्टर

जिसे हम आमतौर पर एआई कहते हैं, वह वास्तव में डेटा-बेस्ड सिस्टम्स (डीएस) का एक सेट है। ये तकनीकें इंसानी जीवन के हर पहलू को बदल रही हैं। नए बिजनेस मॉडल बढ़ा रही हैं और समूची अर्थव्यवस्थाओं को नए सिरे से गढ़ रही हैं। समय के साथ ये नई नैकरियां पैदा करने, उत्पादकता बढ़ाने और कॉन्फिंटिव क्षमताएं बढ़ाने का वादा करती हैं।

लेकिन इन फायदों के साथ ही डिजिटल क्रांति और डीएस का यह प्रसार श्रम बाजार, शिक्षा और प्रोफेशनल ट्रेनिंग को बाधित भी कर रहा है। परिणाम सफ़ दिखने लगे हैं- एल्गोरिदम-आधारित प्लेटफॉर्मों द्वारा तैयार जोखिमपूर्ण कार्य-स्थितियां, घटती मजदूरी और अर्थव्यवस्था की जरूरतों व कामगारों के प्रशिक्षण के बीच बढ़ता असंतुलन। इस सब से यह बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि क्या एआई का बढ़ता इस्तेमाल वेतन या मजदूरी वाले पेशेवर काम को अप्रासंगिक कर देगा? हमें अक्सर बताया जाता है कि तकनीकी छलांग ने हर बार बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की आशंकाएं पैदा कीं और हर बार ये गलत ही साबित हुईं। लेकिन ये ऐतिहासिक ट्रेन्ड अब शाश्वद काम न करे।

मोटे तौर पर अतीत की तकनीकें मानव श्रम को अधिक कुशल या शारीरिक रूप से कम मेहनत वाला बनाने के लिए विकसित हुई थीं। इसके उलट, एआई इंसान को वैल्यू-चेन से हटा देने पर आमादा है। पिछली तकनीकी क्रांतियों के विपरीत एआई सिस्टम्स महज सामान्य या कम-कौशल वाले कामों तक सीमित नहीं हैं। ये उन क्षेत्रों में भी बढ़ रहे हैं, जो कभी मानवीय विशिष्टता में शामिल थे, जैसे चिकित्सा और सर्जरी, कानूनी विश्लेषण या रचनात्मक सृजन।

आज एआई के विस्तार और गति से उस भरोसे को चुनौती मिल रही है कि तकनीकी इन्वेंशंस हमेशा जितनी नौकरियां खत्म करते हैं, उससे अधिक पैदा करते हैं। वस्तुतः ऐसा कोई ऐतिहासिक नियम है ही नहीं, जो यह गारंटी देता हो कि तकनीकी बदलाव अनिवार्य रूप से इंसानों के लिए अधिक पेड़-वर्क पैदा करेगा। इसके

कि अगर विजय उनके साथ आने को राजी हो जाएं तो द्रमुक को 20 सीट मिलनी भी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन विजय किसी के हाथ आसानी से आने वाले नहीं हैं। उसके पास गजब का कॉन्फिडेंस है। खूब पैसा भी है। आज के दिन में वो सबसे पॉपुलर सुपरस्टार हैं। वो दूसरे पक्ष के नेताओं को जल्दी से मिलते नहीं हैं। घटनाओं पर जल्दी प्रतिक्रिया भी नहीं देते हैं। पूरे तमिलनाडु में लड़ाने के लिए उसके पास पर्याप्त उम्मीदवार नहीं हैं। लेकिन लोगों में बिगड़ती हुई परिस्थिति के कारण इतना गुस्सा है कि वो अपनी आशा विजय के साथ बांध रहे हैं। विजय के पीछे दलित, महिलाओं और युवा वर्ग का समर्थन है।

वास्तव में लोग दोनों द्रविड़ दलों से इतने थक चुके हैं कि जो चुनाव द्रमुक के खिलाफ का था, वो मतदान का दिन आते-आते विजय को जिताने का माहौल बना दे तो अचरज नहीं होना चाहिए। द्रमुक के नेता विजय की भरपूर टीका करते हैं कि वो भाजपा के खिलाफ कोई खास बयान नहीं देते। सेंसर बोर्ड ने उनकी महंगी फिल्म रोक रखी है, फिर भी वो भाजपा के खिलाफ बोल नहीं पाए। इस कारण से अफवाहों का बाजार भी गर्म है कि कहीं द्रमुक के खिलाफ भाजपा खेल तो नहीं खेल रही है? जो लगातार सर्वे हो रहे हैं, वो सब को उलझान में डालने के लिए काफी हैं। जानकार लोग ये भी कहते हैं कि विजय द्रमुक और अन्नाद्रमुक दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे। वस स्थिति में द्रमुक मामूली अंतर से भी चुनाव जीतने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि विजय की एंट्री से द्रमुक-विरोधी वोटों का बंटवारा होने की संभावना है। वहीं भाजपा कोशिश करेगी कि तमिलनाडु में त्रिशंकु विधानसभा हो जाए, जिसमें भाजपा भी सरकार बनाने या चलाने में एनडीए के तहत कोई भूमिका अदा कर सके।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)



इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए QR कोड को स्कैन करें।

विपरीत, सामने आ रहे प्रमाण बताते हैं कि जिस गति से नई नौकरियां पैदा हो रही हैं, उससे कहीं ज्यादा तेजी से एआई पूरे के पूरे पेशों को ही समाप्त कर रहा है।

क्योंकि मनीएर कि काम का कम समय और अधिक प्री-टाइम जरूरी तौर पर बुग नहीं। अत्यधिक श्रम से मुक्त कोई समाज अधिक रचनात्मक हो सकता है। खतरा काम खत्म होने से नहीं, बल्कि इसके साथ समाप्त होने वाली चीजों से है। जैसे, वेतन, जनहित में काम आने वाला टैक्स-आधार और रोजगार से मिलने वाली पहचान, प्रोजेन-भावना, अस्मिता और साथ काम करने वाले लोगों के बीच का सीहंदा।

जब आर्थिक मूल्य पैदा करने के लिए कम से कम लोगों की जरूरत होगी तो नीति-निर्माताओं को श्रम बाजार पर एआई का असर स्वीकारना ही होगा। ऐसे में दब पर देशों की वो प्रतिक्रद्धता है, जिसमें अधिक से अधिक रोजगार पैदा करने पर जोर होता है। अस्तित्व खो

एआई के विस्तार और गति से इस भरोसे को चुनौती मिल रही है कि तकनीकी इन्वेंशंस हमेशा जितनी नौकरियां खत्म करते हैं, उससे अधिक पैदा करते हैं। इसके उलट आज एआई पूरे के पूरे पेशों को ही खत्म कर रहा है।

चुके किसी जॉब-मार्केट के प्रति लोगों को कुशल होने के लिए कहना इन बदलावों के लिए ऐसे व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराना होगा, जिन्का उन पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। जबकि जरूरत ऐसे पॉलिसी फ्रेमवर्क की है, जो इस बदलाव की व्यापकता के अनुरूप हो।

ऐसे में हमें 'सोसाइटी, आंत्रोपेनोरिषप और रिसर्च-टाइम' (एसईआरटी) मॉडल को अपनाना होगा, जो आय को काम से पृथक करता है, लेकिन बिना शर्त नहीं। इसका उद्देश्य रिक्तपूर्ण जीवन और मानवीयकियों के साथ मानवीय अस्तित्व की आवश्यकताएं पूरा करना है। लेकिन अगर दुनिया ने बिना किसी सामूहिक प्रतिक्रिया के एआई को मानव श्रम को विस्थापित करने दिया तो यह असमानता और-अन्यथ बढ़ाएगा। इससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगी और सामाजिक ताना-बाना कमजोर होगा।

(@प्रोजेक्ट सिंडिकेट)

असुविधा की वापसी का विचार लोकप्रिय हो रहा है

एक विलक पर ही सब मिल जाएगा तो व्यक्तित्व कैसे निखरेगा?

maxxing) के नए विचार को भी जन्म दिया है, जो हमारी दिनचर्या में 'असुविधा' की वापसी की वकालत करता है। यह शरीर को चलाने और प्रचलशीलता के महत्व के तर्कों को सामने रखता है। ये कहता है कि घर बैठकर खाना मंगवाने के बजाय घर से बाहर निकलना, ट्रैफिक का सामना करना और खाना ऑर्डर करने के बाद उसकी प्रतीक्षा करना हम में कैय और ऐसे माहौल में रहने की क्षमता को विकसित करता है, जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं। क्योंकि खुद को मुश्किल स्थितियों में डालना हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। इससे हासिल होने वाली मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास हमें बात-बात पर निराश होने से बचाता है और हमें बताता है कि जीवन कोई ईस्टा या मेटा का प्लेटफार्म नहीं, एक सघन वास्तविकता है। आखिर यह 'फ्रिक्शन' ही है, जो फिजिक्स की भाषा में व्यक्ति को गिरने से बचाता है और हर चड़ी सतर्क भी रखता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

डिफ्रैक्ट एंगल • ‘फ्रिक्शन-मैक्सिंग’ यानी दिनचर्या में असुविधा का विचार लोकप्रिय हो रहा है



युवामन

नन्दिتهश निलय

वक्ता, एथिक्स प्रशिक्षक एवं लेखक

nanditeshnilay@gmail.com

आपने ध्यान दिया है कि एक तरफ जहाँ सारी दुनिया पूरी ऊर्जा के साथ स्क्रीन पर आलोकित होती रहती है; वहीं दूसरी तरफ हमारी युवा पीढ़ी पर एक कभी न खत्म होने वाली सुस्ती भी छाई रहती है। बेड शीट झाड़ना, दो कदम चलकर पानी का गिलास उठाना, किताबों को सहेजना, किसी का हालचाल पूछना, अपने कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जाना- ये सब उनके लिए बहुत दुर्गह कार्य बन जाते हैं। बिस्तर पर पड़ना, वहाँ पर खाना और साथ-साथ लगातार फोन देखते रहना ही उन्हें सही और उपयोगी नजर आने लगता है। स्क्रीन टाइम के अलावा बाकी सारे कार्य अनिच्छा से भर जाते हैं।

इस पीढ़ी में जितनी ऊर्जा अनवरत फोन देखने और

एक विलक पर सामान मंगाने के लिए है, वैसी घर से बाहर निकलकर टहलने या लाइब्रेरी तक पहुंचने के लिए क्यों नहीं नजर आती है? 'टेक-ब्रोब' कहलाने वाली यह पीढ़ी हजार बातों में अपने माता-पिता से सहमत नहीं होती। तुरंत प्रतिक्रिया देना इनके लिए आम है। अपनी सोच को लेकर ये बहुत पर्जेंसिव होते हैं और उन लोगों को बिलकुल पसंद नहीं करते, जो उनके कम्पर्ट जेन को तोड़ना या उन्हें कुछ सिखाना या समझाना चाहते हैं।

सिलिकॉन वैली में मशहूर 'तेजी से आगे बढ़ो' का मंत्र इस नई पीढ़ी को अक्सर नैतिक गलतियों और अनचाहे नतीजों की ओर ले जाता है। इस पीढ़ी को इन्वेंशन और विजन के लिए सराह जाता है, लेकिन जोखिम लेने को लेकर उनका लापरवाह रवैया समाज को नुकसान भी पहुंचा सकता है। यह डेटा-प्रब्रवेसी के उल्लंघन और एल्गोरिदम में भेदभाव के मामलों में देखा भी गया है।

अगर हम इस पीढ़ी को उनके माता-पिता की नजरों से देखें तो वे उन्हें लगातार गैजेट्स से दूर रखने की कोशिश

करते पाए जाते हैं। उनके लिए अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास मायने रखता है, जबकि 'टेक-ब्रोब' के लिए, तकनीक, दक्षता और कम्पर्ट जेन ही लक्ष्य होता है। और शायद यही कारण है कि जिस बात पर वे सबसे ज्यादा असहमत होते हैं, या जिस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं; वह है मेहनत का महत्व।

उनके माता-पिता का मानना होता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सभी को अपने कम्पर्ट जेन से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन 'टेक-ब्रोब' के लिए तो पूरी दुनिया एक विलक पर मौजूद है, फिर मेहनत क्या करना! श्रम तो निम्न वर्ग के हिस्से गया है। वो भला फोन छोड़ मेहनत का दामन क्यों थामें! तकनीक की दुनिया ने उन्हें एक ऐसा सपनीला संसार दिया है, जहां उनकी हर 'असुविधा' को खत्म कर दिया गया है। सबकुछ इंस्टैंट डिलीवर हो जाता है। अब तो सोचने का काम भी बुद्धिमान चैटबॉट्स को आउटसोर्स कर दिया गया है।

लेकिन इसी ने 'फ्रिक्शन-मैक्सिंग' (Friction-

बिज़नेस ब्रीफ

टाटा पावर का मुनाफा 25% घटा, ₹772 करोड़

मुंबई | टाटा पावर ने वित्त वर्ष 2026 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए 772 करोड़ रुपए का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया। यह पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के 1,031 करोड़ रुपए से 25% की सालाना गिरावट है। कंपनी का परिचालन राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 9% घटकर 13,948 करोड़ रुपए रह गया। कुल खर्च 6% घटकर 13,465 करोड़ रुपए रहे।

इले. कंपोनेंट में 11,000 करोड़ का निवेश आएका नई दिल्ली | इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैनुफैक्चरिंग स्क्रीम के तहत 5 से 7 नए आवेदनों को मंजूरी दे सकता है। इन परियोजनाओं में करीब 11,150 करोड़ रुपए का कुल निवेश होने की संभावना है। इन इकाइयों से करीब 29,000 करोड़ रुपए का उत्पादन हो सकता है।

जनवरी में सर्विसेज पीएमआई बढ़कर 58.5

नई दिल्ली | जनवरी में देश का सर्विसेज पीएमआई दिसंबर 2025 के 58.0 से मामूली बढ़कर 58.5 हो गया। मजबूत मांग, नए कारोबार में बढ़ोतरी और तकनीकी निवेश से वृद्धि मजबूत बनी रही। वित्त और बीमा क्षेत्र में नए ऑर्डरों में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई। कंपनियों ने इंजनेरिंग, केन्या, मलेशिया, ओमान, कतर, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों से नए कारोबार की सूचना दी।

दिल्ली अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए सबसे किफायती

नई दिल्ली | अंतरराष्ट्रीय छात्र-छात्राओं के लिए दुनिया के सबसे किफायती शहरों की सूची में दिल्ली पहले स्थान पर है। नाइट फ्रैक, डेलॉयट इंडिया और क्यूएस की इस सूची में मुंबई 11वें जबकि बेंगलुरु 15वें स्थान पर है। रैंकिंग के लिए दुनिया के 150 शहरों का मूल्यांकन किया गया। पढ़ाई व रहने का खर्च, रोजगार के अवसर, विश्वविद्यालयों की स्थिति, शहर, छात्रों की राय और जीवनशैली जैसे पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक कंपनी भारत में अपने रिटेल कारोबार का विस्तार तेज कर रही है। यह कदम भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में एप्पल की बढ़ती हिस्सेदारी और बढ़ते भरोसे का प्रतीक है।

एपल हैदराबाद में खोलेगी नया रिटेल स्टोर हैदराबाद | आईफोन निर्माता एपल हैदराबाद में एक नया रिटेल स्टोर खोलने की योजना बना रही है और उसने कर्मचारियों की भर्ती शुरू कर दी है। कंपनी ने हैदराबाद में स्टोर लीडर, सैलियर मैनेजर और जिनियस जैसे पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक कंपनी भारत में अपने रिटेल कारोबार का विस्तार तेज कर रही है। यह कदम भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में एप्पल की बढ़ती हिस्सेदारी और बढ़ते भरोसे का प्रतीक है।

अवसर: ट्रम्प नीति, लागत कटौती का असर अमेरिकी टेक दिग्गज भारत में 20% तक हायरिंग बढ़ा रहे

बिज़नेस संवाददाता | बेंगलुरु

अमेरिकी चीजा नीतियों में सख्ती और बढ़ती लागत के कारण गूगल, एपल, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां 2026 में भारत में बड़े पैमाने पर नौकरियां शिफ्ट कर रही हैं। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट भारत में 20,000 तक नई नौकरियां दे सकती है। अल्फाबेट ने बेंगलुरु के वाइएफिल्ड में ऑफिस टावर किराए पर लिया है। एपल बेंगलुरु में सपलाई चेन के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए एजुकेशन हब बना रही है। प्रोफेशनल नेटवर्किंग एप ब्लाइंड के सर्वे में 52% टेक और बैंकिंग कंपनियों के प्रोफेशनलस ने कहा कि कंपनियां 2026 में भारत में भर्ती बढ़ाने की योजना बना रही हैं। 25% कंपनियां मौजूदा टीम का आकार बढ़ा रही हैं। अकेले गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन ने 6 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की है, 5 वर्षों में 20 लाख से ज्यादा जॉब्स पैदा हो सकती हैं।

अमेरिकी टेक कंपनियां भारत में विस्तार क्यों कर रही?

बीजा महंगा पड़ता कर कठिन हुआ: कंपनियों को एच-1बी स्पांन्सर करना अब महंगा पड़ता है। खासकर एंटी-लेवल या नए पदों के लिए। **लागत में कटौती:** अमेरिका में कर्मचारी रखना भारत के मुकामले कई गुना महंगा है। भारत में कम सैलरी में ज्यादा अच्छे टैलेंट उपलब्ध हैं। **भर्ती में आसानी:** अमेरिकन कंपनियों के लिए भारतीय टैलेंट को अमेरिका बुलाने से ज्यादा आसान है। भारत की साख ग्लोबल बैंक-ऑफिस के रूप में है अब यहाँ ग्लोबल कंपेबिलिटी सेंटरस भी तेजी से बढ़ रहे हैं।

शेयर मार्केट: सेंसेक्स में मामूली बढ़त, स्मॉल और मिडकैप का प्रदर्शन बेंचमार्क से बेहतर

एआई का खौफ: आईटी में 6 वर्ष की बड़ी गिरावट, ऑयल-गैस 2% उछले

भास्कर न्यूज़|मुंबई

शेयर बाजार में बुधवार को आईटी कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट देखी गई। निफ्टी आईटी इंडेक्स 6% तक टूट गया। यह मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। परसिस्टेंट सिस्टम्स और एलटीआईमाइंड्टी के शेयरों में 7% से अधिक की गिरावट देखी गई। एसबीआई सिन्क्युरिटीज के वाइस प्रेसीडेंट सुदीप शाह के मुताबिक आईटी इंडेक्स में यह बिकवाली अमेरिकी एआई कंपनी एन्थ्रोपिक द्वारा अपने 'क्लाउड एआई' चैटबॉट के लिए एक कानूनी टूल लॉन्च करने के बाद आई, जिससे सॉफ्टवेयर निर्माताओं के लिए प्रतियस्धों बढ़ने की चिंता पैदा हो गई है। निफ्टी शेयरों में इंफोसिस और टीसीएस सबसे बड़े लुजर रहे।

सेंसेक्स 78 अंक उछल कर 83,817 पर और निफ्टी भी मामूली बढ़त के साथ 25,776 पर बंद हुआ। सेक्टरल इंडेक्स के मोर्चे पर, निफ्टी ऑयल-गैस 2% से अधिक की बढ़त के साथ टॉप गेनर रहा। निफ्टी पीएसई में भी 2% की तेजी देखी गई। स्मॉलकैप्स ने मिडकैप और फ्रंटलान्डन इंडेक्स दोनों से बेहतर प्रदर्शन किया। शाह के मुताबिक इन दोनों इंडेक्स ने एक 'बुलिश कैडल' बनाई, जो निचले स्तरों पर खरीदारी की दिलचस्पी को दर्शाती है।

इंफोसिस, टीसीएस जैसे दिग्गज आईटी शेयरों में 7% से ज्यादा गिरावट					
कंपनी का नाम	गिरावट (%)	बंद भाव (₹)	52 हफ्ते का हाई	52 हफ्ते का निचला स्तर	
इंफोसिस	-7.26%	1,535	1,924	1,307	
टीसीएस	-7.01%	2,999	4,150	2,867	
कोफोर्ज	-5.74%	1,614	1,994	1,194	
एलटीआईमाइंड्टी	-5.58%	5,706	6,429	3,802	
परसिस्टेंट सिस्टम्स	-4.66%	5,986	6,599	4,149	
एचसीएल टेक	-4.34%	1,622	1,780	1,303	
टेक महिंद्रा	-4.15%	1,645	1,854	1,209	
विप्रो	-3.85%	233	324	228	

रिक्वरी तब दिखेगी, जब आईटी फर्म एआई का इस्तेमाल फायदे के लिए करने लगेंगी

भास्कर एक्सपर्ट
जी चोकालिंगम
फाउंडर, इक्विनामिक्स रिसर्च

आज आईटी शेयरों में जो गिरावट देखी जा रही है, उसका मुख्य कारण एआई द्वारा उनके बिजनेस मॉडल को प्रभावित करने का डर है। यह समझना होगा कि आईटी सर्विस इंडस्ट्री पहले से ही सुप्त ग्रोथ वाले दौर में है, क्योंकि इनका एक्सपोर्ट बेस पहले ही बहुत बड़ा हो चुका है। पिछले 3 वर्षों में आईटी निर्यात में केवल मामूली 'सिंगल

डिजिट' बढ़ोतरी हुई है। एआई के बढ़ते डर ने पहले से मौजूद इस सुस्ती को और गहरा कर दिया है। आईटी सेक्टर, विशेष रूप से बड़ी आईटी कंपनियों में अपना निवेश कम करें। अब इन शेयरों में लंबी अवधि के लिए वेल्थ क्रिएशन के अवसर नहीं दिख रहे हैं। निवेशक बेहतर क्वालिटी वाली मिड-कैप आईटी कंपनियों पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि वे अधिग्रहण का लक्ष्य बन सकती हैं। रिक्वरी का सबसे बड़ा संकेत तब मिलेगा जब कोई आईटी कंपनी एआई (एआई) का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना शुरू करेगी।

जियो-ब्लैकरोक: अंबानी-लैरै फिंक ने एआई के भविष्य पर की चर्चा ये भारत का युग... 3 दशक में 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनेगा देश: मुकेश अंबानी

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैकरोक के सीईओ लैरी फिंक ने मुंबई में आयोजित 'इन्वेस्टिंग फॉर ए न्यू एरा' कार्यक्रम में भारत के भविष्य का रोडमैप पेश किया। अंबानी ने विश्वास जताया कि भारत अगले दो-तीन दशकों में 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि भारत पारंपरिक रूप से बचत करने वाला देश रहा है, लेकिन अब समय निवेश का है। अगर भारतीयों की बचत पूंजी बाजार में आती है, तो इससे न केवल परिवारों की संपत्ति बढ़ेगी, बल्कि देश की जीडीपी को भी गति मिलेगी। लैरी फिंक ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि लॉन्ग-टर्म इक्विटी निवेश ही वैश्व क्रिएशन का सबसे प्रभावी जरिया है। मुकेश अंबानी ने कहा कि मजबूत नीति, राजनीतिक स्थिरता और डिजिटल क्रांति ने भारत को निवेश के लिए दुनिया का सबसे आकर्षक केंद्र बना दिया है।

भारत अब खपत से इन्वोवेशन हब बन रहा है
लैरी फिंक ने भारत को विश्व अर्थव्यवस्था के लिए 'आशा की किरण' बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह भारत ने अपनी युवा आबादी को यूपीआई, आधार जैसी डिजिटल तकनीक से जोड़ा है, उसने भारत को एक नई पहचान दी है। अंबानी ने कहा कि भारत अब केवल खपत का बाजार नहीं, बल्कि 'इन्वोवेशन हब' बन चुका है।
एक दशक में ऊर्जा के क्षेत्र में भारत बनेगा आत्मनिर्भर
अंबानी ने दावा किया कि अगले दशक में भारत अपनी 80% ऊर्जा जरूरतें घरेलू स्रोतों से पूरी कर सकता है। लैरी फिंक ने रिलायंस के 'नेट-जीरो' लक्ष्य की सराहना करते हुए कहा कि भारत भविष्य में हरित ऊर्जा का प्रमुख निर्यातक बन सकता है।
युवा खड़ी कर सकते हैं रिलायंस जैसी 100 नई कंपनियां
मुकेश अंबानी ने भारतीय स्टार्टअप्स और युवाओं पर भरोसा जताते हुए कहा कि आने वाले समय में देश में रिलायंस के स्तर की कम से कम 100 नई कंपनियां खड़ी होंगी। उन्होंने युवाओं को 'ग्रोथ' पर भरोसा करने और लंबे समय के लिए निवेश करने की सलाह दी।

आज का भारत प्रचुर फलों से लदा हुआ युग है, जो देश की दीर्घकालिक ग्रोथ पर भरोसा करेगे, वही आने वाले दशकों में ज्यादा लाभ पाएंगे।
- **मुकेश अंबानी, चेयरमैन, रिलायंस इंडस्ट्रीज**
एआई में निवेश न करना बड़ा जोखिम है। अगर हम एआई में निवेश नहीं करते, तो चीन इस रेस में जीत जाएगा। भारत में डेटा की प्रचुरता है, जो एआई का ईंधन होगा।
- **लैरी फिंक, सीईओ, ब्लैकरोक**

बैंकों में एफडीआई 49% हो सकता है

बिज़नेस संवाददाता | नई दिल्ली
देश में बैंकिंग व्यवस्था को नया रूप देने की सरकार की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में सरकारी बैंकों में विदेशी निवेश बढ़ाने की तैयारी है। सरकार ने बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को मौजूदा 20% से बढ़ाकर 49% करने की योजना बनाई है। वित्त सेवा सचिव एम. नागराजू के मुताबिक मंत्रालय स्तर पर इस मामले में चर्चा चल रही है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य बैंकों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए मजबूत करना है। मजबूत बैंक बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी सेक्टर की बढ़ती फंडिंग आवश्यकताओं को पूरा करने में मददगार साबित होंगे।
विकसित भारत 2047 रोडमैप में ऐसे बैंकों की आवश्यकता जताई गई है जो बड़े पैमाने पर, दीर्घकालिक निवेशों को फंड कर सकें।
बैंकों का आरबीआई से तलतला बढ़ाने की मांग
बैंकों ने आरबीआई से संशोधित तलतला नियमों को जल्द लागू करने का अनुरोध किया है। इससे उन्हें कम सरकारी बॉन्ड रखने की अनुमति मिलेगी। नकदी देने के लिए अधिक जरूरी होंगी। गौरतलब है कि अर्थव्यवस्था में तेजी आने के कारण कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत स्तर पर लोन की मांग बहुत बढ़ गई है।

भास्कर नॉलेज

क्या है 'क्लाउड कोवर्क टूल'?
एन्थ्रोपिक ने एआई टूल कोवर्क लॉन्च किया है। यह कंपनियों के जटिल बिजनेस टास्क को ऑटोमेट कर सकता है। यह डेटा एनालिसिस, कानूनी दस्तावेज की समीक्षा, सेल्स सपोर्ट और मार्केटिंग जैसे काम बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कर सकता है।

गिरावट क्यों? निवेशकों के बीच इस बात का डर है कि यह टूल सॉफ्टवेयर, आईटी सेवा कंपनियों के बिजनेस मॉडल को खत्म कर सकता है। इसे सॉफ्टवेयर कंपनियों का अंत कहा जा रहा है क्योंकि अब कंपनियों को अलग से महंगे सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी।

ड्रीम यॉट: 33 करोड़ रुपए हफ्ता दीजिए और बिल गेट्स के सुपरयॉट में रहिए



न्यूयॉर्क | माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने गुप्तचर तरीके से दुनिया का पहला लिविड हाइड्रोजन से चलने वाला सुपरयॉट 'ब्रेकथू' बनवाया है। अब यह 36 करोड़ प्रति हफ्ते के किराए पर उपलब्ध है। इसमें -253C पर जमा कर रखी गई हाइड्रोजन ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती है, जिससे थुर्प के बजाय केवल 'पानी की भाप' निकलती है। यह 90% तक कम कार्बन उत्सर्जन करता है। एक फुटबॉल मैदान से भी बड़ा है। इसमें 12 मेहमानों के लिए 15 केबिन हैं। करीब 587 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसमें पारंपरिक मास्टर सुइट की जगह चार स्तरों का एक 'टाउनहाउस' है, जिसमें जिम, ऑफिस और डार्निंग एरिया हैं।

अगले वित्त वर्ष देश में 18% तक बढ़ेगी ई-दो पहिया की बिक्री: किसल रिपोर्ट

नई दिल्ली | भारत में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में तेजी आने की उम्मीद है। किसल रेंटेंस की रिपोर्ट के अनुसार, रेयर अर्थ मिनरल्स की आपूर्ति में आसानी से ई- दो पहिला की बिक्री में अगले वित्त वर्ष में 16-18% की वृद्धि होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक स्थापित कंपनियां विस्तार कर रही है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन लागत के मामले में काफी किफायती साबित हो रहे हैं। पेट्रोल दोपहिया के 2.2.5 रुपए प्रति किमी की तुलना में ईवी 2 व्हीलर की लागत करीब 3 पैसे प्रति किमी आती है।

भारतीय कंपनियों ने कहा- रूस से खरीदी बंद करने का आदेश नहीं मिला; क्रेमलिन बेफ्रिक

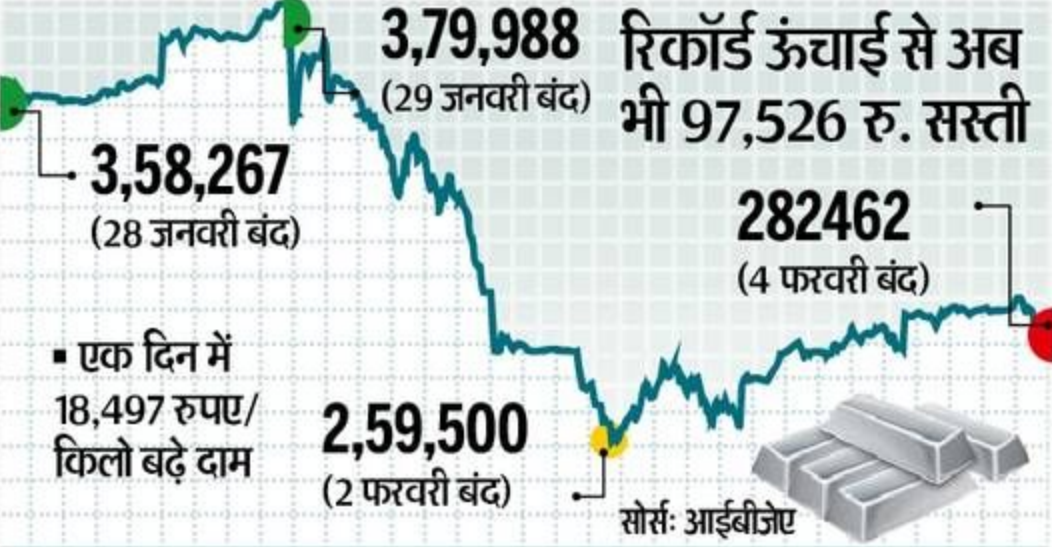
भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली
भारतीय तेल रिफाइनर भारत-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर हस्ताक्षर के बाद रूसी कच्चे तेल की खरीद के लिए अगले कदमों के बारे में सरकार से विवरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी तक सरकार की तरफ से उन्हें कोई निर्देश नहीं मिले हैं। कम से कम तीन रिफाइनरी अधिकारियों इस बात की पुष्टि की है। उधर, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के बाद भारत की तेल खरीद में बदलाव लाने की योजना को रूस कोई नई या आश्चर्यजनक बात नहीं मानता। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि भारत हमेशा से रूस सहित कई देशों से तेल खरीदता रहा है और आगे भी खरीदता रहेगा। रूस इस बात से अलगत है कि भारत कच्चे तेल के लिए एक आपूर्तिकर्ता पर निर्भर नहीं है। पेस्कोव ने कहा कि रूस

भास्कर एनालिसिस | **ईरान-अमेरिका तनाव बढ़ने से मांग फिर बढ़ी**

2 दिन में चांदी 10% उछली, 2.8 लाख पार, रिकॉर्ड स्तर से अब भी 25% नीचे

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

सोने-चांदी के दाम फिर बढ़ने लगे हैं। घरेलू बाजार में चांदी बुधवार को 18,497 रुपए महंगी होकर 2,82,462 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। आईबीजेए के डेटा के मुताबिक चांदी बीते महीने 29 जनवरी को उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी, फिर इसमें बड़ी गिरावट देखी गई और घरेलू बाजार में 2 फरवरी को 2,59,500 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी। बीते दो दिनों में चांदी 9% उछल चुकी है। हालांकि चांदी अपने उच्चतम स्तर से 25% नीचे हैं। इस दौरान 24 कैरेट सोना भी करीब 11% चढ़कर 1,58,158 रुपए पर पहुंच गया। सोना अभी अपने उच्चतम स्तर 176121 से करीब



10% नीचे हैं। कोटक सिन्क्युरिटीज में एवीपी (कमोडिटीज) कायनात चैनवाला के मुताबिक अरब सागर में अमेरिकी सेना द्वारा एक इरानी ड्रोन को मार गिराए जाने के बाद भू-राजनीतिक तनाव पैदा हो गया है, जिससे सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग फिर से बढ़ गई है। रिकॉर्ड ऊंचाई से भारी गिरावट के

बाद खरीदारों की बाजार में वापसी हुई है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सोने की कीमतों में लगातार दूसरे दिन तेजी जारी रही और यह 2% से अधिक बढ़कर 5,050 डॉलर प्रति औंस के ऊपर पहुंच गया। इस साल अब तक सोने ने करीब 17% का रिटर्न दिया, जिससे लंबी अवधि में तेजी का रुझान बरकरार है।

ऑर्डर-टू-ट्रेड नियम आसान हुए, अब जुर्माना लगाने का डर खत्म

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने शेयर बाजार में एल्गोरिदम ट्रेडिंग करने वालों और मार्केट मेकर्स के लिए नियमों को उदार बना दिया है। सेबी ने 'ऑर्डर-टू-ट्रेड रेश्यो' के ढांचे में ढील दी है, जिससे अब इक्विटी ऑप्शन में सौदे करना आसान होगा। तकनीकी कारणों से लगने वाली पेनाल्टी में कमी आएगी।

अगर कोई एल्गो ऑर्डर लास्ट ट्रेडेड प्राइस यानी अंतिम कारोबार मूल्य के 40% ऊपर-नीचे या 20 रुपए (जो भी ज्यादा हो) के दायरे में रखा गया है, तो उसे ऊंचे ओटीआर दंड से छूट मिलेगी। पहले यह छूट सीमा बहुत कम थी। इस कारण ट्रेडर्स को डर रहता था कि अगर उनके ऑर्डर तुरंत ट्रेड में नहीं बदले, तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। ये नए नियम 6 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे।

पीएफ की ब्याज दरों में हो सकती है कटौती

नई दिल्ली | ईपीएफओ प्रॉविडेंट फंड पर दिए जाने वाले ब्याज में कटौती कर सकता है। वर्तमान में पीएफ पर 8.25% ब्याज मिलता है। मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक ईपीएफओ की 239वीं सीबीटी मीटिंग में इसे कम करके 8-8.2% के बीच ला सकता है। ये बदलाव प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत योगदानकर्ताओं की संख्या बढ़ने के कारण फंड को संश्लिष्ट करने के लिए किया जा सकता है।

स्टील्थ फाइटर की रैस से एचएएल बाहर

नई दिल्ली | भारत के सबसे महत्वाकांक्षी रक्षा प्रोजेक्ट 'एएमसीए' (पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान) को लेकर बड़ी खबर आई है। रक्षा मंत्रालय की शॉर्टलिस्ट से सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स बाहर हो गई। बुधवार को शेयर 6% तक टूट गए।

अब इस 15,000 करोड़ रुपए के प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट के लिए तीन निजी दिग्गज टाटा ग्रुप, कल्याणी ग्रुप और एलएलटी बचे हैं। सूत्रों के मुताबिक, यदि किसी कंपनी की 'ऑर्डर बुक' उसके सालाना टर्नओवर से तीन गुना ज्यादा है, तो उसे इस प्रोजेक्ट में 'जीरो' अंक मिलने थे। कंपनी इस मापदंड पर खरी नहीं उतरी।

भास्कर एक्सप्लेनर भारतीय ₹75,000 तक का सामान इयूटी फ्री ला सकते हैं

भारत ने इयूटी-फ्री बैगज रूलस लिए न हों। अन्य सामानों के लिए में संशोधन किया है। हवाई या सामान्य छूट सीमा 50,000 रुपए समुद्री मार्ग से आने वाले से बढ़कर 75,000 रुपए भारतीय यात्री दैनिक उपयोग कर दी गई है। विदेशी पर्यटक के आवश्यक निजी सामान भी अब 15,000 रुपए के बिना शुल्क के ला सकते बजाय 25,000 रुपए तक का हैं, बशर्ते कि ये सामान बिक्री के ड्यूटी फ्री सामान ला सकते हैं।

2 साल विदेश में रह चुके भारतीयों के लिए क्या बदला?
2 साल से अधिक समय विदेश में रह चुके भारतीय 7.5 लाख तक के सामान बिना शुल्क भारत ला सकेंगे। ये पिछली सीमा से दोगुना है।
आभूषणों के लिए पूरी तरह से वजन आधारित प्रणाली। एक वर्ष से अधिक समय विदेश में रह चुके यात्रियों पर ये छूट लागू है। महिलाएं 40 ग्राम, पुरुष 20 ग्राम तक त्क सोना बिना शुल्क ला सकते हैं।
क्या एक नया लैपटॉप बिना शुल्क के ला सकते हैं?
अब यात्रियों को एक नया लैपटॉप बिना शुल्क के लाने की अनुमति है। यह प्रावधान चालक दल के सदस्यों पर लागू नहीं है।
कौन इस छूट का लाभ उठा सकता है?
यह सीमा भारतीय निवासियों, भारतीय मूल के आगंतुकों और वैध बीजा धारक विदेशी नागरिकों पर लागू होती है। यह छूट केवल हवाई या समुद्री मार्ग से भारत आने वाले 18 वर्ष और अधिक आयु के लोगों पर लागू होती है।

मूल्य की) और टेस्ला में 12% हिस्सेदारी पर आधारित है। 1999 में, डॉट-कॉम बूम के चरम पर, 27 वर्षीय इलॉन मस्क ने अपनी पहली कंपनी जिप2 को कॉम्पैक की 307 मिलियन डॉलर में बेचकर पहली बार दस लाख डॉलर कमाई का आंकड़ा पार किया था। इस कमाई पर मस्क ने खुद को एक मैक्लारेन एफ1 कार खरीदकर तोहफा दिया। उस समय उन्होंने ऑनलाइन भुगतान स्टार्टअप एक्स.कॉम को लॉन्च करने के लिए 10 मिलियन डॉलर (7.4 मिलियन पाउंड) का निवेश किया। बाद में इस स्टार्टअप का निम पेपाल कर दिया और एक्स.कॉम को टिवटर की जगह उपयोग किया। 2002 में स्पेसएक्स की स्थापना और 2004 में टेस्ला से जुड़ने के बाद, मस्क ने अपने व्यापारिक साम्राज्य और व्यक्तिगत संपत्ति में तेजी से वृद्धि की।



महीनों में संपत्ति के चार बड़े मुकाम हासिल किए हैं। अक्टूबर 2025 में, टेस्ला के शेयरों में भारी उछाल आने पर वे 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए। 15 दिसंबर 2025 को, इलॉन मस्क की संपत्ति 600 अरब डॉलर पार कर गई। चार दिन बाद, ही वे 700 अरब डॉलर की संपत्ति वाले व्यक्ति बन गए। उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा संयुक्त स्पेसएक्स-एक्सएआई इकाई में 43% हिस्सेदारी (लगभग 542 अरब डॉलर

दिन बाद, ही वे 700 अरब डॉलर की संपत्ति वाले व्यक्ति बन गए। उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा संयुक्त स्पेसएक्स-एक्सएआई इकाई में 43% हिस्सेदारी (लगभग 542 अरब डॉलर

विरोध करने की आदत

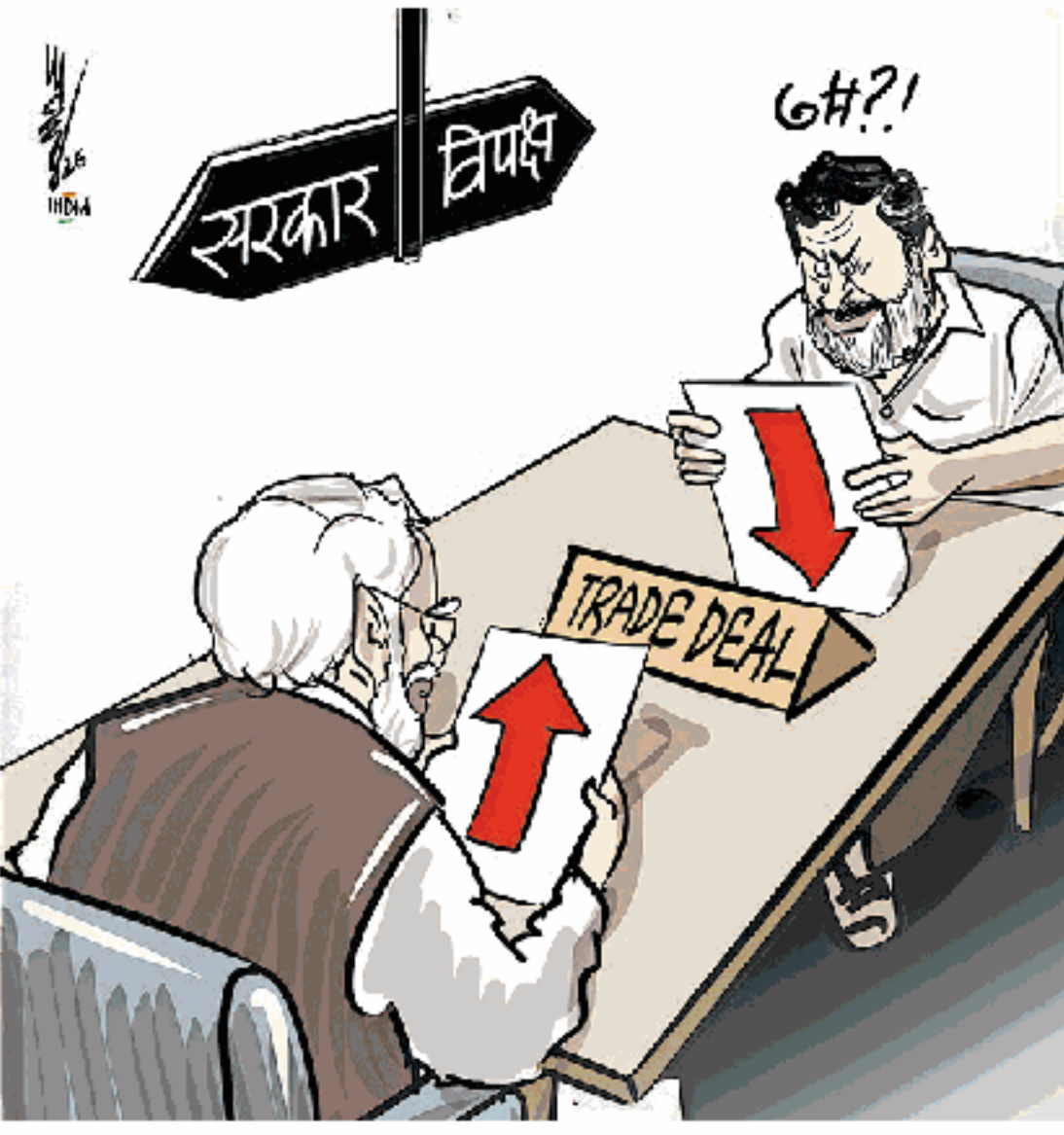
जैसी आशंका थी, वैसा ही हुआ। कांग्रेस को अमेरिका के साथ होने वाला व्यापार समझौता भी रास नहीं आया। जैसे ही अमेरेकी राष्ट्रपति ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ 50 प्रतिशत से कम कर 18 प्रतिशत करने की घोषणा की, वैसे ही कांग्रेस ने आपत्तियां उठानी शुरू कर दीं। यह सही है कि व्यापार समझौते संबंधी ट्रंप की पोस्ट से कुछ सवाल उभर रहे थे, लेकिन इन सवालों का जवाब मांगने के स्थान पर कांग्रेस नेता इस नतीजे पर पहुंच गए कि प्रधानमंत्री मोदी मजबूरी के कारण इस समझौते पर सहमत हो गए। राहुल गांधी ने तो यह कहने में भी संकोच नहीं किया कि प्रधानमंत्री ने किसानों की मेहनत को बेच दिया। कांग्रेस को इस समझौते को लेकर बनी सहमति पर आपत्ति उठाने की इतनी जल्दी थी कि उसने न तो यह देखा कि अमेरेकी राष्ट्रपति की पोस्ट पर भारतीय प्रधानमंत्री की पोस्ट क्या कह रही है और न ही वाणिज्य मंत्री के जवाब की प्रतीक्षा की। जब वाणिज्य मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि व्यापार समझौते में कृषि एवं डेरी क्षेत्र में भारत के हितों की सुरक्षा होगी और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने भी इसकी पुष्टि कर दी तो कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा, फिर भी उसने यह कहना शुरू कर दिया कि सरकार की ओर से इस बारे में संसद में जानकारी क्यों नहीं दी गई। हालांकि, वाणिज्य मंत्री ने उन परिस्थितियों का उल्लेख किया, जिनके चलते वे संसद में चाहकर भी बयान नहीं दे सके, लेकिन कांग्रेस को संतोष नहीं।

कांग्रेस की ओर से अमेरिका के साथ होने जा रहे व्यापार समझौते पर सवाल उठाने का सिलसिला कायम है। उसके साथ-साथ कुछ अन्य विपक्षी दल भी ऐसा ही कर रहे हैं। सामान्य समझ यह कहती है कि किसी भी समझौते या सहमति पर सवाल उठाने से पहले उसका विवरण सामने आने की प्रतीक्षा की जाए, लेकिन आज की भारतीय राजनीति में इस समझ के लिए स्थान शून्य होता जा रहा है। इसके स्थान पर विरोध के लिए विरोध का झंडा उठाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। वैसे तो हर दल विपक्ष में रहते समय इसी प्रवृत्ति का परिचय देता है, लेकिन शायद कांग्रेस ने इसमें महारत हासिल कर ली है। इसी कारण उसकी आलोचना-निंदा चर्चा में तो आ जाती है, लेकिन वह न तो कोई प्रभाव छोड़ती है, न किसी सार्थक बहस को जन्म देती है और न ही सत्तापक्ष को अपने रुख-रवैये पर विचार को बाध्य करती है। विडंबना यह है कि चुनाव व चुनाव पराजय के बाद भी कांग्रेस यह समझने को तैयार नहीं कि विपक्ष का काम केवल खोखली आलोचना करना या फिर सनसनीखेज आरोप उछालना भर नहीं है। सरकार के हर फैसले का हर हाल में विरोध करने की कांग्रेस की आदत इतनी अधिक बढ़ गई है कि वह तर्कों और तथ्यों से भी परे रहने लगी है।

उचित निर्णय

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण मुक्त कराई गई दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की भूमि पर वेवर हाउस, मनोरंजन केंद्र, एम्यूजमेंट पार्क और लंदन आइ की तरह दिल्ली आइ बनाने की योजना स्वागतयोग्य है। ये भूमि अब इसलिए विकसित हो सकेगी, क्योंकि लंबे समय तक अतिक्रमण का शिकार रही भूमि के प्रति दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गंभीरता दिखाई और उसे अवैध कब्जे से मुक्त कराया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में इन योजनाओं पर कार्य करने का निर्णय लिया गया। इन योजनाओं से न सिर्फ दिल्ली में रहने वालों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि इससे दिल्ली विकास प्राधिकरण के राजस्व में काफी वृद्धि होगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरह ही दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम की भी बड़ी संख्या में भूमि पर अतिक्रमण है। यही नहीं, अतिक्रमणकारियों ने राजधानी के तालाबों, जलशायों और पार्कों पर भी कई वर्षों से कब्जा कर रखा है। जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राजधानी के विकास के लिए आवश्यक है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम भी अपनी इन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराएं। इस भूमि का दिल्ली में विकास कार्यों में इस्तेमाल किया जाए और दिल्लीवासियों को इसका लाभ मिले। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने पाए।

कह के रहेंगे	माधत जोशी
	
जागरण जनमत	कल का परिणम
क्या ट्रंप टैरिफ घटने से भारत का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना आसान होगा? आज का सवाल क्या खतरनाक टास्क बेस्ड मोबाइल गेम्स पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए?	52.3 हां 38.4 नहीं 9.3 कह नहीं सकते
परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी अंकड़े प्रतिशत में।	

डालर के दबदबे से सचेत होती दुनिया



शिकंता शर्मा

सोन या कोई अन्य मुद्र फिलतल तो डालर का स्थान लेने की स्थिति में नहीं दिखती, एर बचाव की ज़ल जरूरत बन सकती है

सोने और चांदी के चढ़ते-उतरते भाव इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। विश्व स्वरूप परिषद के अनुसार पिछले वर्ष दुनिया में 3,670 टन सोने का रिकार्ड उत्पादन हुआ था। वैश्विक उत्पादन के लगभग 40 प्रतिशत सोने की खपत अकेले चीन और भारत में होती है। हालांकि आसमान छूती कीमतों के कारण वहां भी सोने की मांग में उछाल की जगह लगभग 10-11 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि ऐसी खपत में हालिया 10 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद सोने के दाम में यह उछाल क्यों आया है? इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। डालर और उसमें धुगतान के लिए जारी किए जाने वाले अमेरिकी ऋणपत्र या बांड अपनी साख की वजह से लगभग सौ वर्षों से अंतरराष्ट्रीय लेनदेन और राजकोषों के रिजर्व का प्रमुख माध्यम बने हुए थे। अमेरिका ने इन्हें हथियार बनाकर रूस को यूक्रेन

से खदेड़ने की कोशिश की। रूस और उसके समर्थकों को डालर में होने वाले लेनदेन की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली से बाहर कर दिया और यूरोपीय बैंकों में अमेरिकी बांड एवं डालर के रूप में जमा रूसी संपत्ति को फ्रीज कर दिया। ट्रंप ने सत्ता संभालते ही उनका और खुल्लाम-खुल्ला प्रयोग करना और व्यापार की हथियार बनाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से दुनिया को अमेरिका की नीयत पर संदेह होने लगा और उसकी मुद्रा और बांड की साख गिरने लगी। ट्रंप की लिबरेशन डे टैरिफ की घोषणा के समय भी अमेरिकी बांड और डालर की कीमतें गिरी थीं और सोने की कीमतों में उछाल आया था।

क्रेडिट संकट के समय सोने ने हमेशा लेनदेन के सर्वग्राह्य और भरोसेमंद माध्यम की भूमिका निभाई है। उसकी सीमित मात्रा और सर्वग्राह्यता के कारण उसके दाम भी संकटकाल को छोड़कर औसतन स्थिर ही रहे हैं। इसलिए इन दिनों विश्व भर के केंद्रीय बैंक और बहुराष्ट्रीय निवेश कंपनियों ने अपने-अपने कोषों में अमेरिकी बांड और डालरों को घटाकर उनकी जगह सोने को रखना शुरू किया है। पिछले पांच वर्षों में चीन ने अपना स्वरूप भंडार बढ़ाने के लिए 351 टन, भारत ने 218 टन और जापान ने 81 टन सोना खरीदा है। भारत ने 51 अरब डालर के अमेरिकी बांड बेचकर उनके भंडार में 21 प्रतिशत की कटौती की है और उनकी जगह सोने का भंडार बढ़ाकर 880 टन कर लिया है जो उसके विदेशी मुद्रा भंडार का 16 प्रतिशत है। सोने की कीमतों में निरंतर उछाल का प्रमुख कारण यही है। कुछ बाजार विश्लेषकों का तो कहना है कि सोने के दाम अगले दो-तीन साल में 30,000

इस्लामिक जगत में बदलते समीकरण

पश्चिम और दक्षिण एशिया की सुरक्षा संरचना इस समय एक गहरे, लेकिन अपेक्षाकृत शांत परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। इसके मूल में विचारधारा से अधिक भू-राजनीतिक यथार्थ, आर्थिक गणनाएं और क्षेत्रीय शक्तियों की बढ़ती आत्मनिर्भरता है। अमेरिका की घटती सुरक्षा भूमिका, यूरोप की आंतरिक विभाजित स्थिति और वैश्विक शक्ति संतुलन में हो रहे बदलावों ने क्षेत्रीय देशों को अपनी सुरक्षा जिम्मेदारी स्वयं संभालने के लिए प्रेरित किया है। लंबे समय तक पश्चिम एशिया की सुरक्षा व्यवस्था अमेरिकी नेतृत्व और गारंटी पर आधारित रही, किंतु ट्रंप के कार्यकाल के बाद से अमेरिका की नीति अधिक लेन-देन आधारित और अनिश्चित होती गई है। इससे पारंपरिक सहयोगी देशों को यह महसूस होने लगा कि संकट के समय अमेरिकी हस्तक्षेप स्वतःस्फूर्त नहीं रहेगा। यूरोप भी यूक्रेन युद्ध, ऊर्जा संकट के कारण इस क्षेत्र में प्रभावी सुरक्षा भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में क्षेत्रीय शक्तियां वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्थाओं की तलाश में हैं। इस बदलते परिदृश्य में एक धारा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच उभरती निकटता के रूप में दिखाई देती है, जिसे 'इस्लामिक नाटो' भी कहा जा रहा है।

पाकिस्तान लंबे समय से सऊदी अरब के साथ रक्षा सहयोग रखता आया है, किंतु हालिया वर्षों में इस संबंध को व्यापक रणनीतिक ढांचे में बदलने का प्रयास तेज हुआ है। उसकी कोशिश है कि सऊदी संसाधनों और तुर्किये की रक्षा तकनीक के साथ मिलकर एक ऐसा सुरक्षा समूह बनाया जाए, जो अमेरिका पर निर्भरता कम कर सके। हालांकि इस प्रस्तावित धुरी की मजबूती उतनी नहीं है, जितनी उसकी राजनीतिक बयानबाजी से प्रतीत होती है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है और उसकी क्षेत्रीय विश्वसनीयता सीमित होती जा रही है। भारत के साथ उसका संघर्ष केवल भू-क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैचारिक भी है, जिसे उसकी सैन्य स्थापना अब भी 'दो-राष्ट्र सिद्धांत' के रूप में जीवित रखे हुए है। इसी वैचारिक ढांचे के माध्यम से पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में समर्थन जुटाने की कोशिश करता रहा

पाठकनामा
pathaknama@nda.jagran.com

सही दिशा में कदम

'अमेरिका के साथ एक नई शुरुआत' शीर्षक से लिखे आलेख में डा. मनिष दामाडे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतिगत अस्थिरता को लेकर कुछ आशंकाएं व्यक्त की हैं, जिनके बारे में स्थिति विवरणों से और स्पष्ट होगी। इसलिए इस व्यापारिक समझौते को फलीभूत होने में कुछ समय लग सकता है। इसके बावजूद यह तो कहा ही जा सकता है कि बहुप्रतीक्षित व्यापारिक समझौते की जो प्रारंभिक बाधाएं थीं, वे दूर हो गई हैं। अब भारत को बड़ा बाजार मिल गया है, जो उसे उसके एशियाई प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त दिलाने में मददगार साबित होगा। तेल खरीद के मामले में वेनेजुएला से आश्वस्त होने के बाद भारत का यह समझौता मील का पत्थर साबित होगा। हालांकि इस संदर्भ में रूस जैसे सामरिक सहयोगी से सन्निकटता-सहभागिता घटना उचित नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप की नीतियों से भारत का अमेरिका पर पूर्णतः विश्वास करना कठिन है। बहरहाल इस समझौते के लिए ट्रंप राजी क्यों हुए? कहीं इसमें यूरोपीय संघ के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौते का अहम योगदान नहीं है? इससे साबित होता है कि अमेरिका के साथ संबंधों में हमारी रणनीतिक स्वायत्तता और दृढ़ता काम आई। इस मामले में भारत ने कूटनीतिक परिपक्वता का जरूर परिचय दिया, मगर भारत के प्रति पड़ोसियों विशेषकर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के मौजूदा रुख में अमेरिका का बर्ताव कम अहम नहीं है। यह भी ध्यान में रखना जरूरी है। खैर, अब वस्त्र, परिधान, रत्न,

समुद्री उत्पादों को व्यापक बाजार मिलने के आसार बढ़ेंगे। बजट में जो तीन लक्ष्य रखे गए हैं उत्पादकता, क्षमता निर्माण, सबका विकास को इससे गति मिलेगी। मुकेश कुमार मनन, पटना

भारत-अमेरिका ट्रेड डील

भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चली आ रही व्यापार वार्ताओं का सकारात्मक नतीजा सामने आना केवल एक समझौता भर नहीं है, बल्कि यह भारत की बदली हुई वैश्विक आर्थिक हैसियत, कूटनीतिक परिपक्वता और नीतिगत स्थिरता का प्रमाण है। टैरिफ दरों में 50 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत तक की कटौती के बाद जिस तरह से शेयर बाजार, क्मोडिटी मार्केट और मुद्रा बाजार में उत्साह दिखा, उसने साफ कर दिया कि यह फैसला केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी अर्थव्यवस्था को गति देने वाला है। सेंसेक्स और निफ्टी का रिकार्ड तेजी के साथ बंद होना, निवेशकों की संपत्ति में एक ही दिन में करीब 12 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी और रुपये की तीन साल की सबसे बड़ी मजबूती, यह सब बाजार की उस भरोसे की अभिव्यक्ति है, जो मौजूदा सरकार की आर्थिक नीतियों पर दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में इस समझौते को धैर्य और दूरदृष्टि का परिणाम बताया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आलोचनाएं होती रहीं, दबाव भी था, लेकिन सरकार ने राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना संयम बनाए रखा। आज उसी का यह परिणाम है कि भारत शानदार तरीके से एक मजबूत सौदे की स्थिति में खड़ा है।

काविलाल मांडोट, नई दिल्ली



अभिषेक राजगुप्त

रुपये प्रति ग्राम पर भी पहुंच सकते हैं। अमेरिकी बांड की साख लंबे राजकोषीय अनुशासन, राजनीतिक स्थिरता के साथ मिलने वाली निश्चित आय से बनी है। वह कर्ज की राशि डालरों में अदा करने के साथ-साथ ब्याज भी चुकाता है, जिसकी दरें बांड की अवधि पर और तत्कालीन ब्याज दरों के रुझान पर निर्भर करती हैं। आम तौर पर अमेरिकी बांड पर मिलने वाले ब्याज की दरें महंगाई की दर से अधिक ही रहती हैं। इसलिए अपने कोष में अमेरिकी बांड रखने वाले देश या कंपनी को कोष की क्रयशक्ति की सुरक्षा के साथ-साथ ब्याज के रूप में कुछ लाभ भी मिलता रहता है। यह लाभ डालर या सोना रखने से नहीं मिल सकता। यही कारण है कि विदेशी मुद्रा भंडारों में अमेरिकी बांड का अनुपात नकद डालर और सोने से अधिक रहता है। जो देश अमेरिका के साथ व्यापार में साल-दर-साल लाभ कमाते रहे हैं उनके पास अमेरिकी डालर जमा हो जाते हैं। ये देश डालरों से अमेरिकी बांड खरीद लेते हैं। व्यापार के इस चक्र की वजह से

प्रतिरोधक क्षमता और आर्थिक विकास पर केंद्रित है। यमन से लेकर अफ्रीका के हार्न क्षेत्र तक यूपूर्ड ने यह दिखाया है कि वह अपने सुरक्षा हितों को स्वतंत्र रूप से परिभाषित करने के लिए तैयार है, भले ही इसके लिए उसे पारंपरिक सहयोगियों से अलग रास्ता क्यों न अपनाना पड़े। इजरायल के साथ सामान्यीकरण ने यूपूर्ड को क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे में एक नई स्थिति प्रदान की है। भारत के लिए यह साझेदारी रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण है। जहां नई दिल्ली पाकिस्तान द्वारा इस्लामिक जगत में अपनी स्थिति मजबूत करने के प्रयासों को लेकर सतर्क है, वहीं वह इजरायल के साथ दशकों से चल आ रहे संबंधों को यूपूर्ड जैसे आर्थिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश के साथ जुड़ने का भी अवसर देख रही है।

हाल में भारत और यूपूर्ड के बीच रक्षा सहयोग पर आशय पत्र इसी दिशा में एक संकेत है। इस समीकरण का विस्तार पूर्वी भूमध्यसागर तक दिखाई देता है, जहां भारत, इजरायल, ग्रीस और साइप्रस के बीच बढ़ता संवाद तुर्किये की समुद्री आक्रामकता और व्यापार मार्गों को सुरक्षा से जुड़ा है। भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे जैसे प्रयास इस रणनीतिक नेटवर्क को आर्थिक आधार भी प्रदान करते हैं। एक ओर ऐसा ढांचा है जो वैचारिक अपील और प्रतीकात्मक शक्ति पर निर्भर करता है, दूसरी ओर एक ऐसा समीकरण है, जो आर्थिक मजबूती, तकनीकी सहयोग और साझा सुरक्षा पर आधारित है। पश्चिम और दक्षिण एशिया की सुरक्षा व्यवस्था एक बहुध्रुवीय, व्यापकनिर्भर और क्षेत्रीय रूप से संचालित ढांचे की ओर अग्रसर है। जो देश आर्थिक रूप से मजबूत, तकनीकी रूप से सक्षम और रणनीतिक रूप से सुसंगठित हैं, वे इस नए परिदृश्य में बेहतर स्थिति में होंगे। जो केवल वैचारिक नारों और प्रतीकात्मक गठबंधनों पर निर्भर हैं, वे शायद ध्यान आकर्षित कर लें, लेकिन स्थायी शक्ति हासिल नहीं कर पाएंगे। फिर भी भारत को सतर्क रहना होगा।

(लेखक मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्येन एवं विश्लेषण संस्थान में एसोसिएट फेलो हैं)

response@jagran.com

आपसी व्यापार अपनी मुद्राओं में करने लगे, लेकिन छोटी मुद्राओं का आपसी विनिमय और तेल, गैस एवं सोने जैसी महत्वपूर्ण चीजों का मूल्य निर्धारण डालर में ही होता है। दूसरी मुद्राओं में लेनदेन के बाद भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और देशों को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचने के लिए स्वेप या हेजिंग डालर में ही करने पड़ती है। इतना अवश्य है कि ट्रंप की व्यापार अस्वीकरण की नीतियों के कारण दुनिया अमेरिकी बांड और डालर पर बनी निर्भरता के प्रति सचेत हो उठी है। उससे बचने के लिए व्यापार और राजकोषीय संग्रह में अमेरिकी बांड और डालर के साथ साथ सोने-चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं और दूसरी मुद्राओं को शामिल करके के सक्रिय प्रयास हो रहे हैं। अमेरिका की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए अमेरिकी बांड की सुनिश्चित बिकवाली का विकल्प भी है। ऐसी बिकवाली से अमेरिका को मिलने वाले कर्ज की दरों में उछाल आ सकता है, जिससे मनमानी करने वाली सरकार को पीछे हटना पड़ सकता है। ग्रीनलैंड विवाद में डेनमार्क की पेंशन कंपनी एकेडेमीकर ने अपने सारे अमेरिकी बांड बेचकर यही संकेत दिया, जिसने ट्रंप को नरम पड़ने के लिए विवश किया। यूरोप के जिस ब्रह्मास्त्र की बात हो रही थी उसमें यह विकल्प भी शामिल था, क्योंकि अमेरिकी कर्ज का करीब 20 प्रतिशत यूरोप और उसकी कंपनियों के पास ही है। कुल मिलाकर, सोना या कोई और मुद्रा डालर का स्थान लेने की स्थिति में तो नहीं दिखती, पर बचाव की दाल जरूर बन सकती है।

(लेखक बीबीसी हेंद्री के पूर्व संपादक हैं)

response@jagran.com



सत्यनिष्ठा एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को सुंदर एवं अनुकरणीय व्यक्तित्व प्रदान करते हुए समाज में उसे एक अद्वितीय पहचान दिलाता है। सत्यनिष्ठा से आशय केवल सत्य बोलना ही नहीं है, अपितु प्रतिलप सत्य के प्रति निष्ठावान रहना, सत्य को जीवन का मूल आधार बनाना और प्रत्येक परिस्थिति में सत्य को धामे रहना है। यह एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति के चरित्र को दृढ़ता प्रदान करते हुए उसे निर्भीकता के कवच से सुसज्जित करती है। तीव्र एवं अनियंत्रित प्रतिक्रियाएँ नैतिकता को पीछे छोड़ देती है। ऐसे परिवेश में सत्यनिष्ठा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि असत्य, छल, कपट, दिखावा और स्वार्थ जैसे अवगुणों के मध्य सत्यनिष्ठा आशा की एक किरण के समान होती है। सत्यनिष्ठा का अर्थ है-विचारों में सत्यता एवं शुचित्ता, व्यवहार में ईमानदारी, दायित्वों में पारदर्शिता, निर्णयों में न्याय एवं निष्पक्षता तथा अंतरात्मा से सीधा जुड़ाव।

यथार्थ ही कहा गया है कि 'सत्य एक बार जीतता है, झूठ बार-बार हारता है।' सत्यनिष्ठा की सच्ची पहचान विपरीत एवं विषम परिस्थितियों में ही होती है। सत्यनिष्ठ व्यक्ति सदैव अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। सत्यनिष्ठा वह दीपक है, जो निराशा के अंधकार में मार्ग दिखाता है। यह एक बहुमूल्य नैतिक गुण है। सत्यनिष्ठ व्यक्ति सदैव समाज में सम्मान अर्जित करता है, परिवार में विश्वास पाता है और स्वयं के भीतर आत्मशान्ति प्राप्त करता है।

आज के समय में तो यह और आवश्यक हो गया है कि हम सत्यनिष्ठा को केवल आदर्श की भाँति न मानें, बल्कि उसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाएं, क्योंकि सत्यनिष्ठा ही वह शक्ति है जो व्यक्ति की महानता, समाज के स्वास्थ्य एवं राष्ट्र की प्रगति का एक प्रमुख स्तंभ है। निःसंदेह सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलना एक दुष्कर कार्य है, किंतु एक बार इस राह पर अग्रसर होकर व्यक्ति सदा-सदा के लिए डूबराखियों से दूर हो जाता है।

प्रेरणा अवस्थी

✖ पोस्ट
--

देश में इन दिनों व्यापार और टैरिफ मामलों के विशेषज्ञों की बाढ़ आई हुई है। यह भी इंटरनेट मीडिया की खुमारों का असर है।

सेवियों रोड्रिगेज@PrinceArianhan



सैयद अकबरुद्दीन@AkbaruddinIndia

संसद में तमाम किताबों का हवाला दिया जा रहा है। इसका एक सकारात्मक पहलु यह भी हो सकता है कि लोगों में इन किताबों की पढ़ने की उत्सुकता जगो। कम से कम ये किताबें तो पढ़ी ही जा सकती हैं जो प्रतिबंधित नहीं हैं।

पद्मजा जोशी@PadmajaJoshi

इसे कहते हैं बैटे-विटाए बेवजह का मुद्दा देना। पार्टियां बदलने का चलन राजनीति में आम है। ऐसे में किसी को गद्गार कहना मुनासिब नहीं। नेता-विपक्ष का काम सत्तापक्ष से सवाल करना है। ज्वलंत मुद्दे उठाना है। किसी पूर्व साक्षी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना नहीं।

उमाशंकर सिंह@umashankarsingh

जनपथ

यूजीसी की मूर्खता पर तो थे नाराज, पर राहुल का आचरण देख आ रही लाज। देख आ रही लाज चुनें फिर किसको भाई, इक बाजू है कूप दूसरे बाजू खाई! चलने दो सरकाव चल रही है जो जीसी, बहुत बड़ा है देश और छोटी पूंजीसी!!

- ओमप्रकाश तिवारी

संसद प्रश्नोत्तर

28 जनवरी तक बेवी गर्ई 2,930 करोड़ की शत्रु संपत्तियां: सरकार

नई दिल्ली, प्रे़ : भारत सरकार ने संसद में बताया कि 28 जनवरी तक 2,930 करोड़ रुपये की चल और अचल शत्रु संपत्तियां बेची हैं। शत्रु संपति उन संपत्तियों को कहा जाता है जो पाकिस्तान व चीन की नागरिकता लेने वाले लोगों ने देश में मुख्यतः वर्ष 1947 से 1962 के बीच छोड़ी थीं। गुड राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि शत्रु संपत्तियों का निपटारा और मौखिकरण शत्रु संपति अधिनियम, 19६8 और इसके तहत बनाए गए नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जात है।

सरकार की 260 वेंे भारत स्तीपर ट्रेनसेट बनाने की योजना: वैष्णव

नई दिल्ली, एएनआई: देशभर में लंबे दूरी की यात्राओं के लिए सस्कार ने बड़े भारत स्तीपर ट्रेनसेट के लिए बड़े पैमाने पर निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत 2६0 ट्रेनसेट के निर्माण की योजना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी। रेल मंत्रालय ने बताया कि वेंे भारत स्तीपर जैसी ट्रेनों के विकास की प्रक्रिया में एक सप्ताह दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें तकनीकी नवाचार, रणनीतिक योजना और उत्पादन का समन्वय होता है। ताकि सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित की जा सके।

दुरुपयोग रोकने के लिए निष्क्रिय किए गए ढाई करोड़ आधार नंबर

नई दिल्ली, प्रे़: सरकार ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने दुरुपयोग रोकने के लिए ढाई करोड़ से अधिक मृत लोगों के आधार नंबर निष्क्रिय कर दिए हैं। इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि आधार दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली है, जिसमें लगभग 134 करोड़ सक्रिय आधार धारक हैं। एक राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत यूआईडीएआई ने अब तक ढाई करोड़ से अधिक मृत लोगों के आधार नंबर को निष्क्रिय कर दिया है।

5.9 करोड़ फास्टैग सक्रिय : नितिन गडकरी

नई दिल्ली, प्रे़ : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को संसद में बताया कि देश भर में अब तक जारी किए गए कुल 11.86 करोड़ फास्टैग में से लगभग 5.9 करोड़ सक्रिय हैं। फास्टैग का उपयोग टोल का भुगतान के लिए किया जाता है। केंद्रीय सड़क, परिवहन और रातमार्ग मंत्री ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।

पीएम सूर्यधर मुफ्त विजली योजना से 28 लाख परिवारों को हुआ फायदा

नई दिल्ली, प्रे़ : सरकार ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि जनवरी 202६ तक पीएम सूर्यधर: मुफ्त बिजली योजना के तहत 28 लाख से ज्यादा परिवारों को फायदा हुआ है, जिसमें केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता के तौर पर 16 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा दिए गए हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में यह बताया है।

दिल्ली में ड्रामा कर रही हैं ममता : भाजपा

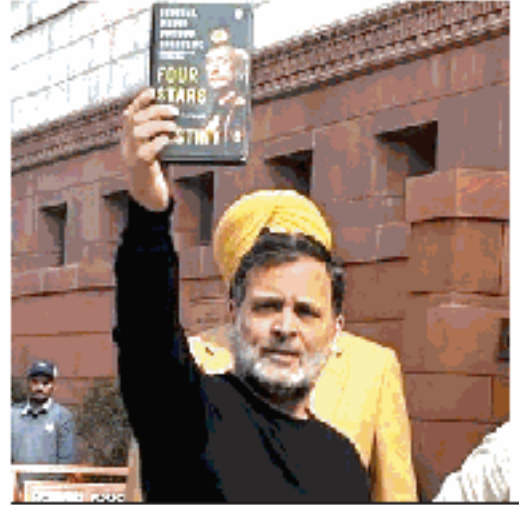
जागरण व्यूरो, नई दिल्ली : बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिली दौरें और एसआइआर के विरोध को भाजपा ने बड़ा "राजनीतिक पाखंड" करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी का खुद बंगाल का पक्ष रखने और एसआइआर की आड़ में लोकतंत्र को खत्म किए जाने के आरोपों पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया है। भाजपा मुख्यालय में आयोजित संबद्धता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य शमिक भट्टराचार्य एवं केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री सुकुंतल मजूमदार ने तृणमूल कांग्रेस पर बेरर लिटरे के शुद्धिकरण से घबराने का आरोप लगाया। शमिक भट्टराचार्य ने कहा कि ममता चाहे जो भी कर लें, बंगाल में एसआइआर की प्रक्रिया होकर रहेगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि ममता बनर्जी के पास कोलकाते के भीषण अग्निकांड के पीछित से मिलने का समय नहीं है। लेकिन, घुसपैठियों के हितों की रक्षा के लिए दिल्ली में झूठा करने का समय है।

सियासी विवाद का विषय बना सैन्य निर्णय तो डगमगाएगा सेना व राजनीतिक नेतृत्व के बीच भरोसा

जागरण व्यूरो, नई दिल्ली : पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक पर संसद में छिड़े संग्राम से साफ है कि अब सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसले पर भी राजनीति भारी पड़ने लगी है। इस अप्रकाशित पुस्तक के आधार पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पूर्वी लड़ाख की कैलास रेंज में 2020 में चीनी सेना के आगे बढ़ने के दौरान फैसला सेना प्रमुख पर छोड़ने के शीर्ष सरकारी नेतृत्व की कमजोरी के रूप में पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि सरकार इसे संसदीय मर्यादाओं के विरुद्ध और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील विषय का राजनीतिकरण करने का आरोप लगा रही है। अगर हर सैन्य निर्णय

राजनीतिक बहस का विषय बनाया गया तो इससे भविष्य में सेना और राजनीतिक नेतृत्व के बीच भरोसे का ताना-बाना प्रभावित हो सकता है। **पुस्तक की प्रति हथ में लेकर बुधवार को संसद पहुंचे राहुल**: नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक का हवाला देकर राहुल गांधी जिस तरह सरकार पर सबल उठा रहे हैं, उसका मतलब है कि सीमा पर किसी भी सैन्य कार्रवाई का फैसला वहां तैनात सैन्य कमांडर व शीर्ष सैन्य नेतृत्व नहीं, बल्कि सरकार और प्रधानमंत्री के स्तर पर होता है। राहुल इसी विषयों को आगे बढ़ाने के लिए नरवणे को पुस्तक की प्रति हथ में लेकर बुधवार को संसद आए। नरवणे को पुस्तक में दाब किया गया

है कि 2020 में कैलास रेंज में जब चीनी सेना चार टैंक लेकर आगे बढ़ रही थी, तब उत्तरी क्षेत्र के कमांडर की सूचना के बाद सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से निर्देश मांगा था। जवाब में विलंब हुआ तो उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को भी फोन किया था। इसके बाद दोबारा रक्षा मंत्री को फोन किया, तो उन्होंने प्रधानमंत्री से बात करके बताया कि शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि जो उचित समझो, करो। राहुल का आरोप है कि जब सीमा पर गंभीर संकट की स्थिति थी, तब राजनीतिक नेतृत्व ने दो घंटे से अधिक की देरी की और अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय फैसला



सेना प्रमुख पर छोड़ दिया। यह राजनीतिक नेतृत्व की गंभीर कमजोरी को दर्शाता है।

सत्ता पक्ष इस तर्क को आधारहीन बताते हुए इसे सेना को राजनीतिक बहस में घसीटने का प्रयास बता रहा है। उसका कहना है कि मोर्चे पर चुनौतियों का जवाब कैसे देना है,

- नरवणे की किताब को आधार बना राहुल दे रहे संकेत, शीर्ष स्तर पर होता है सैन्य कार्रवाई का फैसला**
- सत्ता पक्ष का तर्क- मोर्े पर जवाब की रणनीति सेना स्तर पर तय होती है, ऐसे में उचित थे पीएम के निर्देश**

<< नरवणे की किताब के साथ राहुल •>>

इसकी रणनीति सेना के स्तर पर ही होती है। इस लिहाज से नरवणे को दी गई सलाह सेना एवं सरकार के बीच स्थापित संचालन व्यवस्था के तहत थी और सैन्य व राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा था। बेशक हमारी संघीय व्यवस्था में सेना पूर्णतः सरकार के अधीन है, लेकिन इसका

यह अर्थ नहीं कि हर सामरिक निर्णय राजनीतिक नेतृत्व ही लेता है। कई बार संकट की स्थिति में राजनीतिक नेतृत्व व्यापक नीति एवं दिशा तय करता है और जमीनी हालात के अनुसार मोर्चे पर तत्कालिक निर्णय सेना प्रमुख व उनके कमांडरों पर छोड़े जाते हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री का 'जो उचित समझो, करो' का निर्देश इसी स्थापित प्रक्रिया का हिस्सा था। इसे नेतृत्व की विफलता के रूप में पेश करना सरकार व सेना के बीच कार्य संचालन की स्थापित प्रणाली को नकारना है।

चीन की सामरिक चुनौती से निपटने की रणनीति का हिस्सा: सेना एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को राजनीतिक

हथियार के रूप में इस्तेमाल करना इस दृष्टि से भी उचित नहीं है कि यदि कैलास रेंज में जमीनी हालात के अनुसार फैसला लेने की जिम्मेदारी सेना प्रमुख को दी गई थी, तो यह सामरिक-रणनीतिक विवेक का हिस्सा भी हो सकता है। ऐसे में इस पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि प्रधानमंत्री के जिस कदम को राहुल उनकी कमजोरी बता रहे हैं, वह चीन की सामरिक चुनौती से निपटने की रणनीति का हिस्सा रहा हो। बेशक अहम विषयों पर सरकार पर सबल उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी है, मगर राष्ट्रीय सुरक्षा सेना और राजनीतिक जवाबदेही के बीच संतुलन बनाए रखना भी उतना ही अहम है।

'खाद्य व कृषि से जुड़े हितों का रखा गया ख्याल' वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते के बारे में संसद को दी जानकारी

जागरण व्यूरो, नई दिल्ली : केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को संसद में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक समझौते में खाद्य, कृषि और डेरी क्षेत्र में भारत की संवेदनशीलता का पूरा ख्याल रखा गया है। इस समझौते को भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करने के साथ ही 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य को गति देने वाला बताते हुए उन्होंने कहा कि यह दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच मजबूत जुड़ाव को दर्शाता है, जो साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इस समझौते से अमेरिकी बाजार में निर्यात प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच टेलीफोन पर बार्ता के बाद व्यापार समझौते की घोषणा की गई थी।

लेनों पक्ष तकनीकी प्रक्रियाओं और कामाजी कार्रवाई को अंतिम रूप देने में जुटे: रूस से तेल खरीद को लेकर लगाए जा रहे कार्रवाई पर गोयल ने कहा, 'मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जैसा सरकार ने कई बार सार्वजनिक तौर पर कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों की उर्जा आवश्यकताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। वस्तुनिष्ठ बाजार परिस्थितियों और बदलते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के अनुरूप उर्जा आपूर्ति में बिंबधता लाना हमारी कार्यनीति का



कजट सत्र के दौरान बुधवार को लोकसभा में अपनी बात रखते केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल • एएनआई

विपक्ष का परंपरा तोड़ने का आरोप, सभापति ने किया खारिज वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर संसद में बयान रख दिया है, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। बुधवार को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के उपनेता प्रतियक्ष प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठातेहुए कहा कि संसद नियम-परंपरा से चलती है। परंपरा है कि जब संसद सत्र चल रहा हो तो नीतिगत विषयों की जानकारी सबसे पहले संसद में दी जाती है। इसके बावजूद वाणिज्य मंत्री ने मंगलवार को प्रेसवार्ता कर जानकारी साझा की। लेकिन सभापति सीपी जामनखान ने व्यवस्था का यह प्रश्न यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मंत्री स्वयं ही बुधवार को संसद में वक्तव्य रखना चाहते थे।

मूल आधार है। भारत की सभी कार्रवाइयां इसी को ध्यान में रखकर की जाती हैं।' गोयल ने भारत और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को एक दूसरे का पूरक बताते हुए कहा कि जैसे-जैसे भारत विकास पथ पर बढ़ रहा है उसे उर्जा, विमानन, डाटा सेंटर, परमाणु उर्जा आदि क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत है। अमेरिका इन क्षेत्रों में अग्रणी देश है, जिससे न केवल हमारी खरीद बढ़ेगी बल्कि हमारा निर्यात भी

बढ़ेगा। अनुमान है कि कई क्षेत्रों में अमेरिका को भारत का निर्यात बढ़ेगा। आगे की रणनीति के बारे में गोयल ने बताया कि दोनों पक्ष अब तकनीकी प्रक्रियाओं और कामजी कार्रवाई को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। समझौते की विस्तृत रूपरेखा इन प्रक्रियाओं के समापन के बाद शीघ्र घोषित की जाएगी। समझौते को राष्ट्र हित में बताते हुए उन्होंने कहा कि यह विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत दोनों को सशक्त बनाएगा।

नीट पीजी कट-आफ में कटौती पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली, प्रे़ : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नेशनल बोर्डे आफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (एनबीईएमएस) द्वारा नीट पीजी 2025-2६ के लिए क्बलीफाईंग कट-आफ पसैटइल में भारी कटौती के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, एनबीईएमएस और राष्ट्रीय चिकित्सा अयोग को नोटिस जारी किया है। देशभर में पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल की 18,000 से अधिक सीटों के खाली रहने के कारण एनबीईएमएस ने क्बलीफाईंग पसैटइल में अभूतपूर्व संशोधन किया है। मामले में याचिका समाज सेवी हरिशरण देगमन और डा. सीरव कुमार सहित अन्य डाक्टरों द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि कट-आफ में इस तरह की कमी संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।

जागरण व्यूरो, नई दिल्ली : संसद के अंदर दिखने वाली आपसी तकरार भी सामान्यतया सदन के बाहर परिसर में ही हल्की हो जाती है लेकिन बुधवार को संसद भवन के गेट पर अलग ही नजारा देखने को मिला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच उस समय सीधी भिड़ंत हो गई जब राहुल गांधी ने उन्हें 'गद्दार' दोस्त कहकर संबोधित किया तो बिट्टू ने भी उन्हें 'देश का दुश्मन' कहते हुए तीखा पलटवार किया। इस दौरान बिट्टू ने राहुल की ओर से बढ़ाया गया हाथ मिलाने से भी मना कर दिया। उधर, भाजपा ने राहुल गांधी को इस टिप्पणी को हर सिख का अपमान बताते हुए इस मामले पर लोकसभा स्पीकर से राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

हुआ यह कि केंद्रीय मंत्री बिट्टू बुधवार को जब संसद भवन के गेट से भीतर जा रहे थे, तभी वहां बजट सत्र के शेष समय के लिए निर्लंबित किए गए अपने सांसदों के साथ राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे थे। इनमें

आयोग को वाट्सएप आयोग कहकर संबोधित किया, जो कथित तौर पर चुनाव आयोग द्वारा अधिकारियों को वाट्सएप के माध्यम से दिए जा रहे निर्देशों की ओर इशारा था।

50 लाख से ज्यादा नाम डिलीट किए गए। फिर अब नाम में मामूली अंतर पर एक लाख से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजा गया है।

राकेश द्विवेदी (चुनाव आयोग के कमील) : आयोग ने राज्य सरकार को कई पत्र लिखे और क्लास टू अधिकारियों की मांग की। लेकिन राज्य सरकार ने सिर्फ 80 अधिकारी उपलब्ध कराए। बाकी तृतीय श्रेणी के कर्मचारों की रिहाई पर लिखे आयोग को माइक्रो आख्यर्भ नियुक्त करने पड़े।

ममता : सिर्फ बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है।बीएनटीयू या इआरओही नाम डिलीट करें।माइक्रो आख्यर्भ नहीं। **सुनील** : हम सोमवार को फिर कैसे सुनें। तब तक चुनाव आयोग निर्देश लेकर जवाब देगा।।



संसद के कजट सत्र के दौरान बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बातचीत करते केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू • प्रे़

अधिकांश पंजाब के सांसद थे। उन्हें देखकर केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने कहा -'यहां ये सब यानी निर्लंबित कांग्रेस सांसद ऐसे बैठे हैं जैसे उन्होंने कोई युद्ध जीत लिया हो।' इस पर राहुल ने

गद्दार दोस्त। चिंता मत करो, तुम बापस (कांग्रेस में) आ जाओगे।' इसके बाद तो बिट्टू ने हाथ मिलाने से मना करते हुए राहुल गांधी की ओर इशारा कर उठे 'देश का दुश्मन' कहा। इस तीखे बार्तालाप के बाद बिट्टू संसद के भीतर चले गए। इस बीच, नए संसद भवन के प्रवेश द्वार पर राहुल गांधी की ओर से बिट्टू पर की गई टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी तीखे प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस नेता ने शिष्टाचार की सभी सीमाएं पर कर दी हैं।

बिट्टू वाले- गांधी पंखार के वंशज से कभी हथ नहीं मिलाएगा यह सस्दार : राहुल गांधी के व्यवहार को लेकर केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने बाद में मीडिया से कहा कि वह देश के गद्दार और देश के दुश्मन हैं। यह सस्दार गांधी परिवार के क्लाज से कभी हाथ नहीं मिलाएगा, जो सिखों का हथियार है। वहीं मामले से अफ़कोशित भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के अकबर रोड स्थित कार्यालय पर प्रदर्शन और नारेबाजी कर दी।

गद्दार दोस्त। चिंता मत करो, तुम बापस (कांग्रेस में) आ जाओगे।' इसके बाद तो बिट्टू ने हाथ मिलाने से मना करते हुए राहुल गांधी की ओर इशारा कर उठे 'देश का दुश्मन' कहा। इस तीखे बार्तालाप के बाद बिट्टू संसद के भीतर चले गए। इस बीच, नए संसद भवन के प्रवेश द्वार पर राहुल गांधी की ओर से बिट्टू पर की गई टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी तीखे प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस नेता ने शिष्टाचार की सभी सीमाएं पर कर दी हैं।

बिट्टू वाले- गांधी पंखार के वंशज से कभी हथ नहीं मिलाएगा यह सस्दार : राहुल गांधी के व्यवहार को लेकर केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने बाद में मीडिया से कहा कि वह देश के गद्दार और देश के दुश्मन हैं। यह सस्दार गांधी परिवार के क्लाज से कभी हाथ

नहीं मिलाएगा, जो सिखों का हथियार है। वहीं मामले से अफ़कोशित भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के अकबर रोड स्थित कार्यालय पर प्रदर्शन और नारेबाजी कर दी।

सुप्रीम कोर्ट में दलील के दौरान ममता ने चुनाव आयोग को कहा वाट्सएप आयोग 29 वर्ष पहले हुगली कोर्ट में वकील के लिबास में पहुंचीं थीं ममता बनर्जी

जागरण व्यूरो, नई दिल्ली : बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिली दौरें और एसआइआर के विरोध को भाजपा ने बड़ा "राजनीतिक पाखंड" करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी का खुद बंगाल का पक्ष रखने और एसआइआर की आड़ में लोकतंत्र को खत्म किए जाने के आरोपों पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया है। भाजपा मुख्यालय में आयोजित संबद्धता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य शमिक भट्टराचार्य एवं केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री सुकुंतल मजूमदार ने तृणमूल कांग्रेस पर बेरर लिटरे के शुद्धिकरण से घबराने का आरोप लगाया।

शमिक भट्टराचार्य ने कहा कि ममता चाहे जो भी कर लें, बंगाल में एसआइआर की प्रक्रिया होकर रहेगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि ममता बनर्जी के पास कोलकाते के भीषण अग्निकांड के पीछित से मिलने का समय नहीं है। लेकिन, घुसपैठियों के हितों की रक्षा के लिए दिल्ली में झूठा करने का समय है।

सिरीओआ : हम आपको पांच मिनट नहीं, 15 मिनट का समय देगे। **ममता** : एसआइआर प्रक्रिया सिर्फ नाम हटाने के लिए है। नाम शामिल करने के लिए नहीं। विवाहित महिलाओं को सुसुराल में रहने और पति के उपनाम का प्रयोग करने पर नोटिस भेजा जा रहा है। चुनाव आयोग तार्किक विमर्शियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहा। बंगाल के लोग इस बात से क्रुश हैं कि कोर्ट ने आधार कार्ड को प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता दी है, लेकिन आयोग उसे नहीं मान रहा। अन्य दस्तावेज मांगे जाते हैं। कई जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। इतनी जल्दी क्या थी? जो काम दो साल में होता, उसे तीन महीने में किया जा रहा है। उत्पीड़न की वजह से बीएलओ

के अनुसार, ममता ने कहा-मैं एक बंधुआ मजदूर हूं, मधेय हैं। मैं एक साधारण परिवार से हूं। वे बंगाल को निशाना बनाकर वहां के लोगों को कुचलना चाहते हैं। सीएम ने चुनाव

आयोग को वाट्सएप आयोग कहकर संबोधित किया, जो कथित तौर पर चुनाव आयोग द्वारा अधिकारियों को वाट्सएप के माध्यम से दिए जा रहे निर्देशों की ओर इशारा था।

राज्य व्यूरो, जागरण • **कोलकाता**: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता के रूप में अपना पक्ष रखते हुए देखा गया। सफेद साड़ी और काली शाल लपेटें ममता ने जब अपनी दलीलें पेश कीं, तो बंगाल के लोगों को 29 साल पुरानी वह घटना याद आ गई जब उन्होंने वास्तव में कमील का गाउन पहनकर अदालत में जिरह की थी।

यह घटना जुलाई 1997 की है। हुगली के गुप्तीपाड़ा में रथयात्रा के दौरान पुलिस फायरिंग में एक व्यक्ति हलधर मंडल की मौत हो गई थी। तत्कालीन विपक्षी व कांग्रेस नेता ममता बनर्जी मुक्त के परिवार को न्याय दिलाने के लिए खुद मैदान में उतरी थीं। जब पुलिस प्रशासन शव को गुप्तचुप अंतिम संस्कार करने की तैयारी में था, तब ममता ने हुगली जिला अदालत में कमील के रूप में



सुप्रीम कोर्ट परिसर से बुधवार को बाहर निकलती सीएम ममता बनर्जी • प्रे़

खड़े होकर पुलिस कार्रवाई को चुनौती दी थी। जोगेश चंद्र ला कालेज से कानून की डिग्री प्राप्त ममता अक्सर कहती हैं कि वह आज भी प्रैक्टिस कर सकती हैं। 1997 में वह एक परिवार की लड़ई लड़ रही थीं और आज 202६ में वह एसआइआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हुई हैं। हुगली के स्थानीय लोगों के लिए वह दुख आज भी जीवंत है जब सुश्री बनर्जी ने न्याय के लिए काला गाउन पहन था।

कर्नाटक विधानसभा में 'बीबी-जी राम जी' के खिलाफ प्रस्ताव पारित

बेंगलुरु, प्रे़ : कर्नाटक विधानसभा ने बुधवार को केंद्र से 'बीबी-जी राम जी' को तुरंत निरस्त करने और मनरेगा को पुनर्संघिपित करने का प्रस्ताव पारित किया, जबकि विपक्षी भाजपा और उसके सहयोगी जद (एस) ने सदन से वाकआउट किया। यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री सिद्धरमैया द्वारा मंगलवार को प्रस्तुत किया गया था, जिसे बुधवार की सदन ने स्वीकार कर लिया।

प्रस्ताव में कहा गया है कि 'बीबी-जी राम जी' अधिनियम, जिसे केंद्र द्वारा "एक्तरफ" रूप से लागू किया गया है, "संवेद्यता के मूल सिद्धांतों और ग्रामीण लोगों के आजीविका के अधिकार के लिए हानिकारक" है। विश्व के नेता आर.अशोक ने कहा कि भाजपा सत्तारूढ़ कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध करती है। जअशोक ने प्रस्ताव की प्रति पढ़ दी और इसे विधानसभा में फेंक दिया। भाजपा ने कर्नाटक विधानसभा के अंदर एक रात का आंदोलन किया, जो बुधवार को जारी है।

चिंतन

बच्चों की मोबाइल गतिविधियों पर अभिभावक रखें पैनी नज़र

आज के डिजिटल युग ने बच्चों की दुनिया को जितना आसान बना दिया है, उतना ही जटिल भी कर दिया है। मोबाइल फोन, टैबलेट और इंटरनेट आज बच्चों की पढ़ाई, मनोरंजन और संवाद का अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन यही तकनीक जब नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तो बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए गंभीर खतरा बन जाती है। ऐसे में माता-पिता की भूमिका केवल मोबाइल दिलाने तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि बच्चों की डिजिटल गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखना उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। आजकल साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम बच्चों में चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी, नॉंद की समस्या और सामाजिक अलगाव को जन्म दे रहा है। लंबे समय तक मोबाइल पर गेम खेलने या सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले बच्चे परिवार और दोस्तों से कटने लगते हैं। वे वास्तविक दुनिया की गतिविधियों से दूरी बना लेते हैं, जिससे उनका भावनात्मक और सामाजिक विकास प्रभावित होता है। यहीं वजह है कि विशेषज्ञ लगातार सलाह दे रहे हैं कि बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम की स्पष्ट और सख्त सीमा तय की जाए। हाल ही में गाँजियाबाद में तीन सगी बहनों की आत्महत्या की घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया। 12, 14 और 16 साल की इन बचियों को कोरियाई लवर गेम की लत थी। बताया गया कि वे स्कूल तक छोड़ चुकी थीं और हर गतिविधि एक साथ करती थीं। सुसाइड नोट में लिखा गया “संरी मम्मी-पापा, गेम नहीं छोड़ पाएंगे।” यह घटना एक कड़वी सच्चाई को उजागर करती है कि डिजिटल लत किस हद तक बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले सकती है। ऐसे में माता-पिता के लिए सबसे पहला कदम है समय सीमा निर्धारित करना। बच्चों के मोबाइल उपयोग के लिए प्रतिदिन का समय फिक्स होना चाहिए। इसके साथ-साथ गूगल फैमिली लिंक जैसे पेरेंटल कंट्रोल ऐप्स का इस्तेमाल कर स्क्रीन टाइम को सीमित किया जा सकता है और यह जाना जा सकता है कि बच्चे मोबाइल पर क्या देख रहे हैं। निगरानी के साथ-साथ संवाद भी उतना ही जरूरी है। बच्चों को केवल डांटना या मोबाइल छीन लेना समाधान नहीं है। खुलकर बातचीत करने से बच्चे अपनी समस्याएं साझा करते हैं और गलत डिजिटल कंटेंट से दूर रहने के लिए खुद को तैयार करते हैं। बच्चों को मोबाइल से दूर रखने का सबसे कारगर तरीका है उन्हें बेहतर विकल्प देना। आउटडोर खेल, किताबें, संगीत, चित्रकला और अन्य रचनात्मक गतिविधियाँ बच्चों के लिए न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि उनके व्यक्तित्व विकास में भी सहायक हैं। जब बच्चों को सकारात्मक और रोचक विकल्प मिलते हैं, तो वे खुद-ब-खुद मोबाइल से दूरी बनाने लगते हैं। आज सबसे बड़ा खतरा मोबाइल पर खेले जाने वाले कुछ ऑनलाइन गेम्स से जुड़ा है। ब्लू चैलेंज चैलेंज, मोमो चैलेंज, कोरियाई लवर गेम, पवजी और ब्लैकआउट चैलेंज जैसे टास्क-बेस्ड गेम्स बच्चों को मानसिक रूप से इतना प्रभावित कर देते हैं कि वे जानलेवा कदम उठाने तक के लिए प्रेरित हो जाते हैं। मोमो चैलेंज डर और धमकी के जरिए बच्चों को जानलेवा काम करने को मजबूर करता है। चोकिंग गेम और ब्लैकआउट चैलेंज जैसी चुनौतियां भी सोशल मीडिया के जरिए फैल रही हैं। अगर समय रहते हम सतर्क हो गए, तो कई मासूम जिंदगियों को बचाया जा सकता है।

विचार राजीव श्रीवास्तव



चित्रोत्पला फिल्म सिटी : सपना बड़ा है, शुरुआत संवेदनशील होनी चाहिए



छत्तीसगढ़ में चित्रोत्पला फिल्म सिटी का निर्माण राज्य के सांस्कृतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह परियोजना न केवल फिल्म निर्माण से जुड़ी है, बल्कि इससे छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और रचनात्मक पहचान को राष्ट्रीय मंच मिलने की संभावना भी जुड़ी हुई है। ऐसे में इस परियोजना की हर शुरुआत, हर प्रतीक और हर निर्णय का सांस्कृतिक अर्थ भी होता है। भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान सामने आया विवाद इसी संवेदनशीलता की ओर संकेत करता है, जिसे केवल औपचारिक प्रतिक्रिया देकर टालना उचित नहीं होगा।

जब अपनी ही जमीन पर कलाकार हाशिये पर हों

यदि छत्तीसगढ़ के नाम पर बन रही फिल्म सिटी के पहले सार्वजनिक आयोजन में स्थानीय कलाकार, रंगकर्मी और छत्तीसगढ़ी सिनेमा से जुड़े लोग स्वयं को उपेक्षित महसूस करें, तो यह केवल एक आयोजन की त्रुटि नहीं, बल्कि सोच में आई दूरी का संकेत है। बॉलीवुड कलाकारों के कट-आउट और प्रतीकों के बीच छत्तीसगढ़ की अपनी सांस्कृतिक उपस्थिति का कमजोर दिखना यह प्रश्न खड़ा करता है कि— क्या हम विकास की दौड़ में अपनी जड़ों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं?

संस्कृति आयोजन नहीं, सहभागिता मांगती है

अपने प्रशासनिक अनुभव के आधार पर मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि संस्कृति विभाग का कार्य केवल कार्यक्रम आयोजित करना नहीं होता, बल्कि कलाकारों के आत्मसम्मान और भागीदारी को सुनिश्चित करना होता है। कलाकार मंच नहीं मांगते, वे यह महसूस करना चाहते हैं कि— वे इस परियोजना का हिस्सा हैं,

केवल दर्शक नहीं। यदि चित्रोत्पला फिल्म सिटी वास्तव में छत्तीसगढ़ की है, तो उसकी पहली तस्वीर में छत्तीसगढ़ी कलाकारों की केंद्रीय भूमिका स्वाभाविक होनी चाहिए थी।

सरकार की मंशा और ज़मीनी अपेक्षाएं

सरकार और आयोजन से जुड़े पक्षों ने यह कहा है कि सभी को साथ लेकर चलने की मंशा है और किसी को जानबूझकर नजरअंदाज नहीं किया गया। इस आश्वासन का स्वागत किया जाना चाहिए।

लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि आने वाले समय में—स्थानीय कलाकारों की निर्णायक भागीदारी

छत्तीसगढ़ी फिल्मों और रंगमंच के लिए ठोस नीति प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और मंच के स्थायी प्रावधान

स्पष्ट रूप से दिखाई दें। क्योंकि सांस्कृतिक विश्वास शब्दों से नहीं, कार्यवाही से बनता है।

चित्रोत्पला : नाम के साथ जिम्मेदारी

चित्रोत्पला केवल एक आधुनिक फिल्म सिटी का नाम नहीं है। यह छत्तीसगढ़ की उस सांस्कृतिक स्मृति का प्रतीक है, जहाँ लोककला, शिल्प और रचनात्मकता पीढ़ियों से जीवित रही है। इस नाम के साथ यह जिम्मेदारी भी जुड़ी है कि फिल्म सिटी की आत्मा स्थानीय हो और दृष्टि वैश्विक।

अंततोगत्वा मैं यह कहना चाहता हूँ कि....

चित्रोत्पला फिल्म सिटी छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। लेकिन यदि इसकी नींव में संवेदनशीलता और संवाद की कमी रही, तो भव्य संरचनाएं भी सांस्कृतिक रूप से अधूरी रह जाएंगी। आलोचना को विरोध नहीं, समय रहते मिला संकेत समझना चाहिए। क्योंकि संस्कृति में संकेतों की अनदेखी, सबसे महंगी भूल होती है।

(पूर्व आयुक्त, संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन)



भारत-अमेरिका डील महेन्द्र तिवारी

भारत और अमेरिका के बीच हाल में हुए व्यापारिक समझौते ने केवल दो देशों की नीतियों को ही नहीं बदला, बल्कि वैश्विक राजनीति के समीकरणों को भी नई दिशा दी है। जिस अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान आयात शुल्क के हथियार बनाकर पूरी दुनिया को चेतावनी दी थी, वही ट्रंप अचानक भारत के मामले में नरम पड़ते दिखाई दिए। जिन शुल्कों को उन्होंने पहले पचास प्रतिशत तक पहुंचा दिया था, उन्हें घटाकर अठारह प्रतिशत पर लाना कोई सामान्य फैसला नहीं था। यह बदलाव न तो अचानक हुआ और न ही एकतरफ़ा दबाव का परिणाम था। इसके पीछे भारत की एक सधी हुई, दूरदर्शी और संतुलित कूटनीति काम कर रही थी, जिसने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को भी बातचीत की मेज पर सम्मान के साथ बैठने को मजबूर कर दिया। ट्रंप की राजनीति हमेशा आक्रामक रही है। उनका मानना रहा कि आर्थिक दबाव के जरिए ही किसी देश को झुकाया जा सकता है। सत्ता में आते ही उन्होंने चीन के साथ व्यापार युद्ध छेड़ दिया और उसी क्रम में भारत को भी निशाने पर लिया। भारत पर यह आरोप लगाया गया कि वह विदेशी वस्तुओं पर बहुत अधिक कर लगाता है और अमेरिकी कंपनियों को उचित अवसर नहीं देता। इसी सोच के तहत भारत को विशेष व्यापारिक सुविधा की सूची से बाहर कर दिया गया, जिससे भारतीय निर्यातकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस फैसले से दवाइयों, कपड़ों, रत्नों और कृषि उत्पादों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा और भारत के लिए अमेरिकी बाजार कठिन हो गया। भारत ने इस दबाव को चुपचाप स्वीकार नहीं किया। उसने जवाबी कदम उठाए और अमेरिका से आने वाले कई उत्पादों पर कर बढ़ा दिए। इससे अमेरिका के किसान और उद्योगपति प्रभावित हुए। बादाम, सेब और अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात पर असर पड़ा। यह संकेत साफ था कि भारत केवल सुनने वाला देश नहीं है, बल्कि आपने हितों की रक्षा करना जानता है। इसके बावजूद भारत ने टकराव को भाषा नहीं अपनाई। उसने संवाद के दरवाजे खुले रखे और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का मूल आधार संतुलन रहा है। न तो किसी के आगे झुकना और न ही अनावश्यक टकरावा। इसी नीति के तहत भारत ने अमेरिका के साथ रणनीतिक सहयोग बढ़ाया। सुरक्षा, रक्षा उत्पादन, तकनीक और निवेश के क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत किया गया। भारत ने यह संदेश स्पष्ट रूप से दिया कि वह केवल एक बाजार नहीं, बल्कि भरोसेमंद साझेदार है। अमेरिका की बड़ी कंपनियों को भारत में निवेश के अवसर दिए गए, उत्पादन को बढ़ावा देने वाली

ईश्वर की प्राप्ति ही तो जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है

गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने ईश्वर प्राप्ति के तीन -ज्ञान, कर्म तथा भक्ति मार्ग बताए हैं। ज्ञान मार्ग में सांख्य की सहायता से मनुष्य तर्क-वितर्क द्वारा तत्त्व ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है, परंतु अक्सर तर्क-वितर्क में वह अपने मार्ग से भटक जाता है। कर्म मार्ग में भी मनुष्य को निष्काम भाव से कर्म करना होता है। अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करना पड़ता है। इसलिए इसमें भी भटकने की पूरी संभावना होती है। वहीं भक्ति मार्ग में वह अपने आप को पूर्णतया ईश्वर भक्ति में समर्पित कर देता है। वह स्वयं को विचलित नहीं करता है। इसलिए भक्ति मार्ग में ईश्वर प्राप्ति की पूरी संभावना होती है। इन तीनों मार्गों पर चलकर सफल होने के लिए मनुष्य को अष्टांग योग के पहले दो चरणों को जीवन में अपनाना जरूरी है। यह हैं यम और नियम। यम में सत्य, अहिंसा, ब्रह्माचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह आते हैं। सत्य शब्द से तात्पर्य है सत्यता का जीवन में हर समय पालन करना। अहिंसा केवल जीव हिंसा से ही संबंधित नहीं है, इसमें दूसरों की भावनाओं को आहत नहीं करना भी आता है। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना और अपरिग्रह से तात्पर्य है कि आवश्यकता से ज्यादा किसी वस्तु या धन का संग्रह न करना। वहीं नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्राणिधान आते हैं। शौच से मतलब मन की सफाई होता है। इसके लिए मनुष्य को स्वाध्याय को अपनाना चाहिए। यम और नियम को जीवन में अपनाने के लिए सर्वप्रथम ज्ञानेन्द्रियों पर नियंत्रण करना जरूरी है।



मेरीगांव के पोबितोरा वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी में बुधवार को टूरिस्ट हाथी की सवारी करते हुए।

करंट अफेयर

जिल बाइडन के पूर्व पति पर पत्नी की हत्या का आरोप

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन की पत्नी जिल बाइडन के पूर्व पति पर दिसंबर के अंत में डेलवियर स्थित घर में अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप लगाया गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। विलमिंगटन निवासी विलियम स्टीवेन्सन (77) का जिल बाइडन से वैवाहिक रिश्ता 1970 से 1975 तक चला था। डेलवियर के अर्टोर्नी जनरल की प्रवक्ता कैरोलिन हैरिसन ने फोन पर बातचीत में पुष्टि की कि स्टीवेन्सन, जिल बाइडन के पूर्व पति हैं। पूर्व राष्ट्रपति और भूतपूर्व प्रथम महिला के कार्यालय के प्रवक्ता द्वारा ईमेल के माध्यम से दिए गए जवाब के अनुसार, जिल बाइडन ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हत्या के आरोप में सोमवार को गिरफ्तार किए जाने के बाद पांच लाख अमेरिकी डॉलर की जमानत राशि जमा करने में विफल रहने के कारण स्टीवेन्सन जेल में ही है। उन पर 28 दिसंबर को 64 वर्षीय लिंडा स्टीवेन्सन की हत्या का आरोप है। विज्ञप्ति के अनुसार, रात 11 बजे के बाद घरेलू विवाद की सूचना पर पुलिस को घर बुलाया गया और उन्होंने बैटक कक्ष में एक महिला को बेहोश पाया। लिंडा स्टीवेन्सन के शोक संदेश के मुताबिक, वह व्यवसाय करती थी और उन्हें परिवार-उन्मुख मां और दादी बताया गया है।



का कोई बचा हुआ टुकड़ा जमीन से टकराता है, तो उसे उल्कापिंड कहा जाता है। अधिकांश वस्तु वायुमंडल में जल जाती है। प्रति वर्ष एक बार, औसतन, चार मीटर का क्षुद्रग्रह पृथ्वी की सतह से टकराता है। यदि आपने उस सतह क्षेत्र को दोगुना कर दिया, तो आपको प्रति वर्ष दो मिलेंगे। पृथ्वी की त्रिज्या 6,400 किमी है। दोगुने सतह क्षेत्रफल वाले एक गोले की त्रिज्या 9,000 किमी है। तो, प्रति वर्ष लगभग एक बार, चार मीटर का क्षुद्रग्रह पृथ्वी की सतह के 2,600 किमी के भीतर आएगा – 9,000 किमी और 6,400 किमी के बीच का अंतर।

विचार हरिभूमि 8

वैश्विक राजनीति को मिली नई दिशा

भारत और अमेरिका के बीच हाल में हुए व्यापारिक समझौते ने केवल दो देशों की नीतियों को ही नहीं बदला, बल्कि वैश्विक राजनीति के समीकरणों को भी नई दिशा दी है। जिस अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान आयात शुल्क के हथियार बनाकर पूरी दुनिया को चेतावनी दी थी, वही ट्रंप अचानक भारत के मामले में नरम पड़ते दिखाई दिए। जिन शुल्कों को उन्होंने पहले पचास प्रतिशत तक पहुंचा दिया था, उन्हें घटाकर अठारह प्रतिशत पर लाना कोई सामान्य फैसला नहीं था। यह बदलाव न तो अचानक हुआ और न ही एकतरफ़ा दबाव का परिणाम था। इसके पीछे भारत की एक सधी हुई, दूरदर्शी और संतुलित कूटनीति काम कर रही थी, जिसने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को भी बातचीत की मेज पर सम्मान के साथ बैठने को मजबूर कर दिया। ट्रंप की राजनीति हमेशा आक्रामक रही है। उनका मानना रहा कि आर्थिक दबाव के जरिए ही किसी देश को झुकाया जा सकता है। सत्ता में आते ही उन्होंने चीन के साथ व्यापार युद्ध छेड़ दिया और उसी क्रम में भारत को भी निशाने पर लिया। भारत पर यह आरोप लगाया गया कि वह विदेशी वस्तुओं पर बहुत अधिक कर लगाता है और अमेरिकी कंपनियों को उचित अवसर नहीं देता। इसी सोच के तहत भारत को विशेष व्यापारिक सुविधा की सूची से बाहर कर दिया गया, जिससे भारतीय निर्यातकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस फैसले से दवाइयों, कपड़ों, रत्नों और कृषि उत्पादों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा और भारत के लिए अमेरिकी बाजार कठिन हो गया। भारत ने इस दबाव को चुपचाप स्वीकार नहीं किया। उसने जवाबी कदम उठाए और अमेरिका से आने वाले कई उत्पादों पर कर बढ़ा दिए। इससे अमेरिका के किसान और उद्योगपति प्रभावित हुए। बादाम, सेब और अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात पर असर पड़ा। यह संकेत साफ था कि भारत केवल सुनने वाला देश नहीं है, बल्कि आपने हितों की रक्षा करना जानता है। इसके बावजूद भारत ने टकराव को भाषा नहीं अपनाई। उसने संवाद के दरवाजे खुले रखे और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का मूल आधार संतुलन रहा है। न तो किसी के आगे झुकना और न ही अनावश्यक टकरावा। इसी नीति के तहत भारत ने अमेरिका के साथ रणनीतिक सहयोग बढ़ाया। सुरक्षा, रक्षा उत्पादन, तकनीक और निवेश के क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत किया गया। भारत ने यह संदेश स्पष्ट रूप से दिया कि वह केवल एक बाजार नहीं, बल्कि भरोसेमंद साझेदार है। अमेरिका की बड़ी कंपनियों को भारत में निवेश के अवसर दिए गए, उत्पादन को बढ़ावा देने वाली



समझौते के तहत भारत और अमेरिका दोनों ने एक दूसरे को राहत दी। भारत ने कुछ कृषि उत्पादों पर शुल्क कम करने का संकेत दिया, जबकि अमेरिका ने भारतीय इस्पात, कपड़ा और दवा उद्योग को बड़ी राहत दी। इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और लाखों लोगों के रोजगार सुरक्षित होंगे। दवा उद्योग के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय दवाइयों सस्ती और प्रभावी मानी जाती हैं और अमेरिका में उनकी मांग लगातार बढ़ रही है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा सवाल यह भी उठा कि क्या अमेरिका से बढ़ती नजदीकी का असर भारत के रूस के साथ संबंधों पर पड़ेगा। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से सस्ता तेल खरीदने के कारण भारत पश्चिमी देशों की आलोचना के केंद्र में रहा है। भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए, रूस से तेल खरीद जारी रखी, जिससे उसे अरबों रुपये की बचत हुई और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई। अमेरिका ने इस पर असंतोष जर्ूर जताया, लेकिन कोई ठोस प्रतिबंध नहीं लगाया। रूस की ओर से भी यह स्पष्ट किया गया कि भारत के साथ उसके संबंधों में कोई बदलाव नहीं आया है। रूसी नेतृत्व ने

कहा कि भारत एक भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार है और दोनों देशों का सहयोग आगे भी जारी रहेगा। रक्षा क्षेत्र में चल रही परियोजनाएं, मिसाइल प्रणालियों की आपूर्ति और सैन्य सहयोग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह प्रतिक्रिया इस बात का प्रमाण है कि भारत ने अपनी कूटनीति में संतुलन बनाए रखा है और किसी एक खेमे में खुद को सीमित नहीं किया है। आजादी के बाद से ही भारत ने गुटनिरपेक्षता और रणनीतिक स्वायत्तता का रास्ता चुना है। भारत अपने फैसले स्वयं करता है, दबाव में नहीं। अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौता भी इसी सोच का परिणाम है। इसमें न तो आत्मसमर्पण है और न ही टकराव, बल्कि आपसी लाभ का रास्ता है।

इस समझौते का असर केवल भारत और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी इसके सकारात्मक संकेत दिखाई देंगे। जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सहयोग का रास्ता चुनती हैं, तो बाजारों में स्थिरता आती है। निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और विकास को गति मिलती है। भारत के लिए यह अवसर है कि वह खुद को विश्व उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित करे और वैश्विक आपूर्ति शृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करे। हालांकि चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। डिजिटल कर, बौद्धिक संपदा अधिकार और आंकड़ों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। भारत को सावधानी से आगे बढ़ना होगा ताकि घरेलू हितों की अनदेखी न हो। विदेशी कंपनियों को अवसर देते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि देश के कानूनों और संप्रभुता से कोई समझौता न हो। राजनीतिक दृष्टि से भी यह समझौता महत्वपूर्ण है। इससे यह संदेश जाता है कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं, बल्कि वैश्विक नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की यह एक बड़ी परीक्षा थी, जिसमें वे सफल दिखाई देते हैं। ट्रंप का नरम रुख इस बात का संकेत है कि भारत की बात अब सुनी जाती है। आने वाले वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग और गहरा हो सकता है। उभरती तकनीकों, रक्षा उत्पादन और निवेश के क्षेत्रों में नए रास्ते खुलेंगे। साथ ही रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा सहयोग भी जारी रहेगा। भारत दोनों शक्तियों के साथ अपने हितों के अनुसार संबंध बनाए रखेगा। अंततः यह कहानी बदलती दुनिया में समझदारी भरी कूटनीति की है। यह दिखाती है कि शोर मचाने से नहीं, बल्कि संवाद और संतुलन से बड़े फैसले लिए जाते हैं। भारत ने यही रास्ता चुना है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है।

(लेखक रवींद्र सनकर हैं वे उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर आपकी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

आखिर कर्म ही महान है

एक बार बुद्ध एक गांव में अपने किसान भक्त के यहां गए। शाम को किसान ने उनके प्रवचन का आयोजन किया। बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए गांव के सभी लोग उपस्थित थे, लेकिन वह भक्त ही कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के लोगों में कानाफूसी होने लगी कि कैसा भक्त है कि प्रवचन का आयोजन करके स्वयं गायब हो गया। प्रवचन खत्म होने के बाद सब लोग घर चले गए। रात में किसान घर लौटा। बुद्ध ने पूछा: कहां चले गए थे? गांव के सभी लोग तुम्हें पृछ रहे थे। किसान ने कहा, दरअसल प्रवचन की सारी व्यवस्था हो गई थी, पर तभी अचानक मेरा बेल बीमार हो गया। पहले तो मैंने घरेलू उपचार करके उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो मुझे उसे लेकर पशु चिकित्सक के पास जाना पड़ा। अगर नहीं ले जाता तो वह नहीं बचता। आपका प्रवचन तो मैं बाद में भी सुन लूंगा। अगले दिन सुबह जब गांव वाले पुनः बुद्ध के पास आए तो उन्होंने किसान की शिकायत करते हुए कहा, यह तो आपका भक्त होने का दिखावा करता है। प्रवचन का आयोजन कर स्वयं ही गायब हो जाता है। बुद्ध ने उन्हें पूरी घटना सुनाई और फिर समझाया, उसने प्रवचन सुनने की जगह कर्म को महत्व देकर यह दिखा कर दिया कि मेरी शिक्षा को उसने बिल्कुल ठीक ढंग से समझा है। उसे अब मेरे प्रवचन की आवश्यकता नहीं है। मैं यही तो समझाता हूं कि अपने विवेक और बुद्धि से सोचो कि कौन सा काम पहले किया जाना जरूरी है।



खबर संक्षेप

टाटा पावर का लाभ मामूली बढ़कर 1,194 करोड़ रुपये



नई दिल्ली। टाटा पावर का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ मामूली रूप से बढ़कर 1,194 करोड़ रुपये हो गया। राजस्व में कमी के बावजूद कंपनी के मुनाफे में यह बढ़त दर्ज की गई है। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में कंपनी को 1,188 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध लाभ हुआ था।

बजाज फिनसर्व का शुद्ध लाभ 2,229 करोड़ रुपये पर स्थिर

नई दिल्ली। बजाज फिनसर्व का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ लगभग स्थिर रहा और यह 2,229 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी को 2,231 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। कंपनी ने बुधवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही के वित्तीय नतीजों की जानकारी दी। आलोच्य तिमाही में बजाज फिनसर्व की कुल आय बढ़कर 39,708 करोड़ रुपये हो गई।

दो माह बाद दिए गए जांच के आदेश

सीसीआई ने दिए इंडिगो के खिलाफ जांच के आदेश

नई दिल्ली । भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने परिवालन अडचनों के कारण दिसंबर में हजारों उड़ानें रद्द किए जाने के मामले में बुधवार को देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के खिलाफ विस्तृत जांच का आदेश दिया। घटना के करीब दो महीने बाद जारी इस आदेश में सीसीआई ने कहा कि बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द कर इंडिगो ने अपनी निर्धारित क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बाजार से हटा लिया, जिससे कुत्रिम अभाव की स्थिति पैदा हुई और व्यस्त मांग के दौरान यात्रियों की हवाई यात्रा तक पहुंच सीमित हुई। आयोग ने कहा, "किसी प्रमुखवाली कंपनी की तरफ से ऐसे आचरण को प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा चार (2)(बी)(आई) के तहत सेवाओं की आपूर्ति सीमित करने के रूप में देखा जा सकता है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा चार बाजार में दबावबे की स्थिति के दुरुपयोग से संबंधित है।" ने कहा कि प्रथम दृष्टया इंडिगो का यह आचरण भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता प्रतीत होता है। इसके मद्देनजर आयोग ने मामले की विस्तृत जांच के लिए अपने महानिदेशक को निर्देश दिए हैं।

सूचना

सभी पाठकों से अनुरोध है कि हरिभूमि समाचार-पत्र में प्रकाशित विज्ञापनों (हस्पले/क्लासीफाईड) में दिए गए तथ्यों/दावों के बारे में अपने विवेक से निर्णय लें और विज्ञापन के दावों की विश्वसनीयता को परखें। हरिभूमि समूह के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की विज्ञापनों के तथ्यों से सम्बन्धित कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

राशिफल

- शैक्षिक कार्यों के लिए किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। रहन-सहन अव्यवस्थित रहेगा। आय वृद्धि के साधन विकसित होंगे।
- व्यर्थ के क्रोध से बचें। किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
- अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धर्म के प्रति श्रद्धाभाव रहेगा। व्यर्थ की भाग-दौड़ रहेगी। सन्तान की ओर से सुखद समाचार मिल सकते हैं।
- आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। परिवार का साथ मिलेगा। वस्त्रों के प्रति रुझान बढ़ सकता है। खानपान के प्रति सचेत रहें। मन में निराशा एवं असंतोष के भाव रहेंगे।
- शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। लेखनादि-बौद्धिक कार्यों से आय के साधन बन सकते हैं। रहन-सहन कष्टमय हो सकता है।
- क्रोध एवं आदेश के अतिरेक से बचें। मन में निराशा एवं असंतोष के भाव रहेंगे। स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है। व्यर्थ के विवादों से बचने का प्रयास करें।
- पठन-पाठन में रुचि रहेगी। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा।
- घर-परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। परिश्रम अधिक रहेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। वस्त्रों पर खर्च बढ़ेगा। रहन-सहन कष्टमय हो सकता है।
- पिता का साथ रहेगा। सेहत का ध्यान रखें। शैक्षिक कार्यों में व्यवधान आएंगे। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे।
- परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। परिश्रम अधिक रहेगा। स्थान परिवर्तन सम्भव है। लंबे समय से रुके हुए काम बनने की उम्मीद है।
- परिवार की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। वाहन के रख-रखाव एवं वस्त्रों पर खर्च बढ़ सकते हैं। शिक्षा में सुधार होगा। आत्मविश्वास में कमी आएगी।
- वस्त्र उधार में मिल सकते हैं। मित्र के सहयोग से आय वृद्धि के स्रोत विकसित हो सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। परिवार में अशांति रहेगी।

वित्त मंत्रालय ने कहा, बजट में की गई घोषणा, विदेशी कंपनियों को निश्चितता प्रदान करेगी

भारत में डेटा सेंटर स्थापित करने वाली विदेशी कंपनियों पर कोई कर जोखिम नहीं

एजेसी ►► नई दिल्ली

वैश्विक स्तर पर क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाली विदेशी कंपनियों को 20 साल की कर छूट देने का बजट प्रस्ताव केवल उन्हीं कंपनियों पर लागू होगा, जिन्होंने भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से अधिसूचित डेटा सेंटर स्थापित किया है। ऐसे मामलों में इन विदेशी कंपनियों की वैश्विक आय पर भारत में कर लगाए जाने का कोई जोखिम नहीं होगा।

वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि बजट की यह घोषणा उन विदेशी कंपनियों को भी निश्चितता प्रदान करेगी, जो भारत में डेटा सेंटर से क्लाउड सेवाएं और खरीद सेवाएं प्राप्त करने के कारोबार में हैं। सूत्रों ने कहा, " अब भारतीय डेटा सेंटर वैश्विक क्लाउड इकाइयों को आत्मविश्वास के साथ अपनी सेवाएं दे सकते हैं क्योंकि इन वैश्विक इकाइयों को भारतीय डेटा सेंटर का उपयोग करने पर किसी कर जोखिम की आशंका नहीं रहेगी।

क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को मिलेगा फायदा



15 प्रतिशत का सुरक्षित

मुनाफा उपलब्ध कराया गया

भारतीय डेटा सेंटर विदेशी कंपनी की संबद्ध इकाई (कॉस्ट-प्लस सेंटर) हालांकि जहां है, वहां 15 प्रतिशत का सुरक्षित मुनाफा (सेफ हार्बर) उपलब्ध कराया गया है। सूत्रों के अनुसार, विदेशी क्लाउड सेवा इकाइयों के लिए कर उपचार समान रहेगा, चाहे डेटा सेंटर भारतीय स्वामित्व का हो या वैश्विक इकाई की अनुबंधी कंपनी हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 2026-27 के बजट में घोषणा की थी कि जो भी विदेशी कंपनी भारत से डेटा सेंटर सेवाओं का उपयोग कर वैश्विक चाहकों को क्लाउड सेवाएं प्रदान करती है, उसे 2047 तक कर छूट दी जाएगी।

सेवा ली जाने वाली कंपनी भारतीय होनी चाहिए

दूसरी शर्त यह है कि भारत में जिस डेटा सेंटर कंपनी से सेवाएं ली जा रही हैं, वह एक भारतीय कंपनी हो। तीसरी शर्त यह है कि डेटा सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित हो। विदेशी कंपनी का भारतीय उपयोगकर्ताओं को सेवाएं एक भारतीय 'रैसेलर' इकाई (जो कि एक भारतीय कंपनी हो) के माध्यम से प्रदान करना चौथी शर्त है।

कंपनियों के वैश्विक

आय पर भारत में नहीं

लगेगा कर

वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा, " इस आधार पर विदेशी कंपनियों की वैश्विक आय पर भारत में कर लगाए जाने का कोई जोखिम नहीं होगा।"

प्रस्ताव को स्पष्ट करते हुए सूत्रों ने बताया कि कर छूट का लाभ उठाने के लिए विदेशी कंपनी को चार आवश्यक शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली शर्त यह है कि विदेशी कंपनी अधिसूचित हो।

350 विदेशी कंपनियों ने कराया पंजीयन

कंपनी अधिनियम के अनुसार, विदेशी कंपनियां वे होती हैं जिनका गठन भारत के बाहर हुआ हो और जिनका भारत में व्यवसाय स्थल हो। ये कंपनियां विदेशी पूंजी से स्थापित होती हैं। 2020 से 2024 के बीच विभिन्न क्षेत्रों की करीब 350 विदेशी कंपनियों ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में पंजीकरण कराया है।

आईटी शेयर में बड़ी गिरावट से बाजार की बढ़त सीमित



मुंबई । सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट के बीच घरेलू शेयर बाजार में बुधवार को मामूली बढ़त दर्ज की गई। संसेक्स 79 अंक की बढ़त पर रहा जबकि निफ्टी 48 अंक चढ़कर बढ़ हुआ। कारोबारियों ने कहा कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी और कच्चे तेल के दाम में तेजी से भी निवेशक धारणा प्रभावित हुई। हालांकि, चुनिंदा शेयरों में तेजी से सुचकांक हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। पिछले कारोबारी सत्र में जोरदार उछाल के बाद बीएसई का 30 शेयर वाला मानक सूचकांक संसेक्स 78.56 अंक बढ़कर 83,817.69 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 83,947.53 अंक के उच्चस्तर तक गया और 83,119.95 अंक के निचले स्तर तक आया। इस तरह इसमें 827.58 अंक का उतार-चढ़ाव देखा गया। निफ्टी 48.45 अंक यानी 0.19 प्रतिशत चढ़कर 25,776 अंक पर बंद हुआ। रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के शोध विभाग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजित मिश्रा ने कहा, " वैश्विक बाजार के मिले-जुले संकेतों और हालिया वैश्विक प्रौद्योगिकी शेयरों में कमजोरी का असर घरेलू आईटी शेयर पर भी पड़ा।"

दो बांड एक साथ

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के मुख्य परिवालन अधिकारी (सीओओ) राजेश मेनन ने कहा, "सन फार्मा का हमारे साथ प्रधान प्रयोजक के बतौर जुड़ना इस प्रतिबद्धता को मजबूत करता है, जो प्रभाव और नवाचार पर केंद्रित दो बांड को एक साथ लाता है।"

सिगरेट पर ऊंचे कर से बढ़ेगा अवैध कारोबार

नई दिल्ली। इस महीने की शुरुआत से लागू हुए अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के कारण सिगरेट की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से इसके अवैध व्यापार में उछाल आ सकता है और कर संग्रह पर दबाव पड़ सकता है। एक रिपोर्ट में बुधवार को यह आशंका जताई गई। सिगरेट पर नया कर शासन और उसका प्रभाव शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सुगंधित सिगरेट मूल्य श्रृंखला और अर्थव्यवस्था पर उच्च कर दरो का प्रभाव काफी गहरा होगा, जिसे बाद में बदलाव मुश्किल हो सकता है। अर्थ आर्बिट्रज कंसल्टिंग ने अपनी रिपोर्ट में कहा, सिगरेट कर दरो में मौजूदा वृद्धि से न केवल अवैध सिगरेट व्यापार और खपत को बढ़ावा मिलने की संभावना है, बल्कि इसके व्यापक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव भी होंगे। एक फरवरी से पान-मसाला पर स्वास्थ्य उपकर के साथ-साथ सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर 40 प्रतिशत की उच्चतम जीएसटी दर के ऊपर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लागू हो गया है। रविवार से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लागू होने के बाद 10 स्टिक वाले सिगरेट के एक पैक की कीमतों में न्यूनतम 22 से 25 रुपये की वृद्धि हुई है। आकड़ों के मुताबिक, बदती कीमतों से अर्थ तंबाकू उत्पादों की मांग लगभग 39 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, जिससे सिगरेट की कुल अवैध खपत 46 अरब स्टिक से अधिक हो सकती है।

भारत दो-तीन दशकों में 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा: अंबानी

नई दिल्ली । रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश डी अंबानी ने कहा कि भारत अगले 20-30 वर्षों में 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता रखता है और यह देश की युवा पीढ़ी के लिए निवेश का एक बहुत बड़ा अवसर होगा। मुंबई में आयोजित जियो-ब्लैकॉक कार्यक्रम इन्वेंस्टिंग फॉर ए न्यू एरा में ब्लैकॉक के सीईओ लैरी फ्रिक के साथ फायरसाइड चैट के दौरान अंबानी ने भारत की विकास यात्रा का स्पष्ट खाका पेश किया। जियो ब्लैकॉक इवेंट में मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत पारंपरिक रूप से बचत का देश रहा है, लेकिन अब समय है कि देश के आगे बढ़ने का फायदा निवेश करके उठाया जाए। बचत को निवेश में बदला जाए। सेविंग्स का पैसा यदि कैपिटल मार्केट्स में निवेश हो, तो इससे न केवल परिवारों की संपत्ति बढ़ेगी बल्कि देश की आर्थिक वृद्धि को भी गति मिलेगी। लैरी फ्रिक ने भी इस विचार का समर्थन करते हुए कहा कि लॉक-डॉम इवेंटों निवेश भारत जैसे तेजी से बढ़ते देश में संपत्ति सृजन का सबसे प्रभावी जरिया बन सकता है।



वंदे भारत स्लीपर ट्रेनसेट के 260 रैक बनाने की योजना: अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली। वंदे भारत स्लीपर जैसी नई रोलिंग स्टॉक के विकास की प्रक्रिया में एक समय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें सुरक्षित, विश्वसनीय और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी नवाचार, रणनीतिक योजना और उत्पादन का संयोजन शामिल है। इसमें प्रोटोटाइप का विकास, व्यापक परीक्षण और प्रयोग के बाद श्रृंखला उत्पादन शामिल है।



वंदे भारत स्लीपर ट्रेन निर्माण कार्यक्रम को बीईएमएल और इंटोवाल कोच फैक्ट्री, चेन्नई और प्रौद्योगिकी मागीदारों द्वारा प्रोटोटाइप विकास, प्रयोग और श्रृंखला उत्पादन के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से निष्पादित किया जा रहा है। इन ट्रेनसेटों की नियमित यात्री सेवा में शामिल करना मांग और परिवालन तत्परता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेनसेट के कुल 260 रैक के निर्माण की योजना बनाई गई है। यात्रियों के यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने और सुरक्षित एवं आरामदायक यात्रा के मामले में नए मानक स्थापित करने के लिए, इन ट्रेनसेटों में आधुनिक कोच लगाए गए हैं।

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई शुरू

रेपो दर को यथावत रखने की संभावना



एजेसी ►► मुंबई

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने बुधवार को द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा पर विचार-विमर्श शुरू कर दिया। यह बैठक अर्थव्यवस्था में वृद्धि पर केंद्रित आम बजट और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा की पृष्ठभूमि में हो रही है, जिससे बाजार की धारणा मजबूत हुई है। मौद्रिक नीति समिति का फैसला शुक्रवार सुबह गवर्नर मल्होत्रा द्वारा घोषित किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले फरवरी से अब तक प्रमुख नीतिगत दर रेपो में 1.25 प्रतिशत अंक की कटौती कर दी है और चूंकि फिलहाल न तो वृद्धि और न ही मुद्रास्फीति के मोर्चे पर कोई बड़ी चिंता है, इसलिए इस बार दरों में यथास्थिति बनाए रखी जा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया, "हमारा यह भी मानना है कि आरबीआई ने अब ब्याज दरों में कटौती करना बंद कर दिया है, लेकिन वह अपने तत्परता प्रावधानों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करना जारी रखेगा।

PUBLIC NOTICE

This is to inform public in general that Kotak Mahindra bank Ltd has organized an auction in below mention respect of Vehicles. VEHICLES FOR SALE

- 1) ASHOK LEYAL 5525
REG. NO. NL01AH2860-YOM- 2023
 - 2) TATA MOTORS TATAACE
REG. NO. DL1LAJ9567-YOM-2023
 - 3) ASHOK LEYAL GA1920
REG. NO. HR38AF3195-YOM-NA
 - 4) FORCE FORCE19D
REG. NO. DL1VC4909-YOM-2024
 - 5) EICHR VECV 1095. GOODS
REG. NO. HR38AA642-YOM-2019
 - 6) EICHR VECV EICPRO3019
REG.NO. HR38AB8543-YOM-2021
 - 7) TATA MOTORS LPT1212
REG. NO. HR55AM0985-YOM-2022
 - 8) TATA MOTORS LPT1109T
REG. NO. UP15GT8447-YOM-NA
 - 9) TATA MOTORS T_INTRAV20
REG.NO. DL1LAM9326-YOM- NA
 - 10) TATA MOTORS TATA3118_T
REG.NO. RJ14GJ3039-YOM-2017
 - 11) BHARATBENZ BB1617RGC
REG.NO. HR38AC0412-YOM- 2022
 - 12) ASHOK LEYAL3520CC
REG.NO. UP13CT8187-YOM- 2023
 - 13) EICHR VECV EICHER_PRO
REG.NO. HR38AD5549-YOM- 2022
- UNDER HYPOTHECATION WITH M/S KOTAK MAHINDRA BANK IS UNDER SALE IN ITS "AS IS WHERE IS CONDITION" INTERESTED PARTIES CAN GIVE THEIR QUOTATIONS WITH IN 7 DAYS AT
BRANCH ADDRESS:
KOTAK MAHINDRA BANK
3RD FLOOR, PLOT NO 7,
SECTOR 125, NOIDA-201313
OR CONTACT : RAMAN AHUJA
KOTAK MAHINDRA BANK LTD.
CONTACT NO. 8377988238
EMAIL-raman.ahuja@kotak.com

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 CrPC देखिए

मेरे सम्मक्ष परिवार दिया गया है कि अभियुक्त केवल कृष्ण कुमार पुत्र स्वो जुगल किशोर कुमार, निवासी: ई-202, रमेश नगर नई दिल्ली-110015, ने CC No. 59/2016, U/S 138 NI Act, पुलिस स्टेशन राजेंद्र नगर, केन्द्रीय जिला, नई दिल्ली, के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किया गया निष्पत्ती के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त केवल कृष्ण कुमार मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त केवल कृष्ण कुमार फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि CC No. 59/2016, U/S 138 NI Act, पुलिस स्टेशन राजेंद्र नगर, केन्द्रीय जिला, नई दिल्ली, के उक्त अभियुक्त केवल कृष्ण कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के सम्मक्ष (या मेरे सम्मक्ष) उक्त परिवार का उत्तर देने के लिए दिनांक 25.03.2026 को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार श्री अरविंद तोमर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (एनआई एक्ट)-07,
DP/1541/CD/2026 केन्द्रीय जिला, कमरा नं0-507, विस्तार खण्ड, (Court Matter) तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr.P.C. देखिए

मेरे सम्मक्ष परिवार दिया गया है कि अभियुक्त नाम युवराज शर्मा (निदेशक) मैसर्स एनएमएम प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड पुत्र: श्री राज कुमार शर्मा पता: प्लेट नंबर 102 (9201) टावर 9 एटीएस वन हैमलेट सेक्टर 4 नोएडा जीबी नगर ने Ct 360/2020 थाना: मंडावली दिल्ली, के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए निरपत्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त युवराज शर्मा मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त युवराज शर्मा फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि Ct 360/2020 थाना: मंडावली दिल्ली, के उक्त अभियुक्त युवराज शर्मा से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के सम्मक्ष (या मेरे सम्मक्ष) उक्त परिवार का उत्तर देने के लिए दिनांक 28.02.2026 को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार श्री सचिन जेएमएफसी-03, पूर्वी जिला, कमरा नंबर-16 कड़कड़दूसा कोर्ट, दिल्ली

शब्द पहेली - 6 1 2 9					
	1		2	3	4
					5
					6
7				8	
		10			9
				11	12
13				14	
			17		16
				18	
19	20	21		22	23
				24	
				25	
26	27	28			29
	30	31		32	
34	35	36			37
				39	
38					

बाएँ से दाएँ

1. पावर हाऊस -5
4. दिमागी, कल्पित -4
7. हृदय-2
8. खोदना-3
9. प्रचार वाक्य, स्लोगन-2
10. नुकीला-4
11. कलिका-2
13. प्यारा, लाडला-3
14. विशिष्ट, विशेष-2
15. खर्च, उपभोग-3
17. नौका-2
19. नाम करण-2,3
22. चमकीला-5
25. महोदय (अंग्रेजी-2)
26. निवास, जनवासा-3
28. संभ्या, सांझ-2
29. दलना, महीन करना-3
30. जस, सम्मान-2
32. कारागृह-4
34. आलाप, लय, सुर-2
36. पागल स्त्री-3

37. इंकार, मना-2
38. सराबोर, सना हुआ -4
39. वेश्या, तवायफ-5
- ऊपर से नीचे
1. चूहे का घर-2
2. नेता-3
3. सार-संभार-2,3
4. आदर्श, कसौटी-3
5. छाती-2
6. अचरज भरा कार्य-4
7. हृदय को ठेस लगाना-5
10. अनवरत वर्षा-4
12. जूँ का अंडा-2
16. ओट, घूँघट-3
17. मां के पिता-2
18. दुख, कष्ट-2
20. राष्ट्रीय पक्षी-3
21. पत्र, लैटर-2
22. गुप्तचर, दूत-2
23. कपड़ों के टुकड़े (अंग्रेजी-4)
24. रवानगी,

- प्रस्थान करना-3,2
25. समयुगीन, समवर्ती-5
26. बंद, स्ट्राइक-4
27. सुरा, शराब-2
31. वचन, प्रतिज्ञा-3
33. बंदर-3
35. नथनी, नथिया-2
37. शहद-2

शब्द पहेली- 6 1 2 8 का हल

ज	र	न	म	स	ल	क	वा	रा
ल	ि	ज्वा	हा	घा	क	र	र	वा
अ	अ	ज	ग	र	म	ल	य	
वी	मा	च	न	म	की	म	त	
सी	ल	म	श	ल	न	जा		
म	म	क	दा	की	मा	व	शि	क
क	म	च	ल	मा	या	र		
अ	र	ज	र	ऐ	च	व	त	
ह	स	द	न	जे	ये	त	म	म्य
न	न	झ	स	म	ब	टा	पू	
क	र	त	ल	व	च	र	त	पू

